दशम माला, खंड 17, अंक 11

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1992
17 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

64
12-1-94
Date

(खंड 17 में अंक 11 से 18 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम मग्ला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 11, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1992/17 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		1—251
	तारांकित प्रश्न संख्या : 201 से 220	1—27
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 2321 से 2431, 2433 से 2458 और 2460 से 2551	28—253
6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में हुई कार सेवा और उसके परिणामस्वरूप देश में हुई घटनायें		253-254

लोक सभा

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1992/17 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

इस समय श्री अनिल बसु, श्री फूलचन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गांधीधाम से नयी रेलगाड़ियां चलाना

*201. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधीधाम से नयी दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद और हावड़ा के लिये नई रेलगाड़ियां चलाने के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने तथा इन्हें लागू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावों पर विचार किया गया है । संसाधनों की तंगी और क्षमता के अभाव में गाड़ियां चलाना संभव नहीं है ।

नर्सरी शिक्षा

*202. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1992 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा "अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन" (नर्सरी शिक्षा) पर आयोजित दो दिन की गोष्ठी का क्या निष्कर्ष रहा;

(ख) छः वर्ष से कम की आयु के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं;

(ग) सभी को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए समर्थन कार्यक्रम के रूप में बाल्यावस्था से ही शिक्षा आरम्भ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गोष्ठी में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुणवत्तात्मक सुधार लाने लिए गोष्ठी में, कार्य नीतियों की सिफारिश की गई। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रम, बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण खेल-खेल में सिखाने की पद्धति तथा क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षा पर बल देते हैं। प्रारम्भिक बाल शिक्षा, विभिन्न बाल विकास कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है तथा यह छोटे बच्चों को प्राथमिक स्कूल के लिए तैयार करती है। ऐसे कार्यक्रमों में शिशु देखभाल सुविधाएं, बड़े सहोदरों को स्कूल जाने के बेहतर अवसर प्रदान करती है। राज्य सरकारों से निम्न पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है :—

(i) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्कूल पद्धति के बीच समन्वय।

(ii) प्रारम्भिक बाल शिक्षा-सामग्री को बेहतर गुणवत्ता का विकास।

(iii) प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानों का पता लगाना।

रेल टिकटों की कालाबाजारी

*203. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में दलालों द्वारा रेल कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके वास्तविक रेल यात्रियों को परेशान किये जाने और उन्हें केवल दलालों से ही टिकट खरीदने के लिए बाध्य किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केवल रेलवे काउंटरों से ही टिकटों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दलालों की गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी बार अचानक जांच और छापे मारे गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्रियों द्वारा टिकटों की खरीद के लिए काफी संख्या में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण टर्मिनलों/काउंटरों की व्यवस्था की गई है। चूंकि रेलवे के टिकट अनधिकृत स्रोतों से खरीदना गैर-कानूनी और रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दण्डनीय है, इसलिए जनता को ऐसा न करने की सूचना देते हुए प्रचार भी किया जाता है।

(घ) नवम्बर 1991 से अक्तूबर 1992 तक की अवधि के दौरान, आरक्षण कार्यालयों में 4295 जांच की गईं जिनके फलस्वरूप 2054 दलाल पकड़े गए। गाड़ियों में भी 8243 जांच की गई और हस्तान्तरित टिकटों पर यात्रा करने के 9449 मामले पकड़े गये थे।

"एड्स रोग" का निवारण और नियंत्रण

*204. **श्री मनोरंजन भक्त** :

श्री उत्तमराव देवराव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में विशेष रूप से भारत में फैले "एड्स" रोग के प्रभाव के संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई हाल की रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ख) नई दिल्ली में नम्बर, 1992 में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में 'एड्स' रोग पर आयोजित द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में भारत में 'एड्स' रोग को प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रित करने हेतु क्या निवारक उपाय किए गए हैं;

(घ) इस भयावह रोग के संबंध में विशेषतौर पर महिलाओं को शिक्षित करने हेतु क्या अभियान शुरू करने का विचार है; और

(ङ) भारत में "एड्स" के निवारण और नियंत्रण हेतु अन्य क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में एड्स के विकासात्मक निहितार्थों पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हाल की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के नीति निर्माताओं से एच० आई० वी०/एड्स के फैलने के बारे में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। इसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि एच० आई० वी० संक्रमण तथा एड्स के सूचित रोगियों के मौजूदा भ्रामक निम्नस्तर से, जोकि देर से रिपोर्टिंग, कम रिपोर्टिंग अथवा यहां तक कि पता न लगाए जा सकने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, नीति-निर्माताओं और लोगों में सन्तुष्टि की भावना पैदा होती है। इस सन्दर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानिक-गरीबी, निम्न उत्पादकता, जनसंख्या दबाव, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोगों का शहरी केन्द्रों की ओर आना, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का स्तर, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप गंदी बस्तियों में वृद्धि, पारिवारिक जीवन और निश्चित साझेदारी में बढ़ती अनिश्चितता और सामाजिक आचरण

में सामान्य गिरावट समुदाय में एच० आई० वी० संक्रमण के फैलने के लिए उत्तरदायी हैं। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की सापेक्षतया अधीनस्थ स्थिति के कारण वे एच० आई० वी० के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि परिवहन, पर्यटन, मनोरंजन, खनन और मत्स्य, कृषि क्षेत्र तथा सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित उद्योगों में उत्पादकता के कारण एच० आई० वी० संक्रमण के फैलने से इस क्षेत्र के गम्भीर रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है। रिपोर्ट में अंत में कहा गया है कि यदि एच० आई० वी० संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बहु-क्षेत्रीय निवारक कार्यनीति नहीं अपनाई गई तो गम्भीर सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा होने की सम्भावना है। यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में निवारण पर खर्च करना सर्वाधिक प्रभावकारी होगा।

द्वितीय एशिया प्रशान्त एड्स कांग्रेस की बैठक नई दिल्ली में 8 से 12 नवम्बर, 1992 तक हुई थी। इसमें सुझाव दिया गया कि एच० आई० वी० की रोकथाम के लिए यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रक्त निरापदता और रक्त उत्पादकता तथा जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों पर काफी बल दिया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों में एच० आई० वी० को फैलने से रोकने के लिए एच० आई० वी० रोकथाम कार्यक्रम तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस का सुझाव था कि एच० आई० वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के प्रति कोई भेदभाव न बरता जाए और उन्हें लांछित न किया जाए इसके लिए सभी प्रयास किए जाएं, एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों के प्रति पूरी गोपनीयता रखी जाए और उन्हें यात्रा तथा कार्य करने की आजादी दी जाए। यह सिफारिश की गई कि अनाम असम्बद्ध प्रहरी सर्वेक्षण हमारी विज्ञान सम्बन्धी निगरानी के लिए सर्वोत्तम उपाय होंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और द्वितीय एशिया प्रशान्त एड्स कांग्रेस के निष्कर्ष और सिफारिशें सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण और रोकथाम के लिए तैयार की गई समग्र कार्यनीति के अंग हैं। जहां सरकार के गरीबी निवारण तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के समग्र प्रयास विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों में अच्छी तरह प्रतिलक्षित होते हैं वहीं, एड्स नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय सम्बन्ध बनाना, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शामिल करना है। जागरूकता पैदा करने और विशिष्ट निवारक उपाय करने के कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक प्रणाली के अन्दर सभी उपलब्ध संगठनों के माध्यम से आरम्भ किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, अब देश में एच० आई० वी० संक्रमण के बहुमुखी आयामों को पहले से बेहतर ढंग से समझा जा रहा है।

चूंकि एड्स के लिए कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है, इसलिए निवारक कार्यनीति में रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता, यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ करने, बेहतर नैदानिक उपचार, कण्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, एच० आई० वी०/एड्स रोगियों के प्रति कोई भेदभाव न करने, उन्हें लांछित न करने तथा व्यक्तियों और समुदाय में एड्स के कारण और निवारात्मक पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात शामिल है। परामर्श, शिक्षा और पारस्परिक बातचीत के माध्यम से महिलाओं पर विशेष ध्यान देना इस कार्यनीति का अविभाज्य अंग है।

स्वायत्तशासी कालेज

*205. **श्री चन्द्रजीत यादव** :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत स्वायत्तशासी कालेज योजना आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस योजना के मूल उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य की तुलना में राज्यवार कितने-कितने कालेजों को स्वायत्तता प्रदान की गई; और

(ङ) योजना के मूल उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना के अनुसरण में आयोग ने जनवरी, 1987 में सभी राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को स्वायत्त शासी कालेजों की योजना से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश परिचालित किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वायत्त शासी कालेजों को अपने अध्ययन पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण निर्धारित करने, प्रवेश नियम निर्धारित करने, मूल्यांकन पद्धतियां तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित करने की स्वतन्त्रता है और वे शिक्षा की कोटि तथा विषय-वस्तु के लिए जिम्मेवार हैं। 1986 की कार्य योजना में, शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि 7वीं योजना में लगभग 500 कालेज स्वायत्त शासी कालेजों के रूप में तैयार किए जाने चाहिएं। तथापि, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 7वीं योजना के अन्त में 102 कालेज स्वायत्त शासी कालेजों के रूप में कार्य कर रहे थे :—

राज्य	स्वायत्त शासी कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	16
गुजरात	2
मध्य प्रदेश	28
उड़ीसा	5
राजस्थान	5
तमिलनाडु	44
उत्तर प्रदेश	2
	102

स्वायत्त शासी कालेज योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1990 में आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 जून, 1991 को आयोजित अपनी बैठक में आठवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि ऐसा पाया गया था कि अधिकांश स्वायत्त शासी कालेजों ने अपने प्रबंध ढांचे और शैक्षिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

हिमाचल क्षेत्र का समेकित विकास

*206. **श्री महेश कनोडिया** :

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हिमालय क्षेत्र के समेकित विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिमालय क्षेत्र के राज्यों को राज्य-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1992-93 के लिए प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) क्या हिमालय क्षेत्र में पेड़-पौधों की देखभाल हेतु राष्ट्रीय जैव-विविधता संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हिमाचल शृंखलाएं देश में उत्तर से उत्तर-पूर्व तक फैली हुई हैं। इनमें पर्वतीय राज्य (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) आते हैं जिन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 8 जिलों, उसमें के दो जिलों तथा दार्जिलिंग जिले के 3 प्रभागों को केन्द्र सरकार के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटन ग्रामीण विकास, कृषि (बागवानी सहित), जल संसाधन (भूमिगत जल सहित), उद्योगों, खनिजों, सड़कों, ऊर्जा उत्पादन आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। विकास के मामलों में इन आवंटनों का संबंध अंतः क्षेत्रीय होता है। कतिपय ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम भी हैं जिन्हें एकीकृत विकास कार्यक्रमों का नाम दिया गया है तथा जिनके लिए किए गए आवंटन अनुलग्नक में दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उल्लिखित विवरण   अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम	अरुणाचल	असम	हिमाचल	जम्मू और कश्मीर	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और संबद्ध कार्यक्रम								
	1989-90	281	878	231	158	80	125	115	115
	1990-91	308	1029	136	250	100	132	148	141
	1991-92	290	1180	260	275	108	150	151	169
	1992-93	225	1300	280	1418	113	192	151	175
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)								
	1989-90	—	—	—	107	—	—	—	—
	1990-91	—	—	—	196	—	—	—	5
	1991-92	—	—	—	196	—	—	—	6
	1992-93	—	—	—	210	—	—	—	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)								
	1989-90	18	57	85	25	10	25	15	10
	1990-91	30	65	70	35	15	40	20	15
	1991-92	35	70	80	45	22	60	25	20
	1992-93	36	65	90	47	22	60	25	20
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)								
	1989-90	44	542	252	303	150	55	35	40
	1990-91	68	1161	254	400	109	102	42	122
	1991-92	70	1300	500	440	109	116	46	135
	1992-93	70	1450	254	490	114	125	91	135
5.	एकीकृत परती भूमि परियोजना स्कीम (आई०डबल्यू०डी०पी०एस०)								
	1989-90	—	48.47	106.95	02.75	—	—	—	—
	1990-91	4.71	—	203.82	27.10	54.50	114.56	91.60	—
	1991-92	12.30	—	355.35	264.08	89.01	153.92	50.20	183.35
	1992-93	—	41.20	278.35	217.98	119.23	204.64	145.80	116.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच० ए० डी० पी०)**								
	1989-90	—	3648	—	—	—	—	—	—
	1990-91	—	3887	—	—	—	—	—	—
	1991-92	—	3887	—	—	—	—	—	—
	1992-93	—	3887	—	—	—	—	—	—

अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम	सिक्किम	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1	2	11	12	13	14
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और सम्बद्ध कार्यक्रम				
	1989-90	23	140	7805	2700
	1990-91	30	340	8118	3485

1	2	11	12	13	14
	1991-92	25	343	8465	3834
	1992-93	25	354	8175	3834
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)				
	1989-90	—	—	693	255
	1990-91	—	—	693	204
	1991-92	—	—	700	287
	1992-93	—	—	694	287
3.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई० आर० ई० पी०)				
	1989-90	16	20	135	35
	1990-91	20	25	70	41
	1991-92	20	25	70	44
	1992-93	20	25	70	44

1	2	11	12	13	14
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (एन० आर० डी० पी०)/ जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)				
	1989-90	35	122	7377	2150
	1999-91	41	122	11275	4624
	1991-92	41	132	10603	4536
	1992-93	35	145	10464	4536
5.	एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना स्कीम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०एस०)				
	1989-90	7.00	—	137.36	—
	1990-91	121.23	32.48	260.29	57.00
	1991-92	200.53	59.88	306.51	76.00
	1992-93	202.06	60.20	316.27	100.00

1	2	11	12	13	14
6.	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच० ए० डी० पी०)**				
	1989-90	—	—	17081	1375
	1990-91	—	—	18201	1632
	1991-92	—	—	18201	1932
	1992-93	—	—	18201	1932

*समूचे राज्य से संबंधित है ।

**उ० प्र० के 8 जिलों, असम के 2 जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के 3 प्रभागों से संबंधित ।

टिप्पणी : स्रोत-सादृश्य वर्षों के लिए योजना आयोग के वार्षिक योजना प्रलेख ।

स्तनपान

*207. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले 6 महीनों में केवल मां का दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले बोतल का दूध पीने वाले बच्चों को अतिसार (डाईरिया) अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा माताओं में यह जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बच्चों को अपना दूध पिलायें; और

(ग) स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए "शिशु-मित्र चिकित्सालयों" की अवधारण को मूर्त-रूप देने के लिए अन्य क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

स्तनपान के सन्देश के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसका प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित हैं :—

1. सरकार द्वारा दिसम्बर, 1983 में स्तनपान के संरक्षण और सम्वर्धन के लिए बनाए गए भारतीय कोड में देश में स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा स्तनपान के लाभों का प्रचार करके इसको बढ़ावा देने और संरक्षण देने की बात कही गई है । इस कोड में यह सुनिश्चित करने के लिए सम-न्वित प्रयास करने की व्यवस्था है कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनमें समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्यकर्ता भी शामिल हैं, माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान के लिए प्रेरित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं ।

2. अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्तनपान के लाभों का सन्देश प्रचारित करने हेतु सरकारों के लिए धनराशि निर्धारित की गई है । यह कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम स्तर पर माताओं की नियमित रूप से बैठकें करके किया जाता है । इस कार्यनीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराने के लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है ।

अतिसार रोगों के नियंत्रण पर पोस्टर , पम्फलेट आदि जैसी प्रचार सामग्री में स्तनपान सम्बन्धी सन्देश भी शामिल होते हैं ।

3. राज्य सरकारों को स्तनपान के महत्व पर बल देते हुए पत्र लिखे गए हैं और उनसे शीर्षस्थ चिकित्सा और उपचर्या-व्यवसायिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य जननेताओं को स्तनपान के लाभों का सन्देश प्रसारित करने के काम में इन्हें शामिल करने को कहा गया है ।

4. भारत में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के समारोहों के दौरान भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों ने देश में स्तनपान की धारणा को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देने

की जरूरत पर बल देने के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक समूहों और सरकारी प्रतिनिधियों की बैठकें कीं।

5. शिशु दुग्ध विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1992 नामक विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें शिशु दुग्ध विकल्पों और दूध पिलाने की बोतलों पर रोक लगाने की व्यवस्था है तथा सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि शिशु दुग्ध विकल्पों के विपणन में ऐसी कोई बात न दी जाए कि इन उत्पादों का सेवन स्तनपान के समकक्ष या उससे बेहतर है। विधेयक के उपाबन्धों का उल्लंघन करने पर दाण्डिक कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार भारतीय संघ जैसे व्यावसायिक निकायों के साथ "शिशु मित्र चिकित्सालयों" की आवधारणा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है, जिसके लिए यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहल की गई है। सरकार राष्ट्रीय कार्यदल तैयार करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है जो देश में शिशु मित्र चिकित्सालयों को मान्यता देने के लिए प्रतिक्रियाएं तैयार करेगा।

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिलें

*208. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों को वरीयता के आधार पर लाइसेंस जारी करने की नीति लागू की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यवार स्वीकृति के लिए कितनी सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) इन चीनी मिलों को लाइसेंस जारी करने के लिए कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 20-7-1992 को सहकारी क्षेत्र से संबंधित लंबित आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

1. उत्तर प्रदेश	—	8
2. महाराष्ट्र	—	226
3. गुजरात		12
4. हरियाणा	—	5

5. पंजाब	—	13
6. बिहार	—	6
7. कर्नाटक	—	9
8. आसाम	—	1
	कुल :	280

(घ) पहले जारी किए गए तथा कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए नए प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

जनसंख्या नियंत्रण

*209. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23-24 दिसम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समग्र रूप से तथा बहुक्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाई गई नीतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या नियंत्रण को सफल बनाने के लिए कौन से प्रोत्साहन देने का विचार है अथवा परिवार नियोजन उपाय न अपनाने वाले लोगों को किस प्रकार हतोत्साहित करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एम० फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

एच० आई० वी०-2 विषाणु

*210. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, कितने व्यक्तियों का परीक्षण किया गया, कितने व्यक्तियों में "एलिसा"—पाजिटिव पाये गये तथा कितने व्यक्तियों में वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण के आधार पर एच०आई०वी० संक्रमण होने का पता चला;

(ख) क्या एच०आई०वी०-1 विषाणु संबंधी परीक्षण ये एच०आई०वी०-2 विषाणु सदैव पता नहीं चलता;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषाणु द्वारा उत्पन्न नए खतरे को देखते हुए "एड्स" रोग के प्रत्येक जांच केन्द्र में एच० आई०वी०-2 विषाणु का पता लगाने हेतु जांच उपकरण उपलब्ध कराने का सरकार का क्या विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) से (घ) 1 अक्तूबर, 1985 से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एच०आई०वी० व्याप्तता संबंधी निगरानी की गई जो नवम्बर, 1990 तक चली। तदुपरान्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस निगरानी कार्य को संभाला। इन वर्षों के दौरान इन कार्यकलापों का लगातार विस्तार भी होता रहा। एलिसा लक्षण-युक्त रोगियों के आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए गए हैं। गत तीन वर्षों के वर्ष 1990, 1991 और 1992 (अक्तूबर,1992 तक) के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	1990*		1991		1992 (अक्तू० 92 तक)	
	जांचे गए नमूने	वेस्टर्न ब्लॉट लक्षण युक्त	जांचे गए नमूने	वेस्टर्न ब्लॉट लक्षण युक्त	जांचे गए नमूने	वेस्टर्न ब्लॉट लक्षण युक्त
1.	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	10402	37	15153	50	4135	9
असम	1080	0	3046	3	2372	1
बिहार	4215	0	972	0	562	—
चंडीगढ़	8756	41	27129	62	5113	16
दिल्ली	50352	136	131222	343	23242	186
गोवा	16807	39	17156	40	5990	99
गुजरात	33180	24	28239	19	49201	194
हरियाणा	28071	8	18412	10	13153	12
हिमाचल प्रदेश	1318	1	3495	2	4351	3
जम्मू व कश्मीर	2906	2	—	0	अनुपलब्ध	1
कर्नाटक	16821	15	26840	47	103272	141
केरल	10411	16	7533	10	6863	47

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	13011	31	12734	4	8082	7
महाराष्ट्र	83745	1006	70456	1135	68395	2520
मणिपुर	5209	909	3764	542	1626	237
उड़ीसा	3441	0	3800	0	3884	—
मिजोरम	—	—	—	—	180	—
नागालैंड	—	—	—	—	397	45
पांडिचेरी	14271	149	6739	45	8358	207
राजस्थान	1109	0	382	0	13012	14
तमिलनाडु	217467	1041	190300	465	73423	596
उत्तर प्रदेश	6655	9	21022	153	10399	75
पश्चिमी बंगाल	20634	14	20537	6	44682	32
योग :	550061	3478	608931	2936	369575	4442

*1990 के आंकड़े, 1986 से 1990 तक के समेकित आंकड़ों को दर्शाते हैं।

यह सच है कि एच०आई०वी०-1 वायरस के स्क्रीनिंग परीक्षण में हमेशा एच०आई०वी०-2 वायरस का पता नहीं चलता। यह सूचित किया गया है कि एच०आई०वी०-2 संक्रमणों के लगभग 40 प्रतिशत से 90 प्रतिशत संक्रमणों का संपूर्ण वायरस लायेसेट एच०आई०वी०-1 एलिसा टिकटों के द्वारा पता चला है। तथापि, उचित और अधिकतम जांच सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार अब देश भर में रक्त जांच के लिए एलिसा किटों से युक्त एच०आई०वी० 1+2 ही प्राप्त कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी कालेज

*211. **श्री काशीराम राणा :**

श्री छीतूभाई गामीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान देने हेतु गुजरात सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस दौरे के क्या परिणाम निकले;

(ग) कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा अब तक कितना अनुदान जारी किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक सदस्य, दो विशेषज्ञ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों की एक समिति ने गुजरात में पात्र कालेजों के आठवीं योजना विकास-प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अक्तूबर, 1991 में अहमदाबाद का दौरा किया। समिति से 6 सरकारी कालेजों सहित 168 कालेजों के विकास-प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। 13 सरकारी कालेज अपने प्रस्ताव समिति को प्रस्तुत नहीं कर सके, अत: इनका मूल्यांकन किसी बाद की तारीख को किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर, आयोग ने 168 कालेजों के लिए 988.90 लाख रु० का आवंटन अनुमोदित किया है जिसमें से सरकारी कालेजों का हिस्सा 41.40 लाख रु० है। सरकारी कालेजों के लिए अनुमोदित आवंटन में से आयोग ने अभी तक 5.85 लाख रु० की राशि दी है।

कालेजों को अनुदान, आयोग के पास संसाधनों की उपलब्धता तथा पहले दिए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र व लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण प्राप्त होने पर किश्तों में दिया जाता है। अनुमोदित अनुदानों की आगे की किश्त कालेजों से जब भी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते हैं, दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

*212. **श्री फूलचन्द वर्मा** :

डा० परशुराम गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का नया औषधालय खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोले गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा और अधिक औषधालय खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) किसी ऐसे स्थान पर एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी सुविधाओं वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, यह आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 2000-2500 हो। किसी नए शहर में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर कम से कम 7500 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होने चाहिएं।

(ग) और (घ) इस समय निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्य कर रही है :—

दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, पुणे, नागपुर, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलूर, मद्रास, अहमदाबाद, जबलपुर और नागपुर ।

(इनके अलावा महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए—भुवनेश्वर और रांची में एक-एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला गया है ।)

ऐसे कई शहर हैं जो मानदण्डों के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं; बहरहाल इस समय वे इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं । निधियों की उपलब्धता के अनुसार ऐसे शहरों एवं शहरों के ऐसे नए इलाकों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

औद्योगिक प्रदूषण

*213. **श्री यशवंतराव पाटिल :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कस्बों/नगरों में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में इस बीच कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आकलन के अनुसार महानगरीय क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि होने के मुख्य कारण वाहन के उत्सर्जन तथा घरेलू अपशिष्ट हैं ।

(घ) जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं आरम्भ नहीं की हैं, उनके प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) उद्योगों से कहा गया है कि बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित सीमा में रखने के लिए वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें; और

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निदेश दिए गए हैं कि वे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें । दोषी इकाइयों के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

[अनुवाद]

गंगा सफाई योजना

*214. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी की सफाई के कार्य में निर्धारित कार्य योजना के अनुसार प्रगति न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य की निगरानी समितियां समय-समय पर योजना की समीक्षा करने के बारे में सतर्क हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने गंगा नदी में निस्सारण मानक मनमाने ढंग से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्धारित किये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों तथा नगर निकायों के लिए समान निस्सारण मानक निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत हाथ में ली गई 261 स्कीमों में से 192 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। शेष स्कीमें पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से अधिकांश के दिसम्बर, 1993 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 स्कीमें, जिनमें से अधिकांश सीवेज उपचार संयंत्रों से सम्बन्धित हैं, उनके भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, मुकदमेंबाजी एवं निविदाकर्ताओं से उचित उत्तर न मिलने के कारण इस तिथि के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है। गंगा परियोजना निदेशालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विभिन्न समितियां, चल रही स्कीमों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करती हैं। राज्य सरकार द्वारा भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*215. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परिवार कल्याण के लिए राज्य सरकारों को देय आवंटित निधियां जारी कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार को देय बकाया राशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम 1951-52 में अपने प्रारंभ से एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम रहा है। अनुमोदित पैटर्न/मानदण्डों के अनुसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। केन्द्रीय बजट में उपलब्ध प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में रिलीज किये जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च की संबंधित महालेखाकारों द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है। प्रतिपूर्ति संबंधी दावे महालेखाकारों द्वारा विधिवत् प्रमाणित खर्च के विवरणों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा भरे जाते हैं। 1990-91 और 1991-92 के दौरान नकद और सामग्री के रूप में राज्यों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

2. खर्च के अंकेक्षित विवरणों के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 301.48 करोड़ रुपये की राशि बकाया राशि के रूप में देय हो गई है। इसके विपरीत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि का आंशिक भुगतान करने हेतु 100.00 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को पहले ही दी गई है।

3. राज्यों के देय बकाया की शेष राशि का भुगतान अतिरिक्त धन उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

विवरण-I

(लाखों रुपयों में)

क्रम०सं०	राज्य	1990-91			1991-92		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3917.58	580.61	4498.19	5129.96	752.44	5882.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.67	25.59	104.26	104.73	10.33	115.06
3.	असम	1289.87	200.08	1489.95	1666.54	316.30	1982.84
4.	बिहार	4373.24	621.70	4994.94	4643.20	755.44	5398.64
5.	गोवा	92.38	15.56	107.94	103.13	19.84	122.97
6.	गुजरात	2664.96	487.63	3152.59	2930.78	718.52	3649.30
7.	हरियाणा	1121.51	239.24	1360.75	1400.00	326.60	1726.60
8.	हिमाचल प्रदेश	1166.39	57.21	1223.60	1965.70	83.32	2049.02
9.	जम्मू और कश्मीर	865.86	73.15	939.01	1262.34	84.19	1346.53
10.	कर्नाटक	3647.79	447.59	4095.39	2860.75	466.73	3325.48
11.	केरल	3253.11	259.85	3512.96	1562.73	350.33	1913.06
12.	मध्य प्रदेश	3934.70	863.14	4797.84	4871.07	963.58	5834.65

1 2	3	4	5	6	7	8
13. महाराष्ट्र	6929.88	893.39	7823.27	5990.81	1105.45	7096.26
14. मणिपुर	215.61	22.11	237.72	272.12	14.31	286.43
15. मेघालय	203.76	8.32	212.08	186.89	13.13	200.02
16. मिजोरम	93.52	9.89	103.41	120.35	7.09	127.44
17. नागालैंड	100.96	16.28	117.24	133.77	9.82	143.59
18. उड़ीसा	2528.55	333.35	2861.90	4253.34	395.08	4648.42
19. पंजाब	1291.34	230.65	1522.18	1715.45	332.58	2048.03
20. राजस्थान	2659.75	520.73	3180.48	3701.94	549.12	4291.06
21. सिक्किम	87.91	5.60	93.51	111.41	6.74	118.15
22. तमिलनाडु	3568.79	422.26	3991.05	4778.65	454.90	5233.55
23. त्रिपुरा	194.68	24.76	219.44	322.91	21.17	244.08
24. उत्तर प्रदेश	13327.83	1579.87	14907.70	10413.14	1919.19	12332.33
25. पश्चिम बंगाल	5151.52	590.63	5742.15	6933.34	593.54	7527.87
योग :	62760.16	8529.38	71289.53	67336.04	10267.74	77603.78

[हिन्दी]

अवैध कब्जे वाला वन क्षेत्र

*216. **श्री मेरू लाल मीणा :**

श्री मोहन लाल झिकराम : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1980 तक के अवैध कब्जे वाले वन क्षेत्र को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी हैक्टेयर भूमि को नियमित किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन भूमि पर 25-10-1980 से पहले के अतिक्रमणों को नियमित करने के बारे में दिनांक 18-9-1990 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को नियमित करने के उद्देश्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश में 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1,367 हैक्टेयर वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कॉलेज

*217. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर रोक लगाने का क्या विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र में नये मेडिकल कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, उन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा यथा-निर्धारित मानकों और आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं का सख्ती से अनुपालन नहीं करते हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 का संशोधन करते हुए 27 अगस्त, 1992 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था जिसके अन्तर्गत नए मेडिकल कॉलेज खोलने से पहले केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य सभा में पहले ही एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है।

मिरगी रोग पर काबू पाना

*218. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने देश में मिरगी के मरीजों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मिरगी के उपचार और रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने 1983 में देश में बेंगलूर, बड़ोदा, कलकत्ता और पटियाला स्थित चार केन्द्रों में गम्भीर मानसिक विकारों और मिरगी पर एक सहयोजित अध्ययन किया। इन चारों केन्द्रों में अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार मिरगी की व्याप्तता दरें प्रति हजार जनसंख्या पर 1.29 से लेकर 7.82 तक भिन्न-भिन्न थीं।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनी-अपनी चिकित्सा संस्थाओं में लगातार मिरगी के निदान और उपचार की सुविधाओं का दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

पोलियो का उन्मूलन

*219. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि में देश से पोलियो-उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) सरकार का सन् 2000 ईसवी तक देश से पोलियो का उन्मूलन करने का लक्ष्य है। उन्मूलन संबंधी नीति के अनुसार नियमित रोग-प्रतिरक्षण सत्रों के माध्यम से मुखीय पोलियो वैक्सीन की तीन खुराकों से शिशुओं के रोग-प्रतिरक्षण कवरेज के ऊंचे स्तर प्राप्त करना है। मुखीय पोलियो वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक तीसरी खुराक देने के 12 महीने के बाद दी जाती है और स्वास्थ्य संस्थाओं में पैदा हुए बच्चों को छुट्टी देने से पहले मुखीय पोलियो वैक्सीन की एक खुराक दी जाती है।

रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए उन क्षेत्रों में प्रकोप की रोकथाम में संबंधित उपाय किये जाते हैं, जहां से मामले सूचित किए जाते हैं।

रोग-प्रतिरक्षण कवरेज स्तरों में वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यावसायिक निकायों के सहयोग से प्रतिवर्ष विशेष रोग-प्रतिरक्षण दिवस आयोजित किए जाते हैं।

अत्यधिक खतरे वाले पाकेटों में वाइल्ड पीलियो वायरस के संचरण को कम करने के लिए तीन वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मुखीय वैक्सीन की दो अतिरिक्त खुराकें देकर समय-समय पर विशेष उन्मूलन अभियान चलाए जाते हैं।

आठवीं योजना के लिए व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रमों हेतु नकद और सामग्री के रूप में (जिसमें वैक्सीनें और शीत भंडारण उपकरण शामिल हैं) राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान व्यापक रोग-प्रतिरक्षण
गतिविधियों के लिए अनुमानित आवंटन

(नकद और सामग्रीगत) (लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	योग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2049.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	787.68
3.	असम	2292.35
4.	बिहार	4249.43
5.	गोवा	148.86
6.	गुजरात	1569.07
7.	हरियाणा	1271.77
8.	हिमाचल प्रदेश	950.84
9.	जम्मू व कश्मीर	1070.02
10.	कर्नाटक	1652.55
11.	केरल	1166.51
12.	मध्य प्रदेश	4546.96

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	2492.33
14.	मणीपुर	612.00
15.	मेघालय	376.22
16.	मिजोरम	218.44
17.	नागालैण्ड	509.35
18.	उड़ीसा	1381.44
19.	पंजाब	984.77
20.	राजस्थान	2768.37
21.	सिक्किम	298.57
22.	तमिलनाडु	1807.92
23.	त्रिपुरा	241.87
24.	उत्तर प्रदेश	6430.60
25.	पश्चिम बंगाल	1513.16
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	140.11
27.	चंडीगढ़	73.41
28.	दादरा व नागर हवेली	73.01
29.	दमण व दीव	138.26
30.	दिल्ली	112.50
31.	लक्षद्वीप	71.93
32.	पांडिचेरी	286.00
	योग :	42285.86

जहरीली दवाइयां

*220. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए शिड्यूल दवाइयों की विषाक्तता की जांच उन्हें बाजार में जारी करने से पहले की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों के बताए नुस्खे अथवा म्युनिसिपल प्राधिकारियों द्वारा निःशुल्क वितरण से इस प्रकार की दवाइयों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से मृत्यु होने अथवा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की दवाइयों की विषाक्तता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने वाले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली के अस्पतालों और नगर प्राधिकारियों ने हाल ही में शड्यूल औषधों के प्रयोग से हुई किसी गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया अथवा मृत्यु के मामले की सूचना नहीं दी है। तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए एक बड़े मलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान हाल ही में बसंत कुंज में मंद प्रतिक्रिया के एक मामले की सूचना दी गई थी।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

2321. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के लिए वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान योजना और गैर-योजना के अंतर्गत बजट आवंटन कितना था;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के बजट आवंटन में की गई कटौती के संबंध में और इसे स्वायत्तशासी निकाय बनाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली का राजस्व व्यय और वर्ष 1992-93 के लिए सदृश बजट अनुमान इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1990-91	1991-92	1992-93
गैर-योजना	125.54	126.55	125.40
योजना	5.58	3.31	5.00

(ख) और (ग) इस बारे में सरकार को कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, सरकार ने समाचारपत्रों में इस आशय के कुछ समाचार देखे हैं।

(घ) चिड़ियाघर के बजट में ऐसी कोई कटौती नहीं की गई है। तथापि, उद्यान एक सरकारी प्रतिष्ठान है और इससे अपेक्षा की जाती है कि यह पशुओं के रख-रखाव को प्रभावित किए बगैर वित्तीय नियंत्रण और आर्थिक निर्धारणों का अनुपालन करे।

आन्ध्र प्रदेश में समुद्र तट के साथ-साथ हरित पट्टी

2322. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से हरित पट्टी का विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू कराया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चक्रवात पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्र में एक सुरक्षा पट्टी वृक्षारोपण कार्यक्रम 1990 से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना 1993-94 में समाप्त हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आन्ध्र प्रदेश के लिए एक वानिकी परियोजना विदेशी सहायता हेतु विश्व बैंक के पास विचाराधीन है। परियोजना प्रस्ताव में बलुई समुद्रतटीय क्षेत्रों का वनीकरण शामिल है।

चीनी उद्योग का घाटा

2323. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी उद्योग को हुए घाटे के लिए उत्तरदायी कारण क्या है;

(ख) घाटों को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सरकार चीनी मिलों को होने वाले लाभ व घाटे का हिसाब नहीं रखती है। गन्ने की उपलब्धता के अतिरिक्त चीनी मिलों की लाभ-प्रदता या हानि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें क्षमता, प्लांट एवं मशीनरी की अवस्था व स्थिति, तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार चीनी मिलों की अर्थक्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय कर रही है

जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई रूपांतरण लागत अनुसूची के आधार पर निर्धारित की गई लेवी चीनी की उचित एक्स फैक्ट्री कीमत का भुगतान;

(2) विवेकपूर्ण मासिक रिलीज के माध्यम से खुले बाजार में चीनी की कीमतें उचित स्तर तक बनाए रखना; और

(3) चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन तथा गन्ना विकास परियोजनाओं दोनों के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(ग) चालू चीनी मौसम 1992-93 के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 122 लाख टन होने का अनुमान है ।

कबीर पुरस्कार

2324. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कबीर पुरस्कार प्रदान करने का क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, व्यवसाय तथा पदनाम क्या हैं जिनको वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान कबीर पुरस्कार प्रदान किये गए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में उक्त पुरस्कार प्रदान करने के कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि काव्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले कबीर सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जिनसे सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दन्त चिकित्सकों का स्थानान्तरण

2325. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे दन्त चिकित्सकों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने दन्त चिकित्सक स्थानांतरित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पांच वर्ष से अधिक समय से एक अस्पताल में कार्य कर रहे दंत-चिकित्सकों का स्थानांतरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एन०सी०ई०आर०टी० में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

2326. **श्री राम विलास पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० ई० आर० टी० शैक्षिक और तकनीकी संवर्गों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो एन० सी० ई० आर० टी० में लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों के कुल कितने पद हैं, इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एन० सी० ई० आर० टी० निर्धारित प्रकिया का पालन किये बिना विभिन्न पदों को अनारक्षित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ शैक्षिक पदों के लिए रा० शै० अ० प्र० प० में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में अप्रैल, 1981 से ही वर्ष 1975 के भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। व्याख्याताओं के पदों में जो ग्रुप "क" पदों की निम्नतम कोटि है, आरक्षण किया जा रहा है। रा० शै० अ० प्र० प० में व्याख्याताओं के 315 पदों में से अभी तक 4 पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में उपचार

2327. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदेशों में उपचार कराने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ताकि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बचाव किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे अधिकतम कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार देशों के निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों को कतिपय प्रोत्साहन देकर उनमें आधुनिक एवं विशेष चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ताकि भारत में ही समुचित उपचार सुविधाएं प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 1-3-1988 की अधिसूचना संख्या 64/88 कष्ट० के अनुसार नवीनतम चिकित्सीय उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट के रूप में अस्पतालों (धर्मार्थ/अर्ध धर्मार्थ/प्राइवेट) को कुछ प्रदान कर रही है । सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा पूरी तरह उस राज्य सरकार की सिफारिश पर प्रदान किए जाते हैं जहां वह संस्थान स्थित है । राज्य सरकार यह भी प्रमाणित करती है कि ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में 40 प्रतिशत तथा अंतरंग रोगी विभाग में 10 प्रतिशत निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा ।

राजधानी एक्सप्रेस में इलाहाबाद और गया के लिए आरक्षण कोटा

2328. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस में इलाहाबाद और गया के लिए आवंटित आरक्षण कोटे का पिछले छः महीनों के दौरान पूर्णतः उपयोग किया गया;

(ख) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटे में से भरे गये कोटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले छः महीनों अर्थात् जून से नवम्बर, 1992 तक कोटा की दैनिक औसत उपयोगिता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

से	तक	वातानुकूल दूसरा दर्जा	कुर्सीयान
इलाहाबाद	नई दिल्ली	44%	47%
इलाहाबाद	हवड़ा	67%	82%
गया	नई दिल्ली	87%	98%
गया	हवड़ा	30%	73%

(ग) विभिन्न स्टेशनों पर कोटा की उपयोगिता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और विभिन्न स्टेशनों की मांगों और आरक्षित स्थान की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

खेल संस्थाओं का निर्माण

2329. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार से 1 जुलाई 1991 से ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; जिनमें स्टेडियमों, खेल संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण तथा खेलों के विकास के लिए अनुदान देने की मांग की गयी है;

(ख) स्वायत्त खेल और स्वयंसेवी संगठनों ने राज्य-वार कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है अथवा कितने विचाराधीन हैं;

(घ) मंजूर की गई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है; और

(ङ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विभाग की बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं के अन्तर्गत 1-4-91 से 30-11-1992 तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार विस्तृत विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

(ङ) प्रस्तावों के औचित्य के आधार पर देय सहायता स्वीकृत की जाएगी ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	कालम 3 में से स्वायत्त शासी खेल तथा स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित योजना की स्वीकृत राशि	केन्द्रीय सहायता हेतु अनुचित पाये गए प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	10	10	2	43,78,682 रुपये	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	76	—	—	4	—	72
4.	बिहार	4	1	1	2	10,00,000 रुपये	1
5.	गुजरात	11	4	2	1	24,00,000 रुपये	8
6.	गोवा	1	—	—	1	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
8.	हरियाणा	79	2	2	2	23,87,620 रुपये	75
9.	जम्मू और कश्मीर	10	—	1	1	77,580 रुपये	8
10.	केरल	38	—	1	13	10,00,000 रुपये	24
11.	कर्नाटक	69	24	20	6	32,95,884 रुपये	43
12.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	11	4	3	5	79,61,000 रुपये	3
14.	मणिपुर	5	—	—	1	—	4
15.	मध्य प्रदेश	125	—	24	64	61,03,382 रुपये	37

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	1	—	1	—	1,00,000 रुपये	—
18.	उड़ीसा	160	—	4	29	4,00,000 रुपये	127
19.	पंजाब	12	—	6	2	5,13,828 रुपये	4
20.	राजस्थान	2	—	—	1	—	1
21.	सिक्किम	4	—	—	4	—	—
22.	तमिलनाडु	430	7	11	270	2,06,72,580 रुपये	149
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	9
24.	उत्तर प्रदेश	56	—	—	47	—	9
25.	पश्चिम बंगाल	33	1	—	7	—	26
	संघ शासित प्रदेश						
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9	—	7	—	7,00,000 रुपये	2
2.	चण्डीगढ़	4	—	—	—	—	4
3.	दमन तथा दीव	—	—	—	—	—	—
4.	दिल्ली	1	—	—	—	—	1
5.	दादर तथा नगर हवेली	1	—	—	—	—	1
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
7.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—

[अनुवाद]

दक्षिण-पूर्व रेलवे में उपरिपुल

2330. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे उपरिपुलों की कौन-कौन सी परियोजनाएं रेलवे सुरक्षा कार्य-निधि से धनराशि दिये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित हैं और कब से पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पुरातत्व सर्किल

2331. **श्री एम० जे० राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पुरातत्व सर्किलों की उनके मुख्यालय स्थलों के साथ संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का गुजरात और अन्य राज्यों में कुछ नए पुरातत्व सर्किलों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का केवल एक ही मंडल कार्यालय है; जिसका मुख्यालय वडोदरा में है ।

(ख) वडोदरा मंडल के अधीन संपूर्ण गुजरात तथा दमन व दीव भी आते हैं ।

(ग) और (घ) गुजरात में किसी भी प्रकार के नये मंडल कार्यालय खोलने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है । दूसरे राज्यों में भी मंडल कार्यालय खोलने के लिए कोई भी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

2332. **श्री रामचन्द्र डोम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम में उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया किन्तु जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) प्रत्येक परियोजना को किस तारीख तक पूरा किया जाना है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(च) इनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं की स्थिति दर्शायी गई है।

(ङ) और (च) आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में वार्षिक आधार पर निर्णय किया जाएगा, जो संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होगा। चालू वर्ष के दौरान एक परियोजना अर्थात् पुरूलिया-कोटशिला (35 कि०मी०) का आमान परिवर्तन कार्य 20 करोड़ रु० की लागत से शुरू किया गया है।

विवरण

(क) से (घ) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल पश्चिम बंगाल की रेल परियोजनाएं, उनकी मौजूदा स्थिति चालू किए जाने की संभावित तारीख तथा उनकी अनुमानित लागत नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्ष	प्रतिशत (%)	लम्बाई (कि०मी०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	तामलुक-दीघा	(1984-85)	11%	87	73.71 करोड़ रु०
2.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	(1987-88)	29%	47	39.16 करोड़ रु०
3.	एकलाखी-बालूघाट	(1985-84)	3%	87	74.14 करोड़ रु०
दोहरीकरण					
1.	साहिबगंज लिंक केबिन न्यू फरक्का-मालदा टाउन	(1986-87)	60%	50	36.80 करोड़ रु०
2.	बारासात-दत्तपुकुर	(1989-89)	67%	8	6.68 करोड़ रु०
3.	दत्तपुकुर-हावरा	(1900-91)	50%	14	18.17 करोड़ रु०

1	2	3	4	5	6
4.	बारसोई-दलकोल्हा और धूलाबाड़ी-अलुआबाड़ी	(1987-88)	76.83%	34	30.11 करोड़ रु०
5.	अलुआबाड़ी रोड-किशनगंज और न्यू जलपाईगुड़ी अम्बारी फालाकाटा	(1989-90)	46.50%	40	46.29 करोड़ रु०

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

2333. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**

श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोपाल तथा आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन स्टेशनों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त स्टेशनों पर 1992-93 के दौरान प्रदान की गई सुविधा का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलें रख-रखाव पर होने वाले वाले व्यय का स्टेशन-वार लेखा नहीं रखती हैं ।

(घ) 1992-93 के दौरान भोपाल और आस-पास के अन्य स्टेशनों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं :—

स्टेशन	निर्माण कार्य का ब्यौरा	प्रत्याशित लागत (लाख रुपयों में)	1992-93 के लिए आबंटित धन (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
विदिशा	दूसरे दर्जे में नया प्रतीक्षालय	10.00	3.00
भोपाल	डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था में सुधार (प्लेटफार्म नं० 3 और 4)	15.00	12.84

1	2	3	4
भोपाल	110 वोल्ट बैटरी जार्ज करने की सुविधा की व्यवस्था	9.46	1.00
विदीशा	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	5.00	3.00
सलामतपुर	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	7.69	0.58
मदन महल	स्टेशन इमारत का विस्तार	4.64	3.14

[अनुवाद]

घातक रोग

2334. **डा० सुधीर राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन रोगों से अधिकतम रोगियों की मृत्यु होती है; और

(ख) 1992 में ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके अब क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1987 तक के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रमुख कारणों से हुई मौतों का विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारों के लिए रोगों की रोकथाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना अपेक्षित होता है। वैसे, क्षयरोग, जो अधिकतम मौतो का कारण है, की रोकथाम के लिए 1962 से राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग-निदान और उपचार संबंधी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश के 390 जिलों में पूर्ण स्टाफ़ और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित जिला क्षयरोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 330 अन्य क्षय-रोग क्लीनिक हैं जो मुख्यतः शहरों में कार्य कर रहे हैं और गम्भीर रूप से बीमार रोगियों के लिए 47000 क्षयरोग पलंग उपलब्ध हैं। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निवारणात्मक उपाय के रूप में 0-1 वर्ष की आयु के बच्चों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है।

संक्षिप्त की गई सूची संख्या, 1979 की पुनरावृत्ति*	विवरण						
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987*
1	2	3	4	5	6	7	8
योग :	—	196847	196240	205226	—	259370	321409
आई०सी०डी० (010-018) क्षय रोग	—	17599	20953	18612	—	17845	23526
आई०सी०डी० (140-239) नियोप्लाजम	—	6703	7013	8594	—	10986	11482
आई०सी०डी० (250) मधुमेह	—	1863	1651	2850	—	3697	4230
आई०सी०डी० (260-269) पौषणिक की कमी	—	1655	1537	2132	—	2267	3221
आई०सी०डी० (282-285) अरक्तक	—	2590	2133	5264	—	6272	6862
आई०सी०डी० (320-322) मेनिन जाइटिस	—	2107	1854	3141	—	3544	5431
आई०सी०डी० (393-398) चिरकालिक रूमेटी हृदयरोग	—	1731	1506	1740	—	2301	2745
आई०सी०डी० (401-405) अतिरक्तदाब रोग	—	1825	3281	2954	—	5513	4249
आई०सी०डी० (410-414) इस्केमिक हृदय रोग	—	11771	11454	13609	—	16724	22709
आई०सी०डी० (430-438) सेरिब्रोवास्कुलर रोग	—	6248	8731	10023	—	12142	12819
आई०सी०डी० (480-486) न्योमोनिया	—	9274	5536	11444	—	10884	17337

1		2	3	4	5	6	7	8
आई०सी०डी० (490-493)	ब्रोंकाइटिस ऐम्फी सेमा एवं दमा	—	2820	4130	4588	—	5905	6480
आई०सी०डी० (571)	क्रोनिक लीवर डिजाज एवं सिरहोसिस	—	2618	2717	3605	—	3556	4095
आई०सी०डी० (580-589)	नेफराइटिस, नेफरोटिक सिन्ड्रोम एवं नेफरोसिस	—	1445	1986	2153	—	2488	4086
आई०सी०डी० (740-759)	जन्मजात व मेलीज	—	1112	1666	1696	—	3118	4086
आई०सी०डी० (E800-E848)	परिवहन दुर्घटनाएं	—	936	1147	2815	—	206	1086
आई०सी०डी० (E950-E959)	आत्महत्या व इन्फ्लिसिटेड इंजुरी	—	103	278	390	—	23	21
अन्य		—	124447	120157	109616	—	151899	188757

स्त्रोत : मौतों के कारणों के मृत्यु दर संबंधी आंकड़े 1987। भारत के जन्म-मरण संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक 1987 के आंकड़े आई० सी० डी०-1979 के नौवें संशोधन के अनुसार हैं।

टिप्पणी : ये आंकड़े केवल उन अस्पतालों के मृत्यु दर संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों "मौत के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन की योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है। जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। अतः ये आंकड़े लक्षण संबंधी रेखाचित्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। अधिक-से-अधिक ये अनुपात को प्रदर्शित करते हैं।"

हावड़ा/सियालदाह की उप-नगरीय रेलवे

2335. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षों के दौरान हावड़ा/सियालदाह उप-नगरीय रेलवे से कितनी आय हुई तथा इस पर कितना व्यय हुआ और अगले दो वर्षों में इससे कितना राजस्व प्राप्त होने तथा इस पर कितना पूंजी निवेश किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हावड़ा/सियालदह की उपनगरीय रेलों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई आय और व्यय नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय
1989-90	73.09	172.06
1990-91	86.15	206.91
1991-92 (अनंतिम)	96.91	245.91

किसी खंड विशेष के लिए राजस्व और निवेश का अनुमान एक वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए अग्रिम में नहीं लगाया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्व और निवेश की राशि क्रमशः 102.50 करोड़ रुपये और 20.75 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

2336. **डा० राजगोपालन श्रीधरण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते समय घायल होने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) "खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष" की योजना के अन्तर्गत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेते समय घातक चोट लगने के अलावा चोट लगने पर खिलाड़ियों को अधिकतम 25,000/- रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते समय घातक चोट लगने के मामले में खिलाड़ियों के परिवारों को अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर पैदल पार-उपरिपुल का ढहना

2337. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 सितम्बर, 1992 को पश्चिम रेलवे के जोगेश्वरी उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर पैदल पार-उपरि पुल ढह गया था;

(ख) क्या सरकार ने इसके ढहने की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) इसमें कितने यात्री घायल हुए और वास्तव में घायल हुए कितने यात्रियों को राहत दी गई है; और

(ङ) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चूंकि बरसात से बचने के लिए ऊपरी पैदल पुल पर बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसलिए फर्श का एक छोटा-सा हिस्सा गिर गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) घायल हुए सभी 50 यात्रियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) चर्चगेट-बिरार खंड पर सभी ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों का एक विशेष निरीक्षण किया गया है तथा तत्काल की जाने वाली सभी प्रकार की मरम्मत कर दी गई है।

रेल पटरियों का नवीकरण

2338. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में देश में कुल कितनी रेल पटरियों का नवीकरण किया जाना था;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा वर्ष 1990-91 और 1991-92 में रेल पटरियों के नवीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वास्तव में कितनी रेल पटरियों का नवीकरण किया गया;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कितनी रेल पटरियों का नवीकरण किया जाना था; और

(घ) शेष बची सभी रेल पटरियों का कब तक नवीकरण कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बकाया रेलपथ नवीकरण की स्थिति इस प्रकार है :—

छठी योजना के अंत में 19500 कि०मी० (पूरे रेलपथ का नवीकरण)

सातवीं योजना के अंत में 12000 कि०मी० (पूरे रेलपथ का नवीकरण)

(ख) सातवीं योजना तथा 1990-91/1991-92 के दौरान रेलपथ के नवीकरण की प्रगति निम्नलिखित थी :—

(आंकड़े कि०मी० में, पूरे रेलपथ का नवीकरण)

सातवीं योजना	लक्ष्य	वास्तविक
1985-86	3300	3578
1986-87	3800	3978
1987-88	4200	4540
1988-89	3750	3858
1989-90	3550	3669
1990-91	3500	3611
1991-92	3325	3360

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में (1-4-92) बकाया रेलपथ का नवीकरण (पूरे रेलपथ का नवीकरण) 9600 कि०मी० था।

(घ) निधि के वर्तमान को देखते हुए बकाया कार्य को नौवीं योजना में ले जाना पड़ेगा··· बहरहाल, आठवीं योजना के दौरान मुख्य मार्गों पर रेलपथ नवीकरण के बकाया कार्य को समाप्त करने के प्रयास किये जाएंगे।

परिक्रमा रेलवे लाइन

2339. **डा० असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न शहरों में अब तक निर्माणाधीन परिक्रमा रेलवे लाइनों को पूरा करने तथा इनका विस्तार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्वीकृत योजना के अनुसार दम-दम से प्रिंसेपघाट (13.5 कि० मी०) तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को दैनिक यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के परामर्श से प्रिंसेपघाट से भाजरहाट (5.5 कि०मी०) तक सर्कुलर रेलवे के विस्तार की व्यावहारिकता की जांच की गई थी, क्योंकि यह क्षेत्र कलकत्ता पोर्ट

ट्रस्ट की भूमि से होकर गुजरता है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण अपेक्षित भूमि को छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं।

[हिन्दी]

आदिवासियों द्वारा पशुओं का शिकार

2340. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों में रहने वाले आदिवासियों का अपने उत्सवों के दौरान शिकार करना एक सांस्कृतिक अधिकार है;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध इस बारे में कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में केवल अधिनियम की धारा 65 में यथा विनिर्दिष्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त शिकार करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। अधिनियम के तहत शिकार करने के लिए अन्य कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वन और वन्यजीव भी शामिल हैं, का संरक्षण और सुधार करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। समाज को ऐसी परंपराओं और धारणाओं का अनिवार्य रूप से त्याग करना होगा जो बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं। इस लक्ष्य को समाज सुधार के लिए शिक्षा, उन्नत सामाजिक जागरूकता और अभियानों के जरिए प्राप्त करना होगा।

संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

स्थायी ग्रामीण रोजगार योजना

2341. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान स्थायी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खराब वन भूमि को आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे देश के प्रस्तावित वन क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अरावली पर्वतमाला में औद्योगिक कार्यकलापों से संबंधित अधिसूचना

2342. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली पर्वतमाला में औद्योगिक और अन्य कार्यकलापों को विनियमित करने वाली अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस अधिसूचना के विरुद्ध कतिपय संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। यह अधिसूचना अरावली पर्वतश्रृंखला में हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान के अलवर जिले में शिनाख्त किये गए क्षेत्रों में खनन, औद्योगिक गतिविधियों, वृक्षों की कटाई, आवास इकाइयों के समूहों का निर्माण तथा विद्युतीकरण आदि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए है।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया में संबंधित विकास एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने का भी प्रावधान है। अतः हरियाणा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों को उपयुक्त रूप से शामिल करके ही अंतिम अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

दृश्य श्रव्य शिक्षा

2343. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दृश्य श्रव्य शिक्षा शुरू की है/शुरू किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सुविधा कितने विद्यालयों को दी गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान ये सुविधाएं कितने विद्यालयों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केंद्र प्रयोजित "शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्कीम", जो पहले से ही चालू है, प्रारंभिक स्कूलों को दृश्य-श्रव्य सहायता प्रदान करती है, अर्थात् उन राज्यों में जहां स्कूलों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है उनके लिए रेडियो कम कैसेट प्लेयर हेतु, शत-प्रतिशत सहायता तथा रंगीन टी० वी० के लिए 75% सहायता प्रदान की जाती है। राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें 1992-93 के दौरान 10,000 रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर तथा 6000 रंगीन टी० वी० प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

रेडियो एवं कैसेट प्लेयर और रंगीन टेलीविजन उपलब्ध कराये गए स्कूलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	संस्वीकृत रंगीन टेलीविजनों की संख्या	संस्वीकृत रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12,709	17,342
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	286
3.	असम	—	14,338
4.	बिहार	430	430
5.	गोआ	79	1,056
6.	गुजरात	7,420	7,000
7.	हरियाणा	—	9,694
8.	हिमाचल प्रदेश	—	7,256
9.	जम्मू और कश्मीर	—	10,863
10.	कर्नाटक	—	26,080
11.	केरल	—	7,441
12.	मध्य प्रदेश	3,360	5,000
13.	महाराष्ट्र	4,000	32,000
14.	मणिपुर	—	2,631
15.	मेघालय	—	1,521
16.	मिजोरम	20	1,505
17.	नागालैंड	—	970
18.	उड़ीसा	3,876	28,000
19.	पंजाब	—	12,807
20.	राजस्थान	1,100	13,500
21.	सिक्किम	—	739
22.	तमिलनाडु	—	20,000

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	—	43
24.	उत्तर प्रदेश	3,020	30,835
25.	पश्चिम बंगाल	—	3,243
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	130
27.	चंडीगढ़	41	41
28.	दिल्ली प्रशासन	1,054	1,255
29.	दादर और नगर हवेली	—	91
30.	दमन और दीव	—	30
31.	लक्षद्वीप	—	32
32.	पांडिचेरी	—	307
	योग :	37,129	2,56,566

साक्षरता

2344. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साक्षरता प्रसार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 1992 तक इस संबंध में राज्य-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार तथा लिंग-वार साक्षरता की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री : (कुमारी शैलजा) : (क) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०एल०एम०) जिसका मुख्य उद्देश्य, वर्ष 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़-निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता-उन्मूलन के लिए समग्र कार्यक्रमों का हिस्सा हैं तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघशासित प्रशासनों के जिलों को अधिक से अधिक शामिल करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, ये अभियान साक्षरता कार्यक्रम में लड़कियों तथा महिलाओं की गतिशीलता तथा सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे।

(ख) आप्रेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत आने वाले ब्लाकों की संख्या, प्रत्येक राज्य/संघ-शासित प्रशासन में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत संस्वीकृत केन्द्रों की संख्या तथा पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत आंशिक या पूरी तरह से शामिल किए गए जिलों की संख्या को दर्शाने वाला संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश के साक्षरता संबंधी आंकड़े, दस-वर्षीय जनगणना के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं। अन्तिम जनगणना 1991 में की गई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार तथा लिंगवार साक्षरता दर्शाने वाले विवरण-II संलग्न है।

(घ) प्रारम्भिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम के साथ-साथ, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 345 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे साक्षरता दर लगभग 70% तक बढ़ने की आशा की जाती है तथा साक्षरता का यह स्तर अनुवर्ती 2-3 वर्षों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	"आप्रेशन ब्लैकबोर्ड" योजना के अन्तर्गत शामिल ब्लाकों की संख्या	पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शामिल जिलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29085	1140	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	24	—
3.	असम	14063	73	6
4.	बिहार	51990	238	6
5.	गोआ	—	10	2
6.	गुजरात	4940	61	20
7.	हरियाणा	810	100	7
8.	हिमाचल प्रदेश	350	68	12
9.	जम्मू और कश्मीर	3993	197	—
10.	कर्नाटक	3201	189	9
11.	केरल	150	151	14

1 2	3	4	5
12. मध्य प्रदेश	34561	345	11
13. महाराष्ट्र	2750	298	12
14. मणिपुर	2650	28	—
15. मेघालय	—	6	—
16. मिजोरम	200	20	—
17. नागालैंड	—	28	—
18. उड़ीसा	20715	241	7
19. पंजाब	—	118	6
20. राजस्थान	12161	237	4
21. सिक्किम	—	405	—
22. तमिलनाडु	1475	399	12
23. त्रिपुरा	—	12	—
24. उत्तर प्रदेश	63700	895	8
25. पश्चिम बंगाल	24828	73	13
संघशासित क्षेत्र			
26. अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	5	—
27. चण्डीगढ़	100	1	1
28. दादरा और नगर हवेली	100	10	—
29. दमन और दीव	—	2	—
30. दिल्ली	500	—	1
31. लक्षद्वीप	—	5	—
32. पांडिचेरी	—	6	4

विवरण-II

क्रम सं०	भारत/राज्य/संघशासित क्षेत्र	साक्षरता दर 1991		
		व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	6	7	8
	भारत	52.11	63.86	39.42
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	45.11	56.24	33.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.22	51.10	29.37
3.	असम	53.42	62.34	43.70
4.	बिहार	38.54	52.63	23.10
5.	गोआ	76.96	85.48	68.20
6.	गुजरात	60.91	72.54	48.50
7.	हरियाणा	55.33	67.85	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	63.54	74.57	52.46
9.	जम्मू और कश्मीर	उ०न०	उ०न०	उ०न०
10.	कर्नाटक	55.98	67.25	44.34
11.	केरल	90.59	94.45	86.93
12.	मध्य प्रदेश	43.45	57.43	28.39
13.	महाराष्ट्र	63.05	74.84	50.51
14.	मणिपुर	60.96	72.98	48.64
15.	मेघालय	48.26	51.57	44.78
16.	मिजोरम	81.23	84.06	78.09
17.	नागालैंड	61.30	66.09	55.72

1	2	6	7	8
18.	उड़ीसा	48.55	62.37	34.40
19.	पंजाब	57.14	63.68	49.72
20.	राजस्थान	38.81	55.07	20.84
21.	सिक्किम	56.53	64.34	47.23
22.	तमिलनाडु	63.72	74.88	52.29
23.	त्रिपुरा	60.39	70.08	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	41.71	55.35	26.02
25.	पश्चिम बंगाल	57.72	67.24	47.15
	संघशासित क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74	79.68	66.22
2.	चंडीगढ़	78.73	82.67	73.61
3.	दादरा और नगर हवेली	39.45	52.07	26.10
4.	दमन और दीव	73.58	85.67	61.38
5.	दिल्ली	76.09	82.63	68.01
6.	लक्ष्यद्वीप	79.23	87.06	70.88
7.	पांडिचेरी	74.91	83.91	65.79

*1991 की जनगणना जम्मू व कश्मीर में नहीं की गई।

उ० न० का तात्पर्य हैं (उपलब्ध नहीं)।

सिन्दूरपंका तथा संबलपुर में पुल

2345. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर सिंदूरपंका तथा सम्बलपुर (उड़ीसा) में रेलवे लाइनों पर सड़क उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्माणाधीन सम्बलपुर-तालचेर नई लाइन से संबंधित ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेके प्रदान कर दिए गए हैं और निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई।

चाणक्यपुरी में रेल दुर्घटना

2346. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1992 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्टेशन पर कोई रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप रेलवे की सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 21-11-92 को भट्टी के तेल से लदे 72 टंकी माल डिब्बों वाली बाद-दिवाना मालगाड़ी 8.35 बजे दिल्ली-सफदरजंग से गुजरी थी। यह गाड़ी-दिल्ली-सफदरजंग और बरार-स्क्वेअर के बीच विभक्त हो गई थी तथा 35 टंकी माल डिब्बे पीछे छोड़ गई थी। परिष्कृत तेल ले जा रही 64 माल डिब्बों वाली एक अन्य खरीरोहर रोड-शकूरबस्ती पैट्रोल, तेल, स्नेहक मालगाड़ी 8.55 बजे दिल्ली सफदरजंग से रवाना हुई और लगभग 9.00 बजे बाद-दिवाना मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है।

(ग) इस दुर्घटना के कारण रेल संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) रेलपथ	2,18,740/- रुपये
(2) सवारी एवं माल डिब्बे	3,74,000/- रुपये
(3) सिगनल व दूर-संचार	20,000/- रुपये
(4) शिरोपरि विद्युत उपस्कर	3,00,000/- रुपये
(5) रेल इंजन	50,000/- रुपये
कुल :	9,62,740/- रुपये

पंजाब में रेलवे स्टेशन

2347. **श्री गुरचरण सिंह दादाहूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवी योजना के दौरान पंजाब में रेलवे स्टेशनों के सुधार संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में सुधार के लिए किन-किन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आठवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1992-93 के दौरान, पंजाब में रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए निम्नलिखित निर्माण-कार्य शुरू किए गए हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन	कार्य का ब्यौरा
1.	फिरोजपुर	प्लेटफार्म नं० 1 पर यात्री प्लेटफार्म के मौजूदा जंग लगे सायबान को बदलना ।
2.	जालंधर शहर	स्टेशन क्षेत्र में जल-सप्लाई व्यवस्था में सुधार ।
3.	लुधियाना	437400 लिटर क्षमता वाले स्टील के मौजूदा एच० एस० टैंक का बदलाव ।
4.	जालंधर शहर	आदर्श स्टेशन (चरण-II) के रूप में विकसित करने के संबंध में, स्टेशन की इमारत के ढांचे में सुधार ।
5.	अमृतसर	प्लेटफार्म नं० 1 पर शेड का विस्तार ।
6.	लुधियाना	प्लेटफार्म नं० 2 एवं 3 पर शेड का विस्तार ।
7.	जालंधर छावनी	प्लेटफार्म नं० 2 एवं 3 पर सायबान का विस्तार ।
8.	भटिंडा	भटिंडा में प्लेटफार्म पर जल-शीतकों और जलशीतक की व्यवस्था ।
9.	अंबाला मंडल	राजपुरा, सरहिंद, संगरूर और अबोहर स्टेशनों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था ।
10.	पटियाला	परिलचन क्षेत्र में सुधार ।

यदि यातायात की आवश्यकता की दृष्टि से अपेक्षित हुआ तो आठवीं योजना के शेष वर्षों में भी इस तरह के सुधार कार्य किये जायेंगे बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

(ग) 60.15 लाख रुपये ।

दिल्ली के अस्पतालों में चूहों की समस्या

2348. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की सरकारी अस्पतालों में चूहों की समस्या के बारे में गत दो वर्षों के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) कुछ सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर चूहों के उपद्रव के बारे में सूचना मिली है। इसके निवारण के लिए चूहेदानियों और चूहामार दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। धूमकनाशी एवं पेस्ट नियंत्रण एजेंसियों को भी इस कार्य में लगाया गया है।

उड़ीसा में चलते-फिरते खाद्य एवं पोषण विस्तार एकक

2349. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर में कार्यरत चलते-फिरते खाद्य एवं पोषण विस्तार एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ढेंकनाल तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे एकक शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उड़ीसा के प्रत्येक जिले में कब तक ऐसे एकक शुरू किए जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य और पोषाहार बोर्ड का भुवनेश्वर में कार्यरत केवल एक ही सामुदायिक खाद्य और पोषाहार विस्तार यूनिट है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नीमच-रतलाम सेक्शन का गेज परिवर्तन

2350. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के चित्तौड़-रतलाम सेक्शन पर नीमच और रतलाम के बीच गेज परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करने की संभावना है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

अम्बलपूजा पर उपरिपुल

2351. **श्री थाईल जाल अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अल्लेप्पी कायनकुलम रेल लाइन पर अम्बलपूजा उपरिपुल के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) अल्लेप्पी-कायनकुलम लाइन पर, पुन्नापुरा तथा अम्बलपूजा स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर 10605 चेनेज पर एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जाना है ।

(ग) प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

[हिन्दी]

गुरूली रामगढ़वा हॉल्ट स्टेशन

2352. **श्री राम सागर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छितौनी सैक्शन पर गुरूली रामगढ़वा हाल्ट स्टेशन का स्थान बदलने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) नवम्बर, 1992 के दौरान गुरूली रायगढ़वा हाल्ट स्टेशन का स्थान परिवर्तन करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इस मामले में यथासमय गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

[अनुवाद]

पुणे और अहमदाबाद के बीच दैनिक रेलगाड़ी

2353. **श्री अन्ना शोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे और अहमदाबाद के बीच कुल कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या इन स्टेशनों के बीच कोई दैनिक ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 5 जोड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियां अहमदाबाद और पुणे को जोड़ती हैं।

(ख) 1095/1096 अहमदाबाद-पुणे एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को प्रतिदिन चलाने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जांच की गई थी, परन्तु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय झील विकास कार्यक्रम

2354. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

डा० कृपासिंधु भोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय झील विकास कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम को लागू करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हेतु किन झीलों का चयन किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ग) से (घ) प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

एन०एम०एम०एल० का कतिपय दिनों को बंद रखा जाना

2355. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल लाइब्रेरी एण्ड म्यूजियम कितने दिन बन्द रहा;

(ख) क्या उक्त परिसर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था के कारण बन्द किया जाता है;

(ग) क्या सरकार को हजारों शोधछात्रों को इस कारण होने वाली अनावश्यक परेशानी की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो एन०एम०एम०एल० में सुनिश्चित रूप से सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान संग्रहालय और अथवा पुस्तकालय आठ अवसरों पर पूरे दिन के लिए तथा दस अवसरों पर दिन में थोड़े-थोड़े समय के लिए बंद रहे।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक संभव हो सके, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं का, जब तक कि अपरिहार्य न हो, बाह्य एजेंसियों द्वारा प्रयोग न करने दिया जाए।

चीनी का आयात

2356. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

श्री राम टहल चौधरी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान चीनी का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और यह खरीद किस दर पर की गई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गत वर्ष अर्थात् 1991-92 के दौरान चीनी का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना-दो के लिए विदेशी सहायता

2357. **श्री बीर सिंह महतो** :

श्री चित्त बसु :

श्री यशवन्तराव पाटील : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण-दो के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों ने गंगा कार्य योजना चरण-दो के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 17.77 बिलियन येन (401 करोड़ रुपए के बराबर) की जापान सरकार की सहायता के लिए वचनबद्धता की गई है।

(ग) से (ङ) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्य घटकों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से स्कीमें तैयार की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का भण्डार

2358. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रत्येक वर्ष औसतन कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की आवश्यकता होती है; और

(ख) फिलहाल केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का कितना भण्डार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन केवल बाजार में उपलब्धा के अनुपूरक होते हैं और इनसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की समस्त मांग को पूरा करने की आशा नहीं की जाती है। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 1992 दौरान के कुल मिलाकर लगभग 9 लाख मीटरी टन चावल और 8 लाख मीटरी टन गेहूं के मासिक आवंटन किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय पूल में 1-11-92 को स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल का कुल स्टाक (अनन्तिम) क्रमशः 40.24 लाख मीटरी टन और 60.02 लाख मीटरी टन है।

[अनुवाद]

बाल रक्षक तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

2359. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **स्वास्थ्य परिवार और कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों में बाल रक्षक तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य-वार किन-किन स्थानों पर इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन से स्थान चुने गये हैं;

(घ) इस कार्यक्रम पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार किन-किन स्थानों को इस परियोजना के अन्तर्गत लाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) 1. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के निम्नलिखित संघटक हैं :—

(क) रोग प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा और रोग निरोधन के चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(ख) दाईयों को प्रति प्रसव बढ़ी हुई 10.00 रुपये की रिपोर्टिंग फीस देकर सामुदायिक स्तर पर मातृत्व परिचर्या में सुधार करना और गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट देना;

(ग) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का चरणवार ढंग से विस्तार करना; और

(घ) उच्च शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, और सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना तथापि, प्रदर्शन प्रयोजनों के वर्ष 1992-93 के प्रथम वर्ष में कर्नाटक के चिकमगलूर जिले को शामिल कर लिया गया है।

2. जहां सामुदायिक स्तर पर व्यापक रोग प्रतिपक्षण कार्यक्रम मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा, रोग निरोधन योजनायें और अनिवार्य मातृत्व परिचर्या को कर्नाटक के जिलों सहित देश के सभी जिलों में पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है, वहां 1992-93 में 51 जिलों से शुरू करके तीव्र श्वसनीय संक्रमण संघटक का चरणवार ढंग से विस्तार किया जायेगा। इसी प्रकार, उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने का कार्य, जो प्रथमतः उच्च शिशु मृत्यु दर वाले 6 राज्यों के जिलों तक सीमित किया गया है, को 1992-93 में 21 जिलों जिससे कर्नाटक का चिकमगलूर जिला भी शामिल है, में शुरू करके चरणवार ढंग से चलाया जायेगा।

3. तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 51 जिलों और उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए 21 जिलों की सूची क्रमशः विवरण-I और-II में दी गई है।

4. 1992-93 के दौरान इस परियोजना के विभिन्न संघटकों के कार्यान्ययन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नगद सहायता के रूप में 2654.45 लाख रुपये का कुल परिव्यय निश्चित किया गया है जिसमें से 1760.71 लाख रुपये पहले ही रिलीज किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों के लिये वैक्सीनों, कोल्ड उपकरण, लौह और फॉलिक एसिड की गोलियां, विटामिन "ए" घोल और मुखीय पुनर्जलपूर्ति नमक के पैकेट और 51 जिलों के लिये औषध किटें भी सामग्री सहायता के रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई है।

विवरण-I

1992-93 के दौरान तीव्र श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए 51 जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश	निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक
असम	कामरूप, नौगांव

बिहार	पटना, औरंगाबाद, गया, सारण
गुजरात	वडोदरा, जामनगर
हरियाणा	अंबाला, रोहतक, यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, मंडी
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण) चिकमगलूर
केरल	अल्लाप्पूजा, मल्लापुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल, रायसेन, विदिशा, धार, छिंदवाड़ा. सियोनी
महाराष्ट्र	नागपुर, यावतमाल
उड़ीसा	गंजम, सम्बलपुर, क्योंझर
पंजाब	होशियारपुर, रोपड़, फरीदकोट
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा
तमिलनाडु	उत्तरी अरकाट, तिरुनेलवेल्ली, धर्मापुरी, रामनाथपुरम
उत्तर प्रदेश	वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, बाराबंकी
पश्चिम बंगाल	हावड़ा, फलकत्ता, 24 परगना जिला

विवरण II

1992-93 के दौरान उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए 21 जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
बिहार	गया, सारण
कर्नाटक	चिकमगलूर
मध्य प्रदेश	रायसेन, छिंदवाड़ा, सियोनी
उड़ीसा	गंजम, सम्बलपुर, क्योंझर
राजस्थान	जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा
तमिलनाडु	नार्थ अरकाट, तिरुनेलवेली
उत्तर प्रदेश	वाराणसी, गाजीपुर, बाराबंकी
पश्चिम बंगाल	24 परगना जिला

[हिन्दी]

शेगांव स्टेशन की बिल्डिंग

2360. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के बुलदाना जिले में शेगांव रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी और इस प्रस्ताव को कब तक अनुमति मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्टेशन की मौजूदा इमारत और यहां पर मुहैया कराई गयी अन्य सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं ।

[अनुवाद]

हावड़ा तथा खड़गपुर के मध्य अतिरिक्त लाइन

2361. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा और खड़गपुर के बीच एक अन्य रेल लाइन बिछाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संतरागाछि (हावड़ा के निकट) से खड़गपुर तक अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने के लिए हाल में ही एक सर्वेक्षण किया गया है । हम सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं । आगामी निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों और आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जले हुए व्यक्तियों का उपचार

2362. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में जलने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) जले हुए व्यक्तियों का उपचार करने के लिए अस्पतालों के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जले हुए व्यक्तियों का इलाज करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में विशेष उपचार केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों द्वारा जले हुए रोगियों की सूचित की गई संख्या 3274 है। जले हुए रोगियों का उपचार करने के लिए दिल्ली के बड़े अस्पतालों में पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां कहीं भी आवश्यक होता है अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। जले हुए रोगियों के वार्डों को भी चरणबद्ध तरीके से वातानुकूलित किया जा रहा है। द्वितीय संक्रमणों के नियंत्रण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पति/पत्नियों की तैनाती

2363. **श्री वी० धनंजय कुमार** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही स्थान पर पति/पत्नि की तैनाती के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली में इन मार्गनिर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु विदेशी सहायता

2364. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्यक्रमानुसार कार्य प्रगति पर है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विदेशी सहायता से कार्यान्तित किए जा रहे कार्यक्रमों का जिलावार ब्यौरा और उनकी कार्यान्वयन संबंधी प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विदेशी सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विदेशी सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :—

क्षेत्रीय परियोजना :

दो अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में 6-4-1990 से 5 वर्षों की अवधि के लिए एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना (आई० पी० पी०-VI) कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए परियोजना लागत 110.54 करोड़ रुपये है जिसमें सम्पूर्ण राज्य को शामिल किया गया है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, जन्म दर और मातृ तथा शिशु मृत्यु दर और रुग्णता दर में कमी करने के लिए चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना।

राज्य में परियोजना के अधीन हो रही प्रगति, जो शुरू में धीमी थी, अब तेज हो गई है। राज्य में परियोजना कार्यकलापों की प्रगति का अनुवीक्षण मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठकों में भाग लेकर और मंत्रालय में पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन करके किया जा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन के आड़े आ रही समस्याएं उपयुक्त स्तरों पर राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र :

पुरुष और महिला बन्ध्यीकरण की गुणवत्ता और जरूरतमंद दम्पतियों को सूक्ष्म शल्य चिकित्सीय तकनीकों द्वारा रिकेनेलाइजेशन सुविधाएं प्रदान करने में चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि की वित्तीय सहायता से एक सूक्ष्म शल्य चिकित्सीय रिकेनेलाइजेशन केन्द्र (उत्कृष्टता केन्द्र) खोला जा

रहा है। कोर-अधिकारियों अर्थात् एक स्त्री रोग विज्ञानी और शल्य चिकित्सक को पहले ही उक्त तकनीक में प्रशिक्षित कर दिया गया है। कालेज को सूक्ष्म शल्य चिकित्सीय उपकरण सप्लाई कर दिए गए हैं। केन्द्र द्वारा शीघ्र ही कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है।

सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण योजना :

निर्धारित दौरे करके, प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, समुदाय की सहभागिता और अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करके प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति में सुधार करने के लिए 211.45 लाख रुपये के परिव्यय के साथ नवम्बर, 1987 से संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से एक सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन क्रमिक रूप से अब तक निम्नलिखित 17 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है :—

चरण-I	चरण-II	चरण-III
लखनऊ	सीतापुर	ललितपुर, बस्ती
हरदोई	रायबरेली	सुलतानपुर, मुरादाबाद
उन्नाव	लखीमपुर खेरी	अलीगढ़
	मेरठ	बदायूं
	सहारनपुर	गोंडा
	बुलन्दशहर	रामपुर

इस योजना के अधीन प्रगति धीमी है। राज्य द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को धन का भुगतान करने में देरी करना, भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को नियमित आधार पर छात्र-वृत्तियों का भुगतान न करना, इस योजना के धीमे कार्यान्वयन के मुख्य कारण हैं। इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों में राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों में इस योजना का अनुवीक्षण करना, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें बुलाना तथा केन्द्रीय दलों द्वारा दौरे करना आदि शामिल हैं।

लिंक महिला योजना :

1992-93 में उत्तर प्रदेश के उन दस पिछड़े जिलों में जिनकी अस्थायी जन्मदर 39 प्रति हजार और इससे अवधि (1981 की जनगणना) है, 4.10 लाख रुपये के परिव्यय के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय सहायता से एक योजना शुरू की गई हैं ताकि महिलाओं की भागीदारी से परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाया जा सके :—

1. बिजनौर
2. बांदा
3. जौनपुर
4. टीहरी गढ़वाल

5. आगरा
6. गाजियाबाद
7. गोरखपुर
8. आजमगढ़
9. प्रतापगढ़
10. देवरिया

ग्राम में 20 पात्र दम्पत्तियों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने और उन्हें छोटे परिवार का आदर्श अपनाने की प्रेरणा देने हेतु एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए एक सम्पर्क महिला का निर्धारण किया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत किए गए खर्च के बारे में अब तक कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

शिशु संरक्षण और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम :

विश्व बैंक और युनिसेफ की वित्तीय सहायता से 8वीं योजनावधि के लिए 853.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत वाला एक शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992-93 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से नवजात, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है :—

(क) चलाये जा रहे रोग प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्ति, चिकित्सा और रोग-निरोधक कार्यक्रमों को जारी रखना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(ख) परम्परागत धात्रियों को प्रति रोगी 10 रुपये की अतिरिक्त रिपोर्टिंग फीस प्रदान करके और गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट प्रदान करके सामुदायिक स्तर पर मातृ परिचर्या में सुधार करना;

(ग) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तीव्र श्वसनी संक्रमण नियन्त्रण कार्यक्रम का चरणवार तरीके से वितार; और

(घ) असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि उच्च शिशु-मृत्यु दर वाले राज्यों के उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

जहां व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, मुख पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा, रोग निरोधन स्कीमें और आवश्यक मातृ परिचर्या सामुदायिक स्तर पर देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वहां तीव्र श्वसनी संक्रमण घटक का वर्ष 1992-93 में 51 जिलों में प्रारम्भ करके चरणवार तरीके से विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, जोकि प्रथम चरण में उच्च शिशु मृत्यु दर वाले छह राज्यों के जिलों तक सीमित हैं, भी 1992-93 में 21 जिलों से प्रारम्भ करके चरणवार तरीके से बढ़ाा जायएगा।

वर्ष 1992-93 में तीव्र श्वसनी संक्रमण संबंधी कार्यकलापों में उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को शामिल किया गया है, वे हैं : बाराबंकी, गाजीपुर, लखनऊ, मिरजापुर और वाराणसी। इनमें से तीन, अर्थात्—बाराबंकी, गाजीपुर और वाराणसी को चालू वर्ष में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलाप अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

बीड़ी कर्मचारी योजना :

उत्तर प्रदेश और अन्य तीन राज्यों में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि (यू० एन० एफ० पी० ए०) की वित्तीय सहायता से बीड़ी कर्मचारियों के लिए एक परियोजना 1-7-1991 से 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की लागत 188.00 लाख रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों/जिलों को कवर किया गया है :—

1. गाजीपुर
2. सुल्तानपुर
3. वाराणसी
4. इलाहाबाद
5. रायबरेली
6. मिरजापुर
7. रामपुर
8. अमरोहा
9. गुरूशियानगंज
10. जौनपुर
11. झांसी

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों के बीड़ी कर्मचारियों में दम्पती सुरक्षा दर में सुधार लाना तथा बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि के अन्तर्गत अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से प्रभावकारी तरीके से परिवार कल्याण शिक्षा, परिवार नियोजन और मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना की प्रगति की हाल ही में समीक्षा की गई थी और इसे सन्तोषप्रद पाया गया।

उप-जिला स्तर पर अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम :

जिला स्तर पर एक अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम, जोकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक घटक है, नार्वे की रायल सरकार द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता से पूरे देश

में कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य मे 147 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन स्वास्थ्य (पी० वी० ओ० एच-II) योजना :

यह योजना 31-8-87 से संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कुल सहायता 10 मिलियन डालर है। यह परियोजना 30-9-1997 तक जारी रहनी है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राइवेट तथा स्वैच्छिक सेक्टर को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा पोषण सेवाओं में सुधार लाकर ग्रामीण तथा निर्धन लोगों में रुग्णता, मृत्यु तथा प्रजननता दरों में कमी लाना है। उत्तर प्रदेश में ये परियोजनाएं निम्नलिखित तीन स्वैच्छिक संगठनों के लिए मंजूर की गई हैं :

क्रम सं०	संगठन/परियोजना का नाम	प्रतिबद्ध अनुदान (रुपये)	दिया गया अनुदान (रुपये)
1.	नौशिल स्वास्थ्य और विकास एकीकृत ग्रामीण परियोजना	59,78,075	18,28,250
2.	जनहितकारी चिकित्सालय, कानपुर	33,78,690	10,22,545
3.	कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल इलाहाबाद	46,19,330	15,19,220

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण परियोजना :

यू० एस० एड सहायता प्राप्त "परिवार नियोजन संचार एवं विपणन" परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को उनकी अनुसंधान क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुदृढ़ करने संबंधी एक घटक है। इस परियोजना के एक अंग के रूप में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चुनिंदा परामर्शी संगठनों और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को शामिल करके समन्वयक एजेन्सी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई के साथ किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण चरणवार ढंग से किया जा रहा है। चरण-II के अन्तर्गत, जो चालू चरण है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां फील्ड कार्य सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में चल रहा है। इस सर्वेक्षण के जनवरी, 1993 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। इस सर्वेक्षण में सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, मऊ, हमीरपुर, सोनभद्र तथा उत्तरकाशी नामक छह जिलों को छोड़कर पूरा राज्य शामिल है।

परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नव-परिवर्तन :

उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों की अवधि में यू० एस० एड से कुल 325 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए दिनांक 30-9-1992 को आर्थिक कार्य विभाग और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं :—

इस परियोजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(क) गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन को बढ़ावा देकर सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में सेवा परिदान का विस्तार करके परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करना।

(ख) गर्भ निरोधक तरीकों की पसन्दगी का विस्तार कर एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण और उनके कौशलों का उन्नयन करके उनकी तकनीकी क्षमता में सुधार करके परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(ग) अग्रणी समूहों में सहायता को बढ़ा कर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना तथा परिवार नियोजन के लाभों से जनता को अवगत कराना।

उम्मीद है कि परियोजना अवधि के अंत में उत्तर प्रदेश की कुल प्रजननता दर 5.4 से घटकर 4 हो जाएगी तथा दम्पत्ति सुरक्षा दर 35% से बढ़कर 50% हो जाएगी। परियोजना के कार्यकलापों के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

[अनुवाद]

दक्षिण में अतिरिक्त गोदामों का निर्माण

2365. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारण प्रयोजन हेतु दक्षिण में अतिरिक्त गोदामों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औंडिहार-छपरा रेल लाइन को बदलना

2366. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने अन्दीहार-छपरा के बीच की मीटर गेज लाइन को परिवर्तित करने के कार्य को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गेज परिवर्तन कार्य को रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवश्यक उपस्करों आदि को अन्दीहार-छपरा रेल लाइन से वाराणसी-इलाहाबाद रेल लाइन पर भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण

2367. **श्री सूर्य नारायण यादव** :

श्री सदीपान भगवान थोरात : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1992 तक अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस क्षेत्र में सितम्बर, 1992 तक राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सितम्बर, 1992 तक मंजूर किए गए प्रस्तावों के संबंध में देश में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए कुल अपेक्षित भूमि 3.67 लाख हैक्टेयर थी। सितम्बर, 1992 तक 1.39 लाख हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण किया जा चुका है। राज्य-वार निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सितम्बर, 1992 तक किए जाने वाले और वास्तविक रूप से किए गए प्रतिपूरक वनरोपण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सितम्बर, 1992 तक के लिए निर्धारित प्रतिपूरक वनरोपण (हैक्टेयर)	सितम्बर, 1992 तक किया गया प्रतिपूरक वनरोपण (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13030	4706
2.	अरुणाचल प्रदेश	873	300
3.	असम	1213	554

1	2	3	4
4.	बिहार	1518	60
5.	गोवा	93	93
6.	गुजरात	19304	9888
7.	हरियाणा	519	507
8.	हिमाचल प्रदेश	5107	2282
9.	जम्मू और कश्मीर	1425	288
10.	कर्नाटक	9014	9515
11.	केरल	701	108
12.	मध्य प्रदेश	228247	64104
13.	महाराष्ट्र	39693	23306
14.	मणिपुर	नगण्य	—
15.	मेघालय	245	270
16.	उड़ीसा	20180	12157
17.	पंजाब	80	136
18.	राजस्थान	4018	985
19.	सिक्किम	213	596
20.	तमिलनाडु	850	333
21.	त्रिपुरा	219	219
22.	उत्तर प्रदेश	14209	5682
23.	पश्चिम बंगाल	4359	604
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1990	2046
25.	दादर और नगर हवेली	262	262
26.	दमण एवं दियू	—	—
	कुल :	363762	139001

गैर-सरकारी क्षेत्र में कैंसर अस्पताल

2368. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे कैंसर अस्पतालों की, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में कैंसर अस्पताल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कैंसर मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए कैंसर अस्पताल स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में कैंसर अस्पतालों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यद्यपि मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर में कैंसर अस्पताल खोलने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करता है लेकिन गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप चलाने एवं कैंसर का शुरू में पता लगाने तथा कोबाल्ट थेरेपी यूनिटें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वैच्छिक/प्राइवेट सेक्टर में कैंसर अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	4
4.	कर्नाटक	3
5.	केरल	1

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	महाराष्ट्र	8
8.	पंजाब	1
9.	तमिलनाडु	7
10.	उत्तर प्रदेश	3
11.	पश्चिम बंगाल	1

जीवाश्म द्वारा एड्स का इलाज

2369. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री श्रीनिवासन :

डा० राजगोपालन श्रीधरन् : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 5 मई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9006 के संबंध में दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवाश्म द्वारा एड्स के इलाज के संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या किसी चिकित्सा पद्धति में एड्स के इलाज के लिए दवा की खोज की जानकारी सरकार को है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा उठाये गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार द्वारा एकत्रित की गई सूचना से विदित होता है कि हार्स-शू क्रैब के रक्त का प्रयोग करके विश्व में कोई वैक्सीन विकसित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक चिकित्सकों द्वारा किए गए कुछ दावों से परिचित है।

(ङ) ऐसी औषधी के प्रभाव तथा समय-समय पर किए गए दावों की जांच करने के लिए किए जा रहे अध्ययन कार्य में भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद सहायता कर रहा है।

हावड़ा-हाल्दिया खंड पर अतिरिक्त रेल सेवा

2370. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री सुबन्धु खां :

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल्दिया के औद्योगिक और वाणिज्यिक विस्तार के कारण हावड़ा-हाल्दिया रेल-लाइन पर यात्री और माल आवागमन में कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या इस खंड पर अतिरिक्त यात्री/मालगाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कुछ वर्षों में हल्दिया पोर्ट पर माल यातायात की गतिविधि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस खंड पर वहन किए जाने वाले मुख्य पण्य हैं। दक्षिण भारत में ताप बिजलीघरों और उद्योगों के लिए कोयला, इस्पात संयंत्रों के लिए आयातित कोयला और कच्चा माल, आयातित उर्वरक तथा पेट्रोलियम उत्पाद। हल्दिया पोर्ट तक माल लाने और वहां से ले जाने के लिए इस खंड पर पर्याप्त संख्या में मालगाड़ियां चल रही हैं। बहरहाल, वहां यात्री यातायात में कोई सुस्पष्ट वृद्धि नहीं हुई है।

एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव

2371. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में महानगरों के सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के संगठनों में एड्स पीड़ित कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने संबंधी भेदभाव करने का मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों की जांच के लिए और सरकार को इस संबंध में परामर्श देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

महिलाओं के लिए आयु-सीमा में छूट

2372. **श्री के० वी० तंगकाबालू** :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए सरकारी पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन जैसी तकनीकी सेवाओं के वास्ते ऊपरी आयु-सीमा को बढ़ाकर 35 वर्ष तक की कर देने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसी छूट सरकारी विद्यालयों में नौकरी के लिए भी उपलब्ध है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भोपाल और रामगंज मंडी के बीच रेल लाइन

2373. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल और रामगंज मंडी के बीच रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या परियोजना को मंजूरी मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन कारणों से परियोजना को अव्यवहारिक पाया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतिफल की ऋणात्मक दर।

[**हिन्दी**]

लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे

2374. **श्री मनफूल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी और तीव्र गति की रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के साधारण सवारी डिब्बों की संख्या अन्य सवारी डिब्बों की तुलना में कम है;

(ख) क्या सरकार का विचार जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सवारी डिब्बों की संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिकांश लम्बी दूरी की गाड़ियों में आरक्षित स्थान पाने के लिए यात्रियों की लम्बी प्रतीक्षा सूची को मद्देनजर रखते हुए रेल इंजनों की वर्तमान कर्षण क्षमता के भीतर दूसरे दर्जे के साधारण डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में रुग्ण चीनी मिलें

2375. **श्री खेलन राम जांगड़े : क्या खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और उनमें से रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन रुग्ण मिलों के पुनः चलाये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनमें से अब तक कितने मिलों को पुनः चलाया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में 8 संस्थापित चीनी मिलें हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेज दिया जाता है। इन उपबंधों का विस्तार करके सरकारी कंपनियों को भी इसमें कवर कर लिया गया है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश से रुग्ण चीनी मिल का एक मामला (जीवाजी राव शुगर कंपनी लि०) उन्हें प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के बारे में फिलहाल खाद्य मंत्रालय में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। रुग्ण चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदित करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

(ङ) बी० आई० एफ० आर० ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के उपबंधों के तहत उक्त चीनी मिल को बंद करने की सिफारिश की है।

डीलक्स रेलगाड़ी को गया होकर चलाना

2376. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कलकत्ता के बीच चलने वाली दैनिक डीलक्स रेलगाड़ी को गया होकर चलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

नर्सिंग महाविद्यालय

2377. **प्रो० के० वी० थॉमस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार नर्सिंग महाविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसे नर्सिंग महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं की है; और

(घ) देश में प्रशिक्षित नर्सों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कुछ और नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) नर्सों को प्रशिक्षण देने का दायित्व अलग-अलग राज्यों का है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार ने और अधिक नर्सिंग स्कूलों की स्थापना करने में राज्यों की सहायता करने का निश्चय किया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	नर्सिंग कालेजों की संख्या	प्राइवेट नर्सिंग कालेजों की सं०	अमान्यताप्राप्त नर्सिंग कालेज
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	—	2
2.	बिहार	1	—	1
3.	असम	1	—	1
4.	गुजरात	1	—	—
5.	केरल	3	—	2
6.	कर्नाटक	3	—	3
7.	मध्य प्रदेश	1	—	—

1	2	3	4	5
8.	महाराष्ट्र	4	1	1
9.	पंजाब	1	—	—
10.	चण्डीगढ़	1	—	—
11.	राजस्थान	1	—	—
12.	उड़ीसा	1	—	1
13.	तमिलनाडु	6	3	4
14.	उत्तर प्रदेश	1	—	1
15.	दिल्ली	2	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	1	—	—
	योग :	31	4	16

रेलवे स्टेशनों पर संचार सुविधाएं

2378. **श्री जितेन्द्रनाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर दूर-संसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जोनवार इस प्रयोजनार्थ अब तक किन-किन स्टेशनों का चयन किया गया है; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है तथा निकट भविष्य में इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिए 1976 स्टेशनों पर डी० ओ० टी० टेलीफोन, 1061 स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और 168 स्टेशनों पर गाड़ी सूचना प्रदर्शन बोर्डों की व्यवस्था की गई है।

(ग) जहां कहीं संभव हो डी० ओ० टी० टेलीफोन जैसी दूर-संचार सुविधाओं और जन-उद्घोषणा प्रणाली की उत्तरोत्तर व्यवस्था किए जाने की योजना है। निकट भविष्य में इस प्रयोजन के लिए जिन स्टेशनों को चुने जाने की संभावना है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन स्टेशनों की सूची जिन्हें डी० ओ० टी० टेलीफोन लगाने की व्यवस्था के लिए चुने जाने की संभावना है ।

1. कुंकावाव
2. सैंड हर्स्ट रोड
3. चिंच पोकली
4. करी रोड
5. परेल
6. विद्या विहार
7. कूंजर मार्ग
8. कलवा
9. मम्बरा
10. दीवा
11. ठाकुर्ली
12. बदलापुर
13. बंगानी
14. शेलू
15. भिवपुरी
16. केसर वाडी
17. खंडाला
18. बेगड़ावाडी
19. मलाबली
20. कमशेट
21. घोरावाडी
22. अकुर्डी
23. पिंपरी
24. दापोडी
25. आप्ता
26. तलेजा-पंचसनद
27. निलजी
28. खरबो
29. कमान
30. अम्बीवली
31. टिटवाला
32. खडावली
33. वासिंद
34. अटगांव
35. खरडी
36. उमवेरमली
37. कसारा
38. डाकयार्ड रोड
39. रे रोड
40. काटन ग्रीन
41. सेवड़ी
42. बडांला रोड
43. गुरू तेग बहादुर नगर
44. चूना भट्टी
45. गोवांडी
46. सलामतपुर
47. बरेठ
48. मेहोल
49. गणेशगंज
50. जेरुवाखेडा
51. वर्गवान
52. सलहाना
53. मेहगांव
54. ननवाड़ा

55. जुकेही
56. हरदुआ
57. अमदारा
58. भेराघाट
59. जखलौं
60. तालभाट
61. बबीना
62. बिरला नगर
63. राजाकी-मण्डी
64. फराह
65. बाद
66. फरीदाबाद न्यू टाउन
67. कजगांव
68. जमनेर
69. महासाबाद
70. काटेपूरना
71. कुरूम
72. माना
73. तकली
74. वचाडा
75. बिलोच पुरा
76. मुराराय
77. नगरंतारी
78. गहमार
79. नरीमगारु
80. देवनीगल
81. सवानर
82. नल्लीलम
83. अलाक्कुडी
84. दरसुराम
85 कटूर
86. कोरादाचेरी
87. नरसिंहमपेट
88. पादानासम
89. सेंदूराय
90. तिरूनागास्वरम
91. माथुर
92. तिरूविदाईमारुदूर
93. उदगमंडलम
94. ऐदावाई
95. मंदामारी
96. रोचनी
97. रेपाल्लीवाडा
98. कारेपल्ली
99. पनगांव
100. पेंडियाल
101. पेड्डापेट
102. नाईगांव
103. नालासोपारा
104. वैतरणा
105. सफाले
106. केलवे रोड
107. काराम्बेली
108. सचिन
109. चलथान
110. किकाकुई रोड

111. भड़भूजा
112. कोलडे
113. टकरखेडा
114. पालधी
115. कंझ
116. नारंजीपुर
117. बजरंगगढ़
118. पंचपिवलिया
119. अमरगढ़
120. रावटी
121. जेकोट
122. मंगलमहूदी
123. उसरा
124. रांतिया
125. धामेरडा
126. बोरडो
127. विक्रमनगर
128. भैरोंगढ़
129. ओंकारेश्वर
130. हरकैंखोल
131. कालकुंड
132. मोखामौरा
133. मराज्याखेरी
134. पातालपानी
135. ताजपुर
136. नईखेरी
137. करछा
138. सरेरी
139. सुनैना
140. हदुण्डी
141. मंदपिया
142. कचनारा
143. कचनारा रोड
144. सोंगारी
145. सिंगवाल
146. ओरडी
147. झरवासा
148. धुबाला
149. सिंदपान
150. लम्बिया
151. देत
152. गंभीरी रोड
153. सरमुजा रोड
154. श्री अमीरगढ़
155. अदेसर
156. देबाड़ी
157. शिरवा
158. अरनिया
159. कोलवाग्राम
160. हरसौली
161. अजेरका
162. परीसल
163. बस्सी
164. कनौता

165. चाकसू
166. दंतिया
167. चौथ-का-बरवारा
168. खोरी
169. कुंड
170. निजामपुर
171. मावन्दा
172. कांवट
173. नुवा
174. पलसाना
175. बिस्साऊ
176. इंदलोड मुकंदगढ़
177. रनोली शिशु
178. चिरवा
179. कनालुस
180. वादनगर
181. नरोदा
182. सवनी
183. भावनगर टर्मिनस
184. गांधीग्राम

भारती रेलों पर उन स्टेशनों की सूची जिन्हें जन-उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था के लिए चुने जाने की संभावना है ।

1. भरथना
2. शिकोहाबाद
3. फिरोजाबाद
4. हाथरस
5. शकूरबस्ती
6. सांपला
7. बहादुरगढ़
8. राजपुरा
9. सिरहंद
10. अबोहर
11. संगरूर
12. पालीमारवाड़
13. नागोर
14. मालाखेड़
15. सुजानगढ़
16. लूनी
17. सिरसा
18. गढ़ीहस्सारू
19. विजयनगर
20. अनूपगढ़
21. महेंद्रगढ़
22. लोहारू
23. पटौदी रोड
24. सदर बाजार

25. गदाधरपुर
26. बतासपुर
27. बनपास
28. कोपाई
29. पिवकुरीघाल
30. नवादरघाल
31. मुराराय
32. लोकनाथ
33. छतरा
34. नसीबपुर
35. आगराद्वीप
36. दुमुरदाहा
37. बेहुला
38. बगनापाड़ा
39. कोटालपुकुर
40. गुमनी
41. बंसलाई ब्रिज
42. नगरनबी
43. तिलभिता
44. तेन्या
45. लक्ष्मीपुर
46. मंडानटिकुड़ी
47. बेलारहाट
48. गलसी
49. पराज
50. राजबंध
51. कालीपहाड़ी
52. बाराचक
53. कुलटी
54. मुगमा
55. कार्लूबाथान
56. छोटा-अम्बाना
57. रुपनारायणपुर
58. मांकड़
59. वारियां
60. कुमारधुबी
61. जमतारा
62. विद्यानगर
63. गिरीडीह
64. कजोराग्राम
65. उखरा
66. पंडावसर
67. दुवराजपुर
68. सुरी
69. थापरनगर
70. सालनपुर
71. मदनराथा
72. मथुरापुर
73. संकरपुर
74. कुमराबाद
75. लहाबोन
76. जगदीशपुर
77. महेशमुण्डा
78. सिधूली
79. भीमगढ़
80. पंचरा

81. चिनपाल
82. कुनूरी
83. बारिस अलीगंज
84. बनाही
85. सकलडीहा
86. सेमारलिया
87. रघुनाथपुर
88. राजेंद्र नगर
89. नदवान
90. पहाड़पुर
91. नोमिया
92. मांड्या
93. यशवंतपुर
94. हिंदूपुर
95. कोकराझार
96. भालूका रोड
97. ओल्ड मालदा
98. बेल्लमपल्ली
99. तंडूर
100. भीमावरम टाउन
101. अन्नावरम
102. यादगीर

दक्षिण-पूर्व रेलवे में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

2379. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ब्यारा क्या है; और

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में निकट भविष्य में ऐसी कितनी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा (द० पू० रेलवे) में स्थित दो अस्पतालों, 22 स्वास्थ्य यूनिटों तथा 2 लाकअप डिस्पेंसरियों के माध्यम से रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को मुफ्त रेल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

अस्पताल

1. खोरधा रोड।

2. बोंडामुण्डा।

स्वास्थ्य यूनिट

1. बालासौर, 2. बोलंगीर, 3. झारसुगुडा, 4. बोंडामुण्डा (लोको), 5. बिमलगढ़, 6. राउरकेला, 7. बानो 8. टिटलागढ़, 5. रायगडा, 10. लक्ष्मीपुर, 11. जगदलपुर, 12. कोरापुट, 13. काटाबांजी, 14. पुरी, 16. कटक 16. ब्रह्मपुर, 17. रेतंग कालोनी, 18. तालचेर, 19. बाचेली, 20. मंचेश्वर 21. पाराद्वीप और 22. खोरदा रोड (लोको कालोनी)।

लॉक अप डिस्पेंसरियां

1. संबलपुर ।

2. बारीपाड़ा ।

(ख) (i) मंचेश्वर में स्वीकृत 50 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है और इस वर्ष के अन्त तक यह उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा ।

(ii) शहडोल में एक अस्पताल जल्दी ही चालू किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

गेहूं के आयात के लिए शिष्टमंडल

2380. **श्री नीतीश कुमार** :

डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई शिष्टमंडल गेहूं के आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशों को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह शिष्टमंडल कब भेजा गया था और इनके द्वारा किन-किन देशों का दौरा किया गया; और

(ग) शिष्टमंडल के दौरे पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पहला शिष्टमण्डल 26-1-1992 से 25-2-1992 तक विदेश भेजा गया था और वे बेल्जियम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे । दूसरा शिष्टमंडल 28-9-1992 से 8-10-1992 तक विदेश भेजा गया था और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था । शिष्टमंडल द्वारा किए गए इन दोनों दौरों पर अनुमानित खर्च 8.24 लाख रुपये हुआ था ।

[अनुवाद]

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में वन्य पशु

2381. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में बाघों, चीतों तथा अन्य प्रमुख प्रजातियों के पशुओं की कुल संख्या कितनी हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : 1992 की गणना के अनुसार सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघों, तेंदुओं और अन्य प्रमुख पशु प्रजातियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :

1. बाघ	—	22
2. तेंदुआ	—	34

3. केराकल	—	15
4. जंगली बिल्ली	—	140+
5. मुश्कबिलाव बिल्ली	—	24+
6. सांभर	—	4500+
7. चीतल	—	2500+
8. नीलगाय	—	4100+
9. चौसिंगा	—	54
10. चिंकारा	—	20+
11. जंगली सुअर	—	2500+
12. धारीदार लकड़बग्गा	—	100+
13. गीदड़	—	170+
14. रेसस मैकाक (बन्दर)	—	2100+
15. लंगूर	—	5000+

पोस्ट-यू०एन०सी०ई०डी० अनुसरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ बैठक

2382. **श्री रवि राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पोस्ट-यू० एन० सी० ई० डी० अनुसरण के लिए गैर-सरकारी संगठनो के साथ हाल ही में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के लिए आमंत्रित संगठन कौन से हैं; और

(ग) उक्त बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए तैयारियों के दौरान और पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की अवधि के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य विशेषज्ञों के साथ नियमित आधार पर चर्चाएं की गई। ये चर्चाएं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही किस्म की थी और इनमें रियो सम्मेलन के निष्कर्षों अर्थात् एजेण्डा-21, वानिकी संबंधी कानूनी रूप से अवाध्यकर सिद्धान्त, रियो घोषणा तथा जैवीय विविधता व जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशन

2383. **श्री प्रबीन डेका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कितने रेलवे स्टेशन विकसित किए गए; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में और अधिक स्टेशनों का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्टेशनों पर विकास संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं, उनकी वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष		स्टेशनों की संख्या
1989-90	—	63
1990-91	—	64
1991-92	—	187

निर्माण कार्यों तथा इन पर किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) गुवाहाटी में 40 लाख रुपये की लागत पर आरक्षण एवं बुकिंग परिसर (1991-92)।

(ii) दिनहट्टा, दामचाड़ा, दाओतुहाजा, बागेटार, बांदराखल, कालाचांद, मूपा, लोअर हाफलोंग, जातिंगा, मिग्रेंडिसा, वारेगंडिसा, फिडिंग में 7.58 करोड़ रुपये की लागत पर लूप का विस्तार तथा अतिरिक्त लूप की व्यवस्था करना (1989-90, 1990-91, 1991-92)।

(iii) बैंहाटा, चापराकोटा, धूपगढ़ी में 2.34 करोड़ रुपये की लागत पर रेक सम्हलाई सुविधाएं (1991-91 और 1991-92)।

(iv) 2.92 लाख रुपये की लागत पर 51 स्टेशनों पर विविध यात्री सुविधा कार्य (1989-90)।

(v) 5.13 लाख रुपये की लागत पर 49 स्टेशनों पर विविध यात्री सुविधा कार्य, (1989-90)।

(vi) 26.30 लाख रुपये की लागत पर 171 स्टेशनों पर विविध यात्री सुविधा कार्य, (1991-92)।

(ग) जी, हां।

(घ) असम में 1992-93 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख नवीकरण तथा अन्य विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	काम का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	कटिहार—नयी स्टेशन इमारत तथा प्लेटफार्म को जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुल	37.13
2.	कटिहार—नई स्टेशन इमारत के पहुंच मार्ग को चौड़ा करने सहित परिचालन क्षेत्र में सुधार करना	21.00
3.	गुवाहाटी - आरक्षण परिसर के चारों ओर परिचालन क्षेत्र की व्यवस्था करना	15.00
4.	दीमापुर—स्टेशन इमारत को सुन्दर बनाना, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा कक्ष, विश्राम कक्ष आदि का विस्तार करना	15.77
5.	कटिहार—प्लेटफार्म नं० 7 तथा 8 (ब० ला०) के मैस्टिंग के फर्श बिछाने की व्यवस्था	16.23
6.	गुवाहाटी—कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था	97.67
7.	29 स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों में अतिरिक्त क्षेत्र की व्यवस्था	24.71
8.	17 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के छत की व्यवस्था/विस्तार करना	25.64
9.	14 स्टेशनों पर फर्श बिछाने सहित प्लेटफार्म की सतह ऊंची करना	24.32

विदेशी दौरे

2384. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

श्रीमती विभु कुमारी देवी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ-साथ कुछ विदेशी राष्ट्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों की यात्राओं के दौरान इनके साथ विचारित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले 6 महीनों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्री ने ब्राजील, अमेरिका, इंगलैण्ड, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, श्रीलंका और डेनमार्क का दौरा किया। ये दौरे संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की बैठकों सहित विभिन्न बैठकों में भाग लेने और दौरा किए गए देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय आधार पर वार्ताओं के लिए किए गए। इन बैठकों और वार्ताओं के परिणामस्वरूप विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण, पर्यावरण और विकास तथा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बाहरी सहायता को बढ़ावा देना आदि में भारत के अपने प्रयासों को बेहतर समर्थन मिला।

गिद्दलूर के निकट पुल

2385. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1985 में गिद्दलूर के निकट एक रेल पुल का निर्माण करने की घोषणा की थी;

(ख) क्या पंचायत ने निर्माण की 50 प्रतिशत लागत वहन करने की इच्छा व्यक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय और दक्षिण मध्य रेलवे में उपलब्ध रिकार्डों में गिद्दलूर में निचले पुल के निर्माण के संबंध में की गई किसी घोषणा का पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग) पंचायत ने पुल तक पहुंच मार्गों के निर्माण के अपने संकल्प के बारे में रेलवे को अवगत कराया है। बहुत ही कम यातायात होने के कारण केवल निक्षेप शर्तों पर ही पुल के निर्माण के बारे में विचार किया जा सकता है जिसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय में दूसरी पारी

2386. **श्री मुहीराम सैकिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ और केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में उन 9 केन्द्रीय विद्यालयों, जहां अक्तूबर, 1990 में दूसरी पारी शुरू की गई थी, के अलावा 13 और केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी शुरू की गई है। जिन केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी चल रही है, उनकी सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जहां दूसरी पारी के आदेश दिए गए हैं

1. दिल्ली कैन्ट नं० I
2. जनकपुरी
3. टैगोर गार्डन
4. रामकृष्ण पुरम सैक्टर-II
5. रामकृष्ण पुरम सैक्टर-VIII
6. एन्ड्रूज गंज
7. लारेंस रोड
8. झड़ौदा कलां
9. गोल मार्किट
10. जम्मू के 3 केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय नं० 1, 2 तथा 3 (दामन्ना)
11. कंकड़ बाग, पटना
12. मुजफ्फरपुर
13. ए० पी० सी० आर० कालोनी, नई दिल्ली
14. नौएडा
15. भोपाल
16. खैरागढ़
17. नं० 1, 2 और 3 कोलाबा, बम्बई
18. गोमती नगर, लखनऊ

कुल : 22 केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

लखीमपुर-खीरी (उत्तर प्रदेश) के बीच रेल सम्पर्क

2387. **डा० जी० एल० कनोजिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी को कुछ नई रेल लाइनों के साथ जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय योजना

2388. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालय योजना के पिछे क्या उद्देश्य है और इस उद्देश्य को राज्यवार कहां तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) की गई पुनरीक्षा के अनुसार, सामने आई कमियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन में प्रवेश के महत्व को दृष्टि में रखते हुए बनाई गई योजना का सापेक्ष महत्व क्या है;

(घ) क्या सरकार कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों तथा लोगों की बढ़ती हुई अभिलाषाओं तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना में इस योजना का पुनर्निर्धारण करने/इसमें संशोधन करने/इसका विस्तार करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है जिसमें सुदृढ़ संस्कृति की घटक, मूल्यों के बारे में जानकारी कराना, वातावरण संबंधी जागरुकता पैदा कराना और छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, के चहुंमुखी विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है। कुल मिलाकर स्कूलों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है। राज्य-वार कोई समीक्षा नहीं की गई है।

(ग) उच्च अध्ययन के लिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में दाखिले के लिए मानदण्ड, संबंधित विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नवोदय विद्यालय योजना में इस पर कोई महत्व नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) सम्बद्ध राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, नवोदय विद्यालय समिति, देश के सभी जिलों में विद्यालय खोलने की इच्छुक हैं।

मुक्त विश्वविद्यालय

2389. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उन विश्वविद्यालयों/मुक्त विश्वविद्यालयों की उनके नामांकन सहित संख्या क्या है जो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे विश्वविद्यालय कोई गैर-परम्परागत और व्यावसायिक उन्मुख पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न हैं, जिसमें अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों/मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम के साथ-साथ शैक्षिक सत्र 1991-92 के लिए उनका नामांकन दर्शाया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि क्या वे गैर-परम्परागत तथा व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम चला रहे हैं। चूंकि शैक्षिक सत्र 1992-93 अभी भी चल रहा है अतः 1 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार नामांकन की तारीख देना संभव नहीं है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गए गैर-परम्परागत/व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों का ब्यौरा परिशिष्ट XXXI पर वि० अ० आ० की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है जो संसद पुस्तकालय में मौजूद है।

विवरण

नामांकन

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	अवर-स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल	क्या व्यवसायिक/ गैर-परम्परागत पाठ्यक्रम चला रहे हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36075	4639	40714	जी हां
2.	डा०बी०आर० अम्बेडकर मुक्त	28393	1149	29542	जी हां
3.	ककातिया	9832	2305	12137	जी हां
4.	उस्मानिया	2293	5744	8037	जी हां
5.	श्री वेंकेटेश्वर	1213	2229	3442	जी हां

1	2	3	4	5	6
6.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान	—	755	755	
7.	पटना	2159	—	2159	
8.	गुजरात विद्यापीठ	—	168	168	
9.	कुरूक्षेत्र	4656	240	4896	
10.	महर्षि दयानन्द	9135	—	9135	
11.	हिमाचल प्रदेश	1218	18384	19602	
12.	जम्मू	1180	212	1392	
13.	कश्मीर	1339	127	1466	जी हां
14.	बंगलौर	1130	1161	2291	
15	मैसूर	15153	17785	32938	
16.	कालीकट	8072	490	8562	
17.	केरल	1717	3407	5124	
18.	बरकतुल्ला	8050	—	8050	
19.	बम्बई	1973	2892	4865	जी हां
20.	पूना	298	—	298	जी हां
21.	एस०एन०डी०टी० महिला	11176	—	11176	जी हां
22.	तिलक महाविद्यालय	4845	—	4845	
23.	यशवन्तराव चौहान मुक्त	11567	—	11567	जी हां
24.	बरहामपुर	1239	132	1371	
25.	उत्कल	9055		9055	
26.	पंजाब	4229	2460	6689	जी हां
27.	पंजाबी	3190	3896	7086	जी हां
28.	कोटा मुक्त	14129	559	14688	जी हां
29.	अलगप्पा	558	—	558	जी हां
30.	अन्नामलै	52429	53281	105710	जी हां
31.	भरतियार	7040	—	7040	
32.	मद्रास	91140	20399	111539	जी हां

1	2	3	4	5	6
33.	मदुरै कामराज	46475	13504	59979	जी हां
34.	मदर टेरेसा	—	124	124	जी हां
35.	इलाहाबाद	5202	—	5202	
36.	काशी विद्यापीठ	3325	—	3325	
37.	मेरठ	233	—	233	
38.	दिल्ली	52055	2640	54695	
39.	इं० गां० रा० मु० विश्वविद्यालय	52124	10251	62375	जी हां
	कुल जोड़ :	503897	169925	673822	

समविश्वविद्यालय संस्थाएं ।

टिप्पणी : जहां वर्तमान आंकड़े मौजूद नहीं हैं, वहां पिछले वर्ष (1990-91) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है ।

"सोथबाइ" की राष्ट्रीय कला वस्तुओं की नीलामी

2390. **श्री नवल किशोर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सोथबाइ" की राष्ट्रीय कला वस्तुओं की नीलामी से भारतीय विरासत को सुरक्षित रखने तथा तस्करी को हतोत्साहित करने में राष्ट्रीय हितों को कोई सहायता मिली है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में "सोथबाइ" की कला वस्तुओं की नीलामी की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) इस प्रकार की नीलामी के परिणामों का इन विशेष परिस्थितियों में मूल्यांकन करना बहुत जल्दी होगा ।

(ख) और (ग) यह नीलामी पूर्णतः निजी रूप से की गई थी । सरकार द्वारा इस प्रकार की नीलामी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मालेगांव में "आउट एजेंसी"

2391. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव और कुछ अन्य स्थानों में "आउट एजेंसी" खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल

2392. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार लाने हेतु देश में बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(i) आयरन तथा फॉलिक एसिड गोलियों के प्रयोग से गर्भवती महिलाओं के लिए रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए मौजूदा रोग-निरोधन योजना को व्यापक बनाना ।

(ii) महिला परा-चिकित्सीय कार्यकर्ताओं को मिडवाइफरी किट प्रदान करके सामुदायिक स्तर पर प्रसूति परिचर्या में सुधार लाना, परंपरागत दाइयों को प्रति व्यक्ति 10.00 रुपये की बढ़ी हुई रिपोर्टिंग फीस देना और गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल किटें प्रदान करना, (स्वच्छ प्रसव सुनिश्चित करने के लिए प्रसव के दौरान दाइयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली) ।

(iii) सामान्य प्रसव के मामलों तथा उच्च खतरे वाले मामलों को संभालने के लिए चरणवार ढंग से क्रमशः उपकरण तथा प्रशिक्षण के संबंध में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।

(iv) मातृ मृत्यु दर को कम करने, की दृष्टि से कम जनांकिकीय संकेतों वाले 90 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना शुरू किया गया है। इन सुविधाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों से सुसज्जित एक प्रसव कक्ष शामिल है।

अश्व-पाद केकड़े का चोरी छिपे शिकार

2393. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से लगे समुद्र तट पर भारतीय अश्व-पाद केकड़े का चोरी-छिपे अंधाधुंध शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लुप्त प्रायः जीव की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) मुख्य वन्यजीव वार्डन, उड़ीसा ने सूचित किया है कि राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों को अश्व-पाद केकड़े की चोरी-छिपे शिकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाजीपुर से मोतिहारी के लिए रेल लाइन

2394. **श्री शिवशरण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्व रेलवे में हाजीपुर से मोतिहारी के लिए बरास्ता वैशाली, साहिबगंज, केशरिया और अरेराज होकर जाने वाली रेल लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

मद्रास-विल्लुपुरम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2395. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मद्रास से विल्लुपुरम के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास-विल्लुपुरम-त्रिची आमान परिवर्तन परियोजना के मद्रास-ताम्बरम् खंड पर कार्य शुरू हो गया है। 30-11-92 तक कार्य की प्रगति 40% है।

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए अंतरिम योजना नीचे दी गई है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों :—

1. मद्रास-ताम्बरम	—	1992-93
2. ताम्बरम्-चेंगलपट्टू	—	1993-94
3. चेंगलपट्टू-त्रिची	—	1994-95

[अनुवाद]

पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव के बारे में अध्ययन

2396. **श्री अनन्तराव देशमुख** :

श्री मदन लाल खुराना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने मानव शरीर पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में संस्थान द्वारा क्या सुझाव/टिप्पणियां की गई; और

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) जी, हां। इस अध्ययन में यातायात पुलिस-कर्मियों के दो दलों—यातायात नियंत्रण की सक्रिय ड्यूटी कर रहे पुलिस-कर्मियों का एक एक्सपोज्ड दल तथा कार्यालयी पर्यावरण में कार्य करने नियंत्रण दल—के तुलनात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग लगातार चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर दोनों अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इस अध्ययन में सक्रिय ड्यूटी करने वाले यातायात पुलिस-कर्मियों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा का सुझाव दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात पुलिस-कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रदूषण के कु-प्रभावों को यथासंभव कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) कांस्टेबलों और अधिकारियों की चौराहों से कार्यालय स्थलों या खुले क्षेत्रों में तैनाती की एक आवर्तन स्कीम शुरू की गई है।

(2) स्थानीय उद्यमियों को प्रेरित किया गया है कि वे प्रदूषित चौराहों पर ड्यूटी देने वाले यातायात पुलिस-कर्मियों के इस्तेमाल के लिए श्वसन सुरक्षा मास्कों का निर्माण करें। यामायात पुलिस-कर्मियों को ये मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पुलिस-कर्मियों को इस मास्कों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कुप्रभावों के बारे में जन-जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

(4) यातायात पुलिस-कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के साथ दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक सतत अनुसंधान अध्ययन शुरू किया गया है ताकि यातायात कर्मचारियों की जांच और जरूरत पड़ने पर उनका उपचार किया जा सके।

किराये में संशोधन

2397. **श्री चित्त बसु** :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री किराये और माल भाड़े की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनबाद डिवीजन में शिक्षा सुविधाएं

2398. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में "धनबाद डिवीजन के रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के अभिरक्ष्य बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या धनबाद रेलवे मिडिल स्कूल, बारवाडीह (पलामू) को हाई स्कूल करने के लिए कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्कूल का दर्जा कब तक बढ़ा दिया जाएगा और हाई स्कूल की कक्षाओं का अध्यापन कब से शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुख्यतः शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है।

बहरहाल, पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में 2 केन्द्रीय विद्यालयों सहित रेलवे ने जहां तक व्यवहारिक है इन सुविधाओं की व्यवस्था की है ।

(ख) और (ग) इस मामले में रेल प्रशासन के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों का विस्तार

2399. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार हेतु चुने गये विश्वविद्यालयों के, राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 जो 1992 में संशोधित की गई है, में यह कहा है कि संस्थानों में चहुमुखी सुधार की आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में विद्यमान संस्थाओं में मुख्य रूप से सुविधाओं के समेकन व विस्तार पर बल दिए जाने का प्रस्ताव है । विश्व० अनु० आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों को संस्थानिक बुनियादी सुविधाओं तथा अध्यापन व शोध की कोटि व स्तर को प्रौन्नत करने हेतु निर्मित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित मानदण्डों के अनुसार विकास अनुदान प्रदान करता है । योग्य विश्वविद्यालयों को विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी अनुदान दिया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

2400. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :

प्रो० रीता वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) दी गई सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गलगंड की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण करने का निर्णय लिया। अब तक 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने स्वास्थ्य निदेशालयों में गलगंड नियंत्रण कक्ष खोले हैं जिन्हें अब पुनः राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम का नाम दिया गया है।

आज की तारीख तक 16 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपने-अपने राज्यों में आयोडीकृत नमक से भिन्न अन्य कोई किसी खाद्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	1,08,244.00	1,81,938.00	1,17,380,00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,23,172.00	1,69,134.00	2,19,932.00
3.	उत्तर प्रदेश	7,70,281.00	9,90,087.00	27,518.00
4.	कर्नाटक	1,66,905.00	2,45,242.00	1,35,086.00
5.	महाराष्ट्र	3,79,241.00	2,41,396.00	4,15,249.00
6.	मिजोरम	1,27,225.00	1,29,116.00	11,600.00
7.	त्रिपुरा	—	62,197.00	1,37,207.00
8.	केरल	10,974.00	93,021.00	1,28,974.00
9.	उड़ीसा	2,683.00	32,144.00	1,38,212.00
10.	मणीपुर	1,92,219.00	1,53,646.00	1,50,064.00
11.	सिक्किम	1,19,271.00	1,16,289.00	1.35,383.00
12.	मेघालय	—	—	2,28,339.00
13.	हरियाणा	192.00	77,451.00	—

1	2	3	4	5
14.	आंध्र प्रदेश	6,357.00	13,510.00	—
15.	हिमाचल प्रदेश	—	—	15,000.00
16.	असम	—	—	1,02,966.0
17.	नागालैंड	—	—	1,57,601.00
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	1,86,921.00

* (पहले इसका नाम राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम था) ।

आयोडीकृत नमक के उपभोग को लोकप्रिय बनाने हेतु सूचना, शिक्षा तथा संचार नीतियों को गहन बनाया जा रहा है।

रेलवे सूचना प्रणाली का कंप्यूटरीकरण

2401. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटरीकृत जन-शक्ति नियोजन सूचना प्रणाली आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कौन-कौन से विभागों तथा जोनों में कार्यान्वित की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रणाली के अन्तर्गत समूचा रेल नेटवर्क आएगा ।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री

2402. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा गाड़ियों और प्लेटफार्मों पर घटिया और अस्वास्थ्यकर खाद्य-पदार्थों की बिक्री की जाती है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रक्रिया को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर अनधिकृत वेंडिंग के कुछ मामले नोटिस में आए हैं ।

(ख) और (ग) रेल अधिनियम के अंतर्गत गाड़ियों और रेल परिसरों में अनधिकृत वेंडिंग एक दंडनीय अपराध है। पूर्ववर्ती भारतीय रेल अधिनियम, 1980 के तदनुरूपी उपबन्धों की तुलना में

रेल अधिनियम 1989 के संबद्ध उपबंध अधिक कठोर हैं क्योंकि इनमें इस अपराध के लिए दण्ड में वृद्धि की गयी है। अनधिकृत फेरीवालों/वेंडरों को पकड़ने के लिए वाणिज्यिक और रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप के अचानक जांच की जाती हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन

2403. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों को ऐसे प्रोत्साहन देने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्वास रोगों का फैलना

2404. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली और अन्य औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण के कारण श्वास-रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रदूषण के कारण होने वाले श्वास-रोगों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली तथा देश के अन्य भागों के मुख्य अस्पतालों में नाक-कान-गला रोग विभागों का दर्जा बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय व्यासायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने कुछ समय पहले अहमदाबाद में वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन किया था।

(ख) इस अध्ययन से अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में महिलाओं में खांसी और सांस लेने में कठिनाई की अत्यधिक घटना-दरों का पता चला। कम प्रदूषण वाले क्षेत्र के मुकाबले उच्च प्रदूषण

वाले क्षेत्रों में फेफड़े के रोग, क्षयरोग और हृदय पर पड़ने वाले वृहत प्रभाव (एन्लार्ज्ड हार्ट शेडोज) भी आमतौर पर काफी अधिक पाए गए ।

(ग) और (घ) श्वसनी रोगों के उपचार और परिचर्या संबंधी सुविधाएं देश के प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

2405. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के छोटे से और सीधे प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालयों में अलग-अलग कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1992 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार का वर्ष 1993 के लिए प्रवेश में संबंधित और अधिक संसाधन जुटाने के संबंध में क्या प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष छूट के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 1991-92 के दौरान 7052 दाखिलों तथा 1992-93 के दौरान नवम्बर, 1992 तक 4350 दाखिलों के आदेश दिए ।

विशेष छूट के अंतर्गत दाखिला प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को दाखिले का पात्र होने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने चालू शिक्षा सत्र में 13 केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली प्रारम्भ की है । 9 केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली पहले से चल रही है ।

रेलवे में चिकित्सा सुविधाएं

2406. **श्री आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी हित निधि योजना के अंतर्गत औषधियों की देशी प्रणाली का विकास करने के उद्देश्य से भारतीय रेलों पर 10 आयुर्वेदिक तथा 114 होम्योपैथिक अंशकालिक डिस्पेंसरियां मुहैया कराई गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्नातकोत्तर वैद्यकीय कालेज, नागपुर को सहायता

2407. **श्री तेज सिंह राव भोंसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; जिसमें स्नातकोत्तर वैद्यकीय कालेज, नागपुर का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता की मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता-राशि देने का विचार है और अब तक कितनी धन-राशि जारी की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) चिकित्सा परिचर्या में दर्जा बढ़ाकर उत्कृष्टता के विशिष्ट संस्थानों के रूप में बदले जाने वाले संस्थानों का पता लगाने के लिए अगस्त, 1990 में एक समिति नियुक्त की गई और इस समिति ने महाराष्ट्र सरकार के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया । तथापि, इस समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् इस मामले के सभी पहलुओं, जिसमें संसाधनों की उपलब्धता इस प्रकार की योजना के सम्भावित प्रभाव और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व पर सावधानी-पूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल न करने का फैसला किया है । इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता निर्धारित नहीं की गई है ।

रेलवे परिसरों में सामान की तलाशी

2408. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

श्री राजवीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर अपवंचन के मामलों का पता की दृष्टि से राज्य सरकार के कर्मचारियों को रेलवे परिसरों लगाने में तलाशी लेने का अधिकार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलवे में परिसरों में माल की तलाशी लेने की अनुमति देने से रेलवे के कार्य संचालन में बाधा पड़ेगी । रेलें वाहक के रूप में पारवहन के दौरान माल के लिए जिम्मेवार हैं । पारवहन के दौरान माल के साथ छेड़-छाड़ करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप यदि पैकिंग आदि अस्त-व्यस्त पायी जाती है तो रेल उपयोगकर्त्ता दावे दायर कर सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

2409. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लोगों ने रेलवे के कितने भूमि-क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) ऐसी भूमि का ब्यौरा क्या है जिसे पट्टे पर दिया गया है;

(ग) ऐसी शेष कितनी भूमि फालतू रूप में पड़ी है; और

(घ) सरकार का इस भूमि का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1.9 हैक्टेयर ।

(ख) 0.25 हैक्टेयर ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिटी बुकिंग एजेंसियां

2410. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बड़े शहरों में नई सिटी बुकिंग एजेंसियां खोलने के कोई प्रताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों को कहां-कहां खोला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में महिलाओं के लिए होस्टल

2411. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय महिलाओं के कितने होस्टल चल रहे हैं, और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को महिलाओं के लिए और अधिक होस्टल खोलने के संबंध में कोई अन्य योजना भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस बीच इस योजना को मंजूरी दे दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली में 14 कामकाजी महिला होस्टल पहले से ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक होस्टल का स्थान दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध—1 में दिया गया है ।

(ख) से (घ) 80 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु भारतीय समाज कल्याण परिषद, नई दिल्ली का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन ने भेजा है जिसकी जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	संस्वीकृत किए जाने का वर्ष	संगठन का नाम	पता
1	2	3	4
1.	1974-75	आल इंडिया वीमेन्ज कान्फ्रेंस, नई दिल्ली।	"सरोजिनी हाउस" 6, भगवानदास रोड़, नई दिल्ली।
2.	1974-75	—तदैव—	"कमला देवी हाउस" 6, भगवानदास रोड़, नई दिल्ली।
3.	1975-76	यंग वीमेन्ज एसो०, नई दिल्ली।	कामकाजी महिला होस्टल, नं०-11, ऐवेन्यू-21, साकेत, नई दिल्ली-110017।
4.	1975-76	महिला इमदाद समिति, नई दिल्ली।	बालिका चमन, चेम्सफोर्ड रोड, (नजदीक नई दिल्ली रे०स्टेशन) नई दिल्ली-110055।
5.	1975-76	सेंट स्टीफन होस्पीटल, दिल्ली।	तीस हजारी, दिल्ली।
6.	1980-81	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	जामिया नगर, नजदीक न्यू ऐरा स्कूल, नई दिल्ली।
7.	1980-81	सर गंगाराम होस्पीटल, नई दिल्ली।	सर गंगाराम होस्पीटल, मार्ग, नई दिल्ली।
8.	1983-84	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, नई दिल्ली।	सावित्री नगर, शेख सराय, फेज-1, नई दिल्ली।
9.	1983-84	दिल्ली महिला समाज, नई दिल्ली।	52, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।

1.	2	3	4
10.	1984-85	नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, नई दिल्ली ।	"स्वाति होस्टल" पालिका केन्द्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली ।
11.	1984-85	सेंट स्टीफन होस्पीटल, दिल्ली ।	तीस हजारी, दिल्ली ।
12.	1985-86	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, नई दिल्ली ।	"प्रभात", मोहम्मदपुर, आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।
13.	1986-87	महिला मंगल, जोरबाग नई दिल्ली ।	दक्षिणपुरी, नई दिल्ली ।
14.	1987-88	गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली ।	जी-25, साऊथ ऑफ आई० आई० टी०, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पीछे, नई दिल्ली ।

[अनुवाद]

मद्रास में कलाक्षेत्र शिक्षा केन्द्र

2412. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास में स्थित मुख्य कला केन्द्र, कलाक्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र के कार्यकरण में सुधार लाने तथा इसे और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार कलाक्षेत्र को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि संस्था के विकास के लिए योजनाओं को वित्तपोषित करना संभव हो सकेगा ।

एल० एल० बी० के लिए प्रवेश परीक्षा

2413. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष आयोजित एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि एक उम्मीदवार की याचिका पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्रों का पहले से ही पता लग जाने का आरोप था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। विश्वविद्यालय द्वारा एस० एल० पी० दायर किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन पर इस शर्त के साथ स्थगन आदेश दे दिया था कि सभी प्रवेश अस्थायी हैं तथा अपील के अन्तिम निर्णय पर ही माने जाएंगे।

विश्वविद्यालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश में निर्धारित शर्तों के आधार पर अस्थायी प्रवेश की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

विधवाओं को सुविधाएं

2414. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सेवा काल के दौरान और सेवा निवृत्ति के पश्चात् मरने वाले रेल कर्मचारियों की विधवाओं को दी जा रही सुविधाओं और लाभों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) प्रचलित आदेशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों की विधवाओं को निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं :—

(i) **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति** :

किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की हालत में, रेल कर्मचारी की विधवा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है। सेवा निवृत्ति के बाद हुई मृत्यु के मामले इस नीति के अन्तर्गत नहीं आते।

(ii) **यात्रा संबंधी सुविधाएं** :

जो रेल कर्मचारी 12-3-1987 को या उसके बाद सेवा में थे/हैं और जिनकी मृत्यु उस तारीख के बाद हुई हो। उनकी विधवाओं को निर्धारित संख्या में मानार्थ पास जारी किए जाते हैं।

(iii) **पावने की राशि** :

पेंशन/भविष्य निधि/उपदान/छुट्टी के बदले नकद भुगतान और बीमा की यथाअनुमेय राशियां ।

(iv) **आवास की सुविधा** :

विधवा रेलवे आवास को अपने पास रखने के लिए भी पात्र है ।

(v) **चिकित्सा सहायता** :

योजना के अन्तर्गत यथा-निर्धारित ।

[अनुवाद]

गुजरात में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल

2415. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केन्द्रीय सरकार का कोई अस्पताल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें चिकित्सीय तथा परा-चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) यदि नहीं तो गुजरात में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी कठिनाईयों को दूर करने हेतु वहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सीय तथा परा-चिकित्सीय कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के अस्पताल खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गुजरात में कोई नया केन्द्रीय सरकार अस्पताल खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं । तथापि, अहमदाबाद शहर में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा परिचर्या सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को शुरू किया गया है ।

[हिन्दी]

वैदिक गणित

2416. **डा० लाल बहादुर राव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को एक विषय के रूप में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बहुमूल्य विरासत के संरक्षण, प्रसिद्धि और प्रसार हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिषद द्वारा प्रकाशित टीचर्स गाईड में वैदिक गणित के कुछ सूत्रों और अनुप्रयोगों को संवर्धक सामग्री के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

बृहत्तर नैनीताल झील क्षेत्र समन्वित पर्यावरण परियोजना

2417. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 28-7-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बृहत्तर नैनीताल झील क्षेत्र समन्वित पर्यावरण परियोजना को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : बृहत्तर नैनीताल झील क्षेत्र समन्वित पर्यावरण परियोजना द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई हैक्योंकि इसमें बहु-विषयी विशेषज्ञता तथा भारी निवेश शामिल हैं। अभी तक, परियोजना दर दाता एजेंसियों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई है।

[अनुवाद]

बैगनों के जरिए मिले कोयले की मात्रा कम होना

2418. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एककों से रेल बैगनों से प्राप्त कोयले की मात्रा कम होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उद्योगों को मिले कोयले की मात्रा में कमी और शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतें आम तौर पर कोयला खानों द्वारा कोयले के कम लदान अथवा कोयला लदान स्थलों पर या परिवहन के दौरान अस्थानीकृत कटचोरी के कारण कोयले की कमी के संबंध में होती हैं। उद्योगों द्वारा कोयले की वास्तव में प्राप्त की गई कम मात्रा का सही आकलन करना संभव नहीं है। बहरहाल, ऐसे मामलों में, जहां रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोयले की कमी सिद्ध

हो जाती हैं। वहां मुआवजे के दावों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान, कोयले एवं कोक के परेषणों पर मुआवजे के रूप में 4.84 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) वाहक के रूप में, रेलें यह सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास करती हैं कि परेषकों द्वारा उन्हें सौंपा गया माल परेषितियों तक सही-सलामत पहुंचा दिया जाए। इस संबंध में किए गए उपायों में अपराधग्रस्त क्षेत्रों में गाड़ियों का मार्गरक्षण करना। अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों को दबाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना शामिल हैं।

[हिन्दी]

ल्यूकोडरमा का उपचार

2419. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ल्यूकोडरमा के उपाचार हेतु नई विधि (दवा) खोज निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस देश में इसकी खोज की गयी;

(ग) क्या उक्त उपचार नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो ल्यूकोडरमा के उपचार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के योगदान सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी बड़े अस्पतालों में ल्यूकोडरमा के उक्त प्रभावी उपचार को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि क्यूबा तथा भारत के वैज्ञानिकों ने विभिन्न नीतियां अपना कर ल्यूकोडरमा का उपचार विकसित करने का दावा दिया है। भारत में मानव प्लेसेंटा से प्लेसेंट्रिक नामक औषध विकसित की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक उपचार विकसित किया है जिसमें मुखसेव्य औषधें प्रैडनीसोलिन और लेवामीसोल तथा त्वचा प्रत्यारोपण भी शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधीन विकृति विज्ञान संस्थान में एक देशी इनविट्रो तकनीक विकसित की गई है।

(ग) और (घ) इस रोग के उपचार संबंधी नीति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में त्वचा रोग विज्ञान और रतिरोग विज्ञान विभाग में कार्य कर रहे डाक्टरों के एक दल द्वारा विकसित की गई है।

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकसित की गई उपचार विधियां बहुत सरल है और इन्हें कहीं भी त्वचा रोग विज्ञानी द्वारा अपनाया जा सकता है।

[अनुवाद]

पाठ्यक्रम में मैकेनिकल ड्रांइग को सम्मिलित करना

2420. **श्री शशि प्रकाश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रमों में +2 स्तर पर "मैकेनिकल ड्रांइग" को एक विषय के रूप में शुरू करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संस्था पत्राचार विद्यालय, दिल्ली, जो स्कूल स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है। जो वर्ष 1992-93 के शैक्षिक सत्र से जमा दो स्तर (कक्षा XII) पर इंजीनियरिंग ड्रांइग शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

खेलों के विकास हेतु योजनाएं

2421. **श्री साईमन मरांडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के प्रत्येक जिले में युवा मामलों तथा खेल विभाग में विभिन्न योजनाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में युवा प्रतिभा के विकास तथा खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) खेलों के संवर्धन तथा बिहार राज्य और इसके पहाड़ी क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, खेल छात्रावास योजना, खेल परियोजना विकास क्षेत्र योजना तथा स्पोर्टस बॉयज कम्पनी जैसी योजनाएं संचालित की गई हैं। रांची को विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत हॉकी केन्द्र के रूप में चुना गया है। रांची और गुमला में खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस० पी० डी० ए०) कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक उत्सव

2422. **श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों का कोई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसे उत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) संस्कृति विभाग और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राज्यों के किसी भी सांस्कृतिक उत्सव का कोई आयोजन नहीं किया है । तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गठित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने राज्य सरकारों और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से ऐसे विभिन्न उत्सव आयोजित किए हैं ।

हरियाणा में रेल लाइनें

2423. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोहतक-हांसी-हिसार और जींद-हांसी-हिसार के बीच नई रेल लाइनें बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें हरियाणा में उक्त अवधि के दौरान बड़ी रेलवे लाइनों में बदला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में निम्नलिखित मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदले जाने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(i) दिल्ली-रेवाड़ी ।

(ii) रेवाड़ी-हिसार-भटिंडा ।

"कोंकण रेल परियोजना संबंधी समिति"

2424. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 28 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3020 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। समिति ने प्रस्तावित संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की पर्यावरणीय, वास्तुशिल्पीय, सांस्कृतिक एवं परम्परा की दृष्टि से जांच की। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय का कार्यकरण

2425. **श्री भीकान्त जेना** :

श्री हरिकिशोर सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में योजना तथा वास्तुकला विद्यालय के कार्यकरण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा):(क) से (ग) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कटिक्चर की साधारण परिषद (जनरलकांउसिल) जिसे स्कूल की वार्षिक रिपोर्टों और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने और संकल्प पारित करने का अधिकार प्राप्त है, ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 की रिपोर्टों की और आगे विस्तृत जांच करने तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने पर विचार करना। फिलहाल आस्थगित कर दिया है।

सौन्दर्य प्रसाधनों में सीसा

2426. **श्री राम कापसे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सौन्दर्य प्रसाधनों—विशेष रूप से आंखों के लिए प्रयुक्त होने वाले सौन्दर्य प्रसाधनों में सीसे की प्रतिशतता के संबंध में व्यापक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे हानिकारक सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) कुछ वर्षों पहले, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सीमित अध्ययन किया गया और दिल्ली के बाजारों से लिए गए नमूनों का विश्लेषण करने पर आंखों के लिए प्रयुक्त होने वाले सौन्दर्य-प्रसाधनों में सीसे की अधिक मात्रा नहीं पाई गई।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 आंखों के लिए सामग्री तैयार करने में सीसायुक्त रंगों के प्रयोग का निषेध करता है। इस नियम में ऐसे सौन्दर्य प्रसाधनों को तैयार करने और बेचने के लिए दांडिक कार्रवाई की भी व्यवस्था है जो मानक गुणवत्ता के नहीं होते।

त्रिवेन्द्रम और कोट्टायम स्टेशन

2427. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम और त्रिवेन्द्रम को माडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए केवल त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल का चयन किया गया है।

(ख) त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल पर केवल स्टेशन इमारत के विस्तार के काम को छोड़कर अन्य सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इमारत के विस्तार का काम भी 1993-94 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। 147.16 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 131.76 लाख रुपये की धनराशि पहले से ही इस काम पर खर्च की जा चुकी है।

नागपुर स्टेशन से शायिकाओं का कोटा

2428. **श्री बत्ता मेघे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जाने वाली गाड़ियों में नागपुर स्टेशन हेतु उपलब्ध शायिकाओं/सीटों के वर्तमान कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान कोटे के अतिरिक्त आपातकालीन कोटे में वृद्धि करने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बम्बई, दिल्ली, हवड़ा और मद्रास की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए नागपुर में उपलब्ध आरक्षण कोटे इस प्रकार हैं :--

दिशा	उपलब्ध कोटा				
	पहला दर्जा वा० कू०	वा० कू० 2-टियर	पहला दर्जा	वा० कू० कुर्सीयान	दूसरा दर्जा
बम्बई	6	83+ 12 (आर०ए०सी०)	40+ 6 (आर०ए०सी०)	—	723+ 158 (आर०ए०सी०)
दिल्ली	1	20	10	10	265
हवड़ा	3	44	10	—	225+ 35 (आर०ए०सी०)
मद्रास	2	12	4	—	155

(ख) और (ग) आपात कोटे में वृद्धि करने हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, इस स्टेशन के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने हेतु मांगें प्राप्त हुई हैं। 1-2-1993 से 6039 मद्रास वाराणसी एक्सप्रेस और 6034 मद्रास पटना एक्सप्रेस गाड़ियों में नागपुर स्टेशन को दूसरे दर्जे की चार-चार शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा आवंटित कर दिया गया है।

सरकारी अस्पतालों में खराब निश्चेतक यंत्र

2429. **श्री वी० कृष्ण राव** :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पीड़ित लाभार्थियों तथा जन सामान्य लोगों की शिकायतें सुनने और समुचित समयावधि में उनका निराकरण करने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई जन शिकायत अधिकारी कार्यरत है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अस्पताल में खराब निश्चेतक यंत्रों के संबंध में 1992 के दौरान (आज तक) कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में निश्चेतक यंत्रों की संख्या कितनी-कितनी है और उनमें कितने यंत्र खराब हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली में प्राय: अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों और जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए लोक शिकायत अधिकारी/सेल हैं।

(ख) दिल्ली में वर्ष 1992 (अब तक) में अस्पतालों में खराब निश्चेतक यंत्रों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	निश्चेतना मशीनों की कुल संख्या	खराब निश्चेतक मशीनों की संख्या
1	2	3	4
1.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	16	2
2.	सफदरजंग अस्पताल	42	—
3.	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	17	—
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	33	14*
5.	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	42	24**
6.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	13	—
7.	सिविल अस्पताल	1	—
8.	गुरू तेगबहादुर अस्पताल	20	—
9.	मानसिक रोग अस्पताल	1	—
10.	गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल	12	1
11.	चरक पालिका अस्पताल	4	—
12.	पालिका प्रसूति अस्पताल	3	2***
13.	स्वामी दयानन्द अस्पताल	7	—

1	2	3	4
14.	श्रीमती गिरधारीलाल प्रसूति अस्पताल	2	—
15.	कस्तूरबा अस्पताल	7	—
16.	हिंदूराव अस्पताल	14	—
17.	डी० एच० एस०	8	—

*बेकार घोषित किए जाने हैं और रद्द किए जाने हैं।

**24 मशीनों में से 16 मशीन बेकार घोषित की गई हैं और 8 बेकार घोषित की जानी हैं।

***मरम्मत करने के लिए कार्रवाई की गई है।

पर्यावरण संबंधी पुस्तकें

2430. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में चलाये जा रहे प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली-पाठ्यक्रम-पुस्तक ब्यूरो द्वारा पर्यावरण पर "पर्यावरण अध्ययन" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक कक्षा III से V तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नागपुर और दिल्ली के बीच गाड़ी

2431. **श्री रामचन्द्र धंगारे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन नागपुर होकर दिल्ली आने वाली एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट गाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में नागपुर से आरक्षित शायिका कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक गाड़ी में प्रत्येक श्रेणी में प्रतिदिन प्रतीक्षा-सूची में औसतन कितने यात्रियों को रखा जाता है;

(घ) क्या नागपुर में यात्रियों की बढ़ती-संख्या को देखते हुए नागपुर से दिल्ली के लिए सीधे गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय 5 सुपरफास्ट गाड़ियां (एक साप्ताहिक सहित) और 6 एक्सप्रेश गाड़ियां (सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक और 3 सप्ताहिक गाड़ियों सहित) नागपुर और दिल्ली/नई दिल्ली/निजामुद्दीन को जोड़ती हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गाड़ी का नं० और नाम	कोटा				दैनिक औसत प्रतीक्षा सूची में			
	पहला दर्जा वा० कू०	वा० कू० 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	पहला दर्जा वा०कू०	वा०कू० 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
2615 मद्रास-नई दिल्ली जी०टी० एक्सप्रेस	—	4	—	50	—	4	2	40
2621 मद्रास-नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस	1	4	2	60	—	5	3	46
2625 तिरूवनंतपुरम-नई दिल्ली केरल एक्प्रेस	—	2	2	25	—	6	3	15
2723 सिकन्दराबाद-नई दिल्ली ए० पी० एक्सप्रेस	—	4	2	28	—	5	3	23
7021 हैदराबाद-निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस	—	2	—	32	—	3	—	8
8237 बिलासपुर-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	—	—	2	18	—	—	4	25

निधियों का उचित उपयोग

2433. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) में अपनी योजनाओं के कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों द्वारा क्रियान्वयन और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी कोई व्यवहार्य निगरानी तंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर में सुधार लाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के क्या प्रयास किए लिए गए हैं; और

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बनाई गई अपनी आरक्षण नीति पर किस प्रकार निगरानी रखता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं में यह अपेक्षित है कि नए अनुदान प्रदान करने से पहले-पहले दिए गए अनुदानों के परीक्षित लेखे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र आयोग को भेजे जाए। संस्वीकृति प्रदान करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसका पालन किया जाता है, अत: वि० अ० आ० की पूर्व सहायता के साथ किए गए कार्य पर निगरानी रखी जाती है। छात्रों द्वारा अनुसंधान योजना के अन्तर्गत इस कार्य का मध्यावधि में और परियोजना के अन्त में मूल्यांकन किया जाता है। उच्च अनुसंधान के लिए विभागों की सहायता योजनाओं के अन्तर्गत विभाग की पूर्व अनुसंधान निष्पादन के विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर संस्वीकृति प्रदान की जाती है और प्रत्येक संस्वीकृति की अवधि की समाप्ति पर जोकि सामान्य रूप से 4-5 वर्ष है, विभागों का समय बढ़ाने से पूर्व पुन: विशेषज्ञ मूल्यांकन किया जाता है।

प्रत्येक की मिसिल के माध्यम से वास्तविक रूप से इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है और चूंकि उन छात्रों और कार्यक्रमों को संख्या, जिनमें वि० अ० आ० सहायता प्रदान करता है, अत्यधिक हो गई है, कुछ कमियां देखने में आई हैं। अत: वि० अ० आ० ने संस्थाओं, छात्रों और कार्यक्रमों का संगणकीकरण शुरू किया है ताकि निरीक्षण और अधिक सावधानी से किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिक कार्यान्वयन और वि० अ० आ० के कार्यक्रमों की समीक्षा में सुधार करने के लिए आवधिक आधार पर विश्वविद्यालयों से कुछ वरिष्ठ अकादमिकों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। वि० अ० आ० के सदस्य विभिन्न वि० अ० आ० कार्यकलापों के कार्यान्वयन के स्तर की अलग-अलग जांच करते हैं।

(घ) विशेषज्ञों के माध्यम से वि० अ० आ० द्वारा 27 विषयों में माडल पाठ्यचर्या हाल ही में विकसित की गई है और ये अपनाए जाने/अनुकूल बनाए जाने के लिए भी स्वायत्त कालेजों में

उपलब्ध है। स्वायत्त कालेज अपनी स्वयं पाठ्यचर्या तैयार करने में स्वतंत्र हैं और अतः उन्हें समय-समय पर इसका मूल्यांकन करना तथा इसको अद्यतन बनाना अपेक्षित है। स्वायत्त कालेजों को दिए गए अनुदानों का उचित उपयोग वि० अ० आ० द्वारा शुरू किया जाता है जैसाकि ऊपर बताया गया है।

(ङ) विश्वविद्यालय स्वायत्त है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम और संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों के अधीन है। वि० अ० आ० और विश्वविद्यालयों के बीच संबंध पर्यवेक्षी और अधीनस्थ संगठन के नहीं हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति वि० अ० आ० और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू होती है जो वि० अ० आ० से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं। वि० अ० आ० केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की जानकारी में आरक्षण नीति के प्रावधान लाता है और उनके द्वारा कार्यान्वयन के लिए इसकी सिफारिश करता है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्टारों की आवधिक बैठकों द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन स्तर का पता लगाने और निरीक्षण समिति के माध्यम से किया जाता है जिसमें कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इसके अलावा वि०अ०आ० का एक सदस्य समय-समय पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के स्तर की जांच करता है।

हावड़ा दिल्ली सेक्शन पर अपर इण्डिया एक्सप्रेस

2434. **श्री अमल दत्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा दिल्ली सेक्शन पर "अपर इण्डिया एक्सप्रेस" को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे पुनः कब से शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सियालदह और दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्ववर्ती 13/14 अपर इण्डिया एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र अक्तूबर, 1987 से कम करके दिल्ली और वाराणसी तक कर दिया था। नवम्बर, 1989 में इस गाड़ी का नम्बर बदल कर 3133/3134 कर दिया गया और अब यह सियालदह और मुगलसराय के बीच चल रही है।

(ख) कम लोकप्रिय होने के कारण।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कालेजों को मान्यता प्रदान करना

2435. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री छीतू भाई गामीत :

श्री लाल बाबू राय :

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास राज्य सरकार की ओर से कालेजों को मान्यता देने हेतु प्राप्त राज्यवार कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन पत्र किन-किन तारीखों से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इनको शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यायल अनुदान आयोग ने वि० अ० आ० अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए विनिमय अधिसूचित किए गए हैं। ये विनिमय मान्यता प्रदान करने संबंधी कतिपय शर्तें निर्धारित करते हैं। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 115 कालेजों से प्राप्त मान्यता संबंधी प्रस्ताव आयोग के पास लंबित पड़े हैं। ऐसे प्रस्तावों की राज्यवार संख्या, ऐसे प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है। इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या	वि०अ०आ० में प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	विक्रम विश्वविद्यालय	4	1-12-92, 1-12-92, 16-10-92, 13-11-92
	डा० एच० एस० गोड विश्वविद्यालय सागर (मध्य प्रदेश)	4	20-10-92, 1-10-92, 1-12-92, 1-12-92
	ए० पी० एस० सिंह	25	1-12-92
	रवि शंकर विश्वविद्यालय	3	1-10-92, 3-8-92, 12-8-92
	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	3	28-10-92, 28-10-92, 20-10-92
आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन विश्व०	3	16-7-92, 28-7-92, 2-12-92
	एस० के० डी० विश्व०	3	25-11-92, 3-11-92, 20-10-92
	एस० वी० विश्व०	1	16-9-92

1	2	3	4
	उस्मानिया विश्व०	5	19-11-92, 24-8-92, 11-11-92 11-11-92, 20-10-92
केरल	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	1	24-8-92
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कलकत्ता विश्व०	7	2-12-92, 2-12-92, 9-9-92, 25-6-92, 28-7-92, 12-8-92, 24-8-92
	उत्तर बंगाल विश्व०	1	30-6-92
बिहार	बिहार विश्व०	1	4-8-92
	रांची विश्व०	1	20-7-92
	एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	1	25-8-92
	के० एस० दरभंगा विश्वविद्यालय	2	4-8-92, 24-6-92
हरियाणा	एम० डी० विश्व०	4	1-12-92, 8-7-92, 4-8-92, 2-12-92
	कुरुक्षेत्र विश्व०	1	10-6-92
महाराष्ट्र	पूना विश्व०	1	11-11-92
	नागपुर विश्व०	3	21-7-92, 6-7-92, 24-9-92
	बम्बई	3	11-8-92, 3-11-92, 16-6-92
	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	1	24-9-92
	शिवाजी विश्व०	2	3-11-92, 24-8-92
	अमरावती	1	16-9-92
तमिलनाडु	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	3	30-9-92, 21-10-92, 31-11-92
	मद्रास	5	28-10-92, 24-6-92, 18-6-92 21-7-92, 3-11-92

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	कुमाऊं विश्व०	1	24-6-92
राजस्थान	सुखाडिया विश्व०	1	16-10-92
कर्नाटक	कर्नाटक विश्व०	3	2-9-92, 20-11-92, 25-11-92
	मैसूर विश्व०	1	29-10-92
उड़ीसा	उत्कल विश्व०	14	13-5-92, 8-7-92, 16-7-92, 22-7-92, 27-7-92, 7-8-92, 24-8-92, 26-8-92, 9-9-92, 30-9-92, 30-9-92, 30-9-92, 1-10-92
	साम्लबपुर विश्व०	4	6-7-92, 5-8-92, 5-8-92, 5-11-92
	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	2	12-10-92, 5-11-92
	कुल :	115	

[अनुवाद]

बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन

2436. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और मैसूर को बड़ी लाइन से जोड़ने के कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस लाइन के संचालन से संभावित हानि को वहन करने का कोई आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह आश्वासन कितने वर्षों के लिए दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 126.72 करोड़ रुपए इस लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे 9-9-92 को खोल दिया गया है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने मुफ्त भूमि प्रदान की है।

(ग) जी, हां।

(घ) तीन वर्ष की अवधि के लिए।

नर्सों का चयन

2437. **डा० अमृत लाल कालीदास पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के स्कूल आफ नर्सिंग में तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए चुने गये प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता सूची में कुछ विसंगतियां सरकार की जानकारी में आयी हैं;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है कि भविष्य में ऐसी चूक न होने पाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। जैसे ही यह मामला प्रधानाचार्य के ध्यान में लाया गया वैसे ही तत्काल कागजातों को सील कर दिया गया। समीक्षा समिति जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली नर्सिंग यूनियन ट्यूटर्स और संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया। समीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई संशोधित योग्यता सूची, पहले तैयार की गई योग्यता सूची के स्थान पर रख दी गई।

(ग) परीक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

खेल-कूद विद्यालय

2438. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल-कूद विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और अब तक कितनी धनराशि वास्तव में दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश में खेल कूद स्कूल स्थापित करने के लिए कुल लागत (10.60 करोड़ रुपए) के 50% तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ख) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रस्तावित स्कूल में विभिन्न विधाओं में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा जो 12 वर्ष से कम युवाओं को नियमित शैक्षिक अध्ययन के साथ-साथ खेलों में संस्थागत कोचिंग प्रदान करेगा। स्कूल रंगारेड्डी जिले के तुमकुंता ग्राम में 200 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभाग में ऐसे कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल स्कूल के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा सके।

प्रवाल का नष्ट किया जाना

2439. **श्री संयद शाहाबुद्दीन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्नार की खाड़ी में सफेद प्रवाल के खंजे को अंधाधुंध नष्ट किया जा रहा है और उद्योगों को कच्चे माल के रूप में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्रियाकलापों को रोकने और इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय प्रणाली को बचाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मन्नार की खाड़ी के द्वीपों में पाए जाने वाले सफेद प्रवालों के अवैध निष्कासन एवं बिक्री पर नियन्त्रण लगाने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं :—

(1) अपराधों को दर्ज करके और सामग्री को जब्त करके इनके निकालने पर नियन्त्रण लगाया जा रहा है।

(2) संबंधित उद्योगों से अनुरोध किया गया है कि वे इन सामग्रियों को न खरीदें तथा उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

(3) सफेद प्रवालों को अवैध रूप से निकाले जाने का पता लगाने तथा इसे रोकने हेतु गश्त लगाने के लिए जल नौकाएं खरीदी गई हैं।

(4) राजस्व और मछलीपालन विभाग के नियंत्रणाधीन अनेक द्वीप समूहों को वन विभाग ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है तथा इन्हें भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

(5) फिंगर जेलियों के नाम पर प्रवालों को अवैध रूप से निकालने को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

2440. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्राइवेट दन्त महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) देश में दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान से रेल सम्पर्क

2441. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच रेल यातायात में सुधार करने पर सहमति हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच शीघ्र रेल सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच यात्री और माल यातायात संबधी सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । हाल ही में बैठक में दोनों देश यात्री और माल यातायात के संचलन की सुविधाएं उन्नत करने तथा वातानुकूल सेवा और समूह में यात्रा करने की सुविधा के लिए कार्यक्रमबद्ध सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत थे ।

खुर्धा रोड में डीजल सैटेलाइट शेड की स्थापना

2442. **श्री सुबाष चन्द्र नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उड़ीसा में खुर्धा रोड पर डीजल सैटेलाइट शेड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह डीजल सैटेलाइट शेड की स्थापना वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। खोरधा रोड क्षेत्र में डीजल रेल इंजनों की छोटी-मोटी खराबी को दूर करने के लिए मरम्मत गैंगों की व्यवस्था की गई है। खोरधा रोड में एक ईंधन संस्थापन की स्थापना भी की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेल-परियोजनाएं

2443. **श्री थाइल ज्ञान अंजलोज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-कौन सी रेल परियोजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक परियोजना इस समय किस स्तर पर चल रही है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने की अनुमानित तारीख क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जाएगी और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केरल में उन परियोजनाओं के नाम, जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था परन्तु अभी तक पूरा नहीं किया गया, प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति और उनको पूरा करने का सम्भावित तारीख नीचे दर्शायी गयी है :—

परियोजना का नाम	लागत करोड़ रुपये	प्रतिशत प्रगति 30-9-92	पूरा करने की सम्भावित तारीख
नई लाइनें			
त्रिचूर-गुरुवायूर	23.48	95.5%	92-93
दोहरीकरण			
कोल्लम-तिरूवनंतपुरम सेंट्रल	76.41	3.3% (भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है)	95-96*
कायनकुलम-कोल्लम	42.17	39.51%	94-95*

*आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान हर वर्ष की जाती है जो परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होती है। केरल में 1993-94 में शुरू की जाने वाली किसी परियोजना के प्रस्ताव की पहचान नहीं की गई है।

रेल टिकटों में हेराफेरी

2444. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कुछ बुकिंग क्लर्क राजस्थान तथा अन्य स्थानों के लिए जाली रेल टिकटें बेचने के दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में इन कदाचारों को रोकने के लिए कौन-से निवारक/निरोधक उपाए किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 5-10-92 को श्री सतीश, बांदीकुई, राजस्थान के निवासी ने लगभग 09.00 बजे ड्यूटी पर तैनात बुकिंग कल्र्क को 50% कमीशन पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक की 4 टिकटें बिक्री हेतु देने की पेशकश की। धोखाधड़ी को भांपते हुए बुकिंग कल्र्क ने इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक को सूचित करने और अपने सहकर्मियों की मदद से श्री सतीश को पकड़ने की व्यवस्था कर ली। रा०रे०पु० को मामले की रिपोर्ट की गई जिसने रे०सु०ब० की मदद से दिल्ली स्थित मालाबार होटल, फतेहपुरी, जहां श्री सतीश ठहरे हुए थे पर छापा मारा तथा उनके कमरे से 86 टिकटें बरामद कीं। उनके द्वारा यह भेद बताये जाने पर कि उनका गैंग जयपुर से भी परिचालित हो रहा था, रा०रे०पु० उन्हें जयपुर ले गई तथा उनके बहनोई श्री लक्ष्मीनारायण सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 220 कार्ड टिकट तथा लगभग एक दर्जन रबड़ की मोहरें बरामद कीं। ऐसे अभिशंसी प्रमाणों के आधार पर रा०रे०पु० ने न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जिस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली मेन स्टेशन के तीन बुकिंग क्लर्कों को भी इस मामले के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है क्योंकि इस मामले में उनके भी शामिल होने का संदेह है।

(घ) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए जांच की जाती है। इन जांच कार्यों को आगे बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न सुरक्षित भंडार

2445. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-10-92 को स्थिति के अनुसार गोदामों में सरकार के पास कितना सुरक्षित खाद्यान्न भंडार था;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अपने भंडार के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का क्रय किया गया; और

(ग) पिछले वर्ष में उपलब्ध भंडारों को मिलाकर इस समय कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) 31-10-1992 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में अनन्तिम तौर पर 100.26 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों, दोनों चावल और गेहूं का स्टाक था ।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं, चावल और मोटे अनाजों को वसूल की गई मात्रा निम्नानुसार है :—

		(लाख मीटरी टन में)
चावल		
(1-1-92 से 3-12-92 तक)		78.84
गेहूं		
(1-1-92 से 27-11-92)		63.80
मोटे अनाज		
(1-1-92 से 3-12-92 तक)	—	0.26
	जोड़	142.90

(ग) 1-1-1992 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में अनन्तिम तौर पर गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

चावल	गेहूं	जोड़
86.25	52.77	139.02

[अनुवाद]

पं० ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की पुण्य शती

2446. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री सुदर्शन रायचौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की पुण्य शती मनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धन राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) आम-तौर पर, सरकार द्वारा विख्यात विभूतियों की पुण्य तिथियां मनाने की कोई परंपरा नहीं है तथापि, यदि किसी संस्था से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सरकार उन पर वित्तीय सहायता हेतु विचार करेगी ।

बालूरघाट और रायगंज से कलकत्ता/हावड़ा के बीच रेल संपर्क

2447. **श्री सुव्रत मुखर्जी** :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालूरघाट और रायगंज क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए इन स्थानों को कलकत्ता/हावड़ा से रेल से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रायगंज पहले ही बारसोई और कटवा के रास्ते रेल द्वारा कलकत्ता से जुड़ा है । बालूरघाट को एकलाखी के रास्ते जोड़ने का प्रस्ताव है । एकलाखी-बालूरघाट लाइन का निर्माण एक स्वीकृत कार्य है जिसे निचली परिचालनिक प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने और चल रही परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही धन की व्यवस्था की जाएगी।

कोंकण रेल मार्ग

2448. **श्री मनोरंजन भक्त** :

श्री महेश कनोडिया :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल रिएलाइनमेंट यूनिट ने कोंकण रेलवे के गोआ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग को राज्य के कम विकसित अंदरूनी क्षेत्रों से ले जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित मार्ग के पुनसंरेखण के प्रश्न की जांच सेवा-निवृत्त अध्यक्ष रेलवे, बोर्ड एवं गोआ के एक प्रमुख इंजीनियर श्री एम० मेंजिस की अध्यक्षता में एक सदस्ययी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। उनकी शिफारिशों के अनुसार मायेम और बल्ली के बीच 13 कि०मी० लंबाई में सरकार ने संरेखण को उपयुक्त रूप से बदल दिया है।

[हिन्दी]

मोरों का मारा जाना

2449. **श्री काशीराम राणा :**

श्री लाल बाबू राय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 9 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मोरों के मारे जाने के संबंध में पुलिस जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

2450. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री दिग्विजय सिंह :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री राम विलास पासवान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक/गैर-शिक्षक स्टाफ के बारे में 4 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षक तथा गैर-शिक्षक पदों की कुल संख्या, क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित पदों पर वर्तमान तथा पिछली रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए अथवा किए जा रहे हैं :—

— विशेष विज्ञापन।

— साक्षात्कारों के आधार पर पैनल तैयार करना।

— आवेदन पत्रों का संगणकीकरण।

— क्षेत्रीय चयन बोर्डों द्वारा भर्ती/चयन प्रक्रिया में तेजी लाना।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में क्षेत्र-वार रिक्त पद :

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	शिक्षण	गैर शिक्षण
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	560	81
2.	भोपाल	564	90
3.	जयपुर	568	91
4.	मद्रास	469	54
5.	हैदराबाद	520	69
6.	गुवाहाटी	517	66
7.	चंडीगढ़	595	85
8.	कलकत्ता	170	69
9.	पटना	617	114
10.	भुवनेश्वर	734	151
11.	जम्मू	523	103
12.	लखनऊ	477	86

1	2	3	4
13.	दिल्ली	311	73
14.	बम्बई	468	61
15.	सिल्चर	603	78
	कुल :	7996	1271

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए वर्तमान तथा पिछली बकाया रिक्तियां :

क्रम सं०	वर्ग	वर्तमान रिक्तियां		पिछली बकाया रिक्तियां	
		अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०
1	2	3	4	5	6
1.	पी० जी० टी०	90	45	168	125
2.	टी० जी० टी०	100	50	209	162
3.	पी० आर० टी०	183	92	165	161
4.	विविध	54	27	102	66
5.	अवर श्रेणी लिपिक	—	—	4	10

एड्स रोग के नियंत्रण में लगी विदेशी एजेंसियां

2451. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री अनंतराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एजेंसियां देश में "एड्स" रोग के नियंत्रण में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इन विदेशी एजेंसियों के सहयोग से कोई परियोजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यू० एस० एड, यूनिसेफ, यू० एन० डी० आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। जिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए धन प्रदान किया है/धन देने का वचन दिया है, उसका विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एड्स में अनुसंधान करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक यूनिट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से धनराशि देने के लिए एक परियोजना शुरू की है। व्यवहार संबंधी और नैदानिक घटक पर बल देते हुए "मणिपुर में इंजेक्शन द्वारा मादक औषध उपयोगकर्ताओं में एच० आई० वी० संक्रमण के भविष्य प्रभावी अध्ययन" नामक परियोजना को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त परिषद के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे, ने पुणे में यौन संचारित रोग क्लिनिक में आने वाले रोगियों में एच० आई० वी०-1 और एच० आई० वी०-2 की व्यापकता पर एक अनुसंधान अध्ययन किया है। इस अध्ययन का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी समर्थन किया है।

विवरण

क्रम सं०	अभिकरण का नाम	अमरीकी डालर में राशि
1	2	3
1.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	85,26,014
2.	सीडा	17,45,985
3.	नोराड	2,78,000
4.	यू० एस० एड	1,18,60,000
5.	ई० ई० सी०	1,80,000
6.	ओडा	25,35,000
7.	फोर्ड फाउंडेशन	1,10,000
8.	यू० एन० डी० सी० पी०	20,000
9.	यू० एन० डी० पी०	20,000
10.	यूनिसेफ	2,00,000
11.	विश्व बैंक	8,50,00,000

[हिन्दी]

नर्मदा बांध के निर्माण के कारण स्मारकों का स्थानान्तरण

2452. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध का निर्माण करने के कारण पुरातत्व महत्व के कई मन्दिर और स्मारक परियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वहां से कुछ मन्दिरों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बाजीराव पेशवा की छतरी को भी स्थानान्तरित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के चार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक जिनके नाम—चौबीस अवतार मन्दिर, मान्धाता, जिला खंडवा; बाजीराव पेशवा की छतरी, रावरखेड़ी, जिला खरगोन; सिद्धेश्वर मन्दिर, निमावर, जिला देवास; जोगा किला, जोगा कलां, जिला होशंगाबाद नर्मदा बांध परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) से (च) चारों केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संबंध में यह निर्णय किया गया कि मान्धाता स्थित चौबीस अवतार मन्दिर को निकटवर्ती ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए; बाजीराव पेशवा की छतरी और रावेरखेड़ी, जिला खरगोन की सराय के लिए नदी के साथ ऊंची दीवार की जाए; जिला देवास, निमावर में बांध को मजबूत किया जाए और जिला होशंगाबाद में जोगा कलां स्थित जोगा किले की बुर्ज को और मजबूत किया जाए। फिर नर्मदा घाटी का विकास प्राधिकरण ने यह सुझाव दिया है कि चौबीस अवतार मन्दिर के अतिरिक्त बाजीराव पेशवा की छतरी भी किसी निकटवर्ती सुरक्षित ऊंचे स्थान पर पुनर्स्थापित कर दी जाए।

[अनुवाद]

सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के मध्य रेल मार्ग

2453. **श्री हरि किशोर सिंह** :

श्री नवल किशोर राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी को रेल लाइन द्वारा मुजफ्फरपुर से जोड़ने के लिए दो वर्ष पूर्व कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । वर्ष 1991 में ।

(ख) और (ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) लम्बाई : 62.72 कि० मी०

(ii) आमान : 1676 मि० मी० (ब० ला०)

(iii) अनुमानित लागत : 61.97 करोड़ रु०

प्रतिशत की ऋणात्मक दर तथा संसाधनों की तंगी के कारण लाइन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

राउरकेला-सम्बलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करना

2454. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण-पूर्व रेलवे के राउरकेला-सम्बलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) अब तक इस परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस परियोजना को शुरू करने और पूरा करने के लिए कब तक का समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राउरकेला से झारसुगुड़ा तक पहले ही दोहरी लाइन है । यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए झारसुगुड़ा-सम्बलपुर खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थायी विकास संबंधी आयोग

2455. **श्री के० वी० तन्कावालू** :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में रियो डी जेनेरो में पर्यावरण एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात् भी उत्तर और दक्षिण के बीच पारिस्थितिकी विवाद अभी तक चल रहा है;

(ख) क्या न्यूयार्क में पिछले महीने हुई पहली पश्चवर्ती-रियो बहुपक्षीय मंत्रीय बैठक में स्थाई विकास संबंधी आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उपरोक्त आयोग के उद्देश्यों, कृत्यों और रचना को अंतिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है । इन चर्चाओं में सतत् विकास आयोग की स्थापना का मुद्दा भी शामिल है । इस विषय पर न्यूयार्क में मंत्रियों की अलग से कोई बैठक नहीं हुई । तथापि नवम्बर, 1992 के पहले सप्ताह के दौरान उत्तर और दक्षिण दोनों के विभिन्न देशों के बहुत से मंत्रियों ने रियो सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम बहस में भाग लिया और इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए ।

प्रस्तावित सतत् विकास आयोग के विभिन्न पहलुओं पर अभी महासभा में चर्चा की जा रही है ।

कलकत्ता में परिक्रमा रेलवे

2456. **डा० असीम बाला** :

श्री तरित वरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में परिक्रमा रेलवे परियोजना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या परियोजना का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्वीकृत योजना के अनुसार दम-दम से प्रिंसेपघाट (13.5 कि० मी०) तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

(ग) और (घ) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के परामर्श से प्रिंसेबघाट से माजरहाट (5.5 कि० मी०) तक सर्कुलर रेलवे के विस्तार की व्यावहारिकता की जांच की गई थी, क्योंकि यह संरेखन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि से गुजरता है । कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण अपेक्षित भूमि को छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं ।

[हिन्दी]

सामुदायिक भोजन तथा पोषण एकक

2457. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यरत सामुदायिक भोजन तथा पोषण एककों को राज्यवार संख्या तथा उनके स्थानों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन एककों पर राज्य-वार किया गया अनुमानित व्यय कितना है;

(ग) क्या बिहार में रांची में ऐसे एकक सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) इस समय 43 सामुदायिक खाद्य और पोषाहार विस्तार यूनिट हैं जो अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली (3), एर्णाकुलम, फरीदाबाद, गंगतोक, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, लुधियाना, मद्रास, मदुरै, मंडी, मंगलौर, नागपुर, पणजी, पटना, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, सिलवासा, तिरूअनन्तपुरम, उदयपुर, वलसाड, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में कार्य कर रहे हैं।

(ख) ये यूनिट क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए हैं। 1991-92 के दौरान किया गया अनुमानित व्यय 1.6 करोड़ रुपये था।

इस व्यय का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

पूर्वी क्षेत्र	—	0.4 करोड़ रुपए
उत्तरी क्षेत्र	—	0.4 करोड़ रुपए
दक्षिणी क्षेत्र	—	0.4 करोड़ रुपए
पश्चिमी क्षेत्र	—	0.4 करोड़ रुपए
	जोड़ :	1.6 करोड़ रुपए

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

धूम्रपान न करने वाले यात्रियों के लिए सवारी डिब्बे

2458. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** :

श्री रामसिंह काछवां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धूम्रपान न करने वाले यात्रियों के लिए गाड़ियों में सवारी डिब्बे निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और यह नीति कितनी गाड़ियों में लागू की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर सिगरेट, बीड़ी, पान तथा पानमसाला की बिक्री पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। प्रयोग के तौर पर 18 गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी का एक-एक शयनयान धूम्रपान न करने वालों के लिए निर्धारित किया गया है। इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) सिगरेट, बीड़ी तथा पानमसाला की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। बहरहाल रेलवे स्टेशनों पर पान की बिक्री सीमित करने हेतु उपयुक्त अनुदेश मौजूद हैं तथा यथोचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जंगली भैंसे को गैर-कानूनी रूप से मारना

2460. **श्री के० तुलसियेया वान्डायार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूजर जनजाति द्वारा राजाजी अभयारण्य में जंगली भैंसों को गैर-कानूनी रूप से मारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों का वास-स्थल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को सी०जी०एच०एस० सुविधा

2461. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी सी०जी०एच०एस० की डिस्पेंसरियों से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन डिस्पेंसरियों के नाम क्या हैं, जहां से वे चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं के समान हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे किसी भी औषधालय या अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सूची संलग्न विवरण "क" में दी गई ?

(ग) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को हृदय रोग के उपचार को छोड़कर, कमोवेश ऐसी ही सुविधाएं स्काट्स इंस्टिट्यूट, बत्रा अस्पताल और नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध हैं।

(घ) सेवाओं में सुधार लाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए अपने औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/पॉलीक्लिनिकों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है कार्डधारक तथा कार्ड में दर्ज उस पर निर्भर सदस्य इस योजना के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे :

विवरण

औषधालयों की सूची

एलोपैथिक

1. बिजवासन, औषधालय
2. झील कुरंजा औषधालय
3. नांगलोई औषधालय
4. न्यू पुलिस लाइन औषधालय
   किंग्सवे कैम्प दिल्ली
5. पहाड़गंज औषधालय
6. जामा मस्जिद औषधालय
7. लाल कुआं औषधालय
8. श्री नारायण औषधालय
   लाहौरी गेट
9. सदर बाजार औषधालय
10. बाड़ा हिन्दू राव औषधालय
11. कश्मीरी गेट औषधालय
12. जंगपुरा औषधालय

13. आई० टी० आई० औषधालय

14. राजेन्द्र नगर औषधालय

15. करौल बाग औषधालय

16. म्यूनिसिपल औषधालय, तिहाड़

17. म्यूनिसिपल औषधालय आजादपुर

18. गूंका मार्ग औषधालय, रोशनआरा गार्डन के पास

19. शकूरबस्ती औषधालय

20. रमेश नगर औषधालय

21. म्यूनिसिपल औषधालय

22. माडल टाउन औषधालय

23. सुभाष नगर औषधालय

24. दौलतपुर औषधालय

25. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, सीलमपुर

26. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, पांडुनगर

27. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, नांगलोई

28. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, हस्टल, दिल्ली

29. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, रघुवीरपुरा

30. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, सीमापुरी

31 चन्द्र नगर, औषधालय

32. त्रिनगर, औषधालय

33. रैंगर पुरा औषधालय

34. छतरपुर औषधालय

35. चिराग दिल्ली औषधालय

36. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, बुद्ध नगर

37. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, सनलाइट कालोनी

38. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, श्रीनिवासपुरी

39. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, बजीरपुर

40. दिल्ला विकास प्राधिकरण औषधालय, मादीपुर

41. दिल्ली विकास प्राधिकरण औषधालय, मदनगीर

42. दिल्ली प्रशासन औषधालय, गुलाबी बाग

43. दिल्ली प्रशासन औषधालय, अरबिंद नगर

44. दिल्ली प्रशासन औषधालय, शोरा कोठी पहाड़ गंज

45. दिल्ली प्रशासन औषधालय, अजमेरी गेट

46. दिल्ली प्रशासन औषधालय, जनपुर

47. दिल्ली प्रशासन औषधालय, शाहबाद मुहम्मदपुर

48. दिल्ली प्रशासन औषधालय, सराय रोहिल्ला, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी

49. दिल्ली प्रशासन औषधालय, वेस्ट पटेल नगर

50. दिल्ली नगर निगम औषधालय, प्रताप नगर

51. दिल्ली प्रशासन औषधालय शास्त्री नगर

52. दिल्ली प्रशासन रनजीत नगर

53. दिल्ली प्रशासन औषधालय कमला नगर

54. दिल्ली प्रशासन औषधालय प्रेम नगर

55. पुल बंगश औषधालय, दिल्ली

56. लारेंस रोड औषधालय

57. मोतियाखान औषधालय

58. लक्ष्मी नगर (शकरपुर) औषधालय

59. कृष्णा नगर औषधालय

60. गीता कालोनी औषधालय

61. कालकाजी औषधालय

62. इन्द्रपुरी औषधालय

63. दिल्ली प्रशासन औषधालय खेड़ा कलां

64. दिल्ली प्रशासन औषधालय जौरथ

65. नगर निगम औषधालय, कीर्ति नगर

आयुर्वेदिक औषधालय

1. मोती बाग
2. सरोजिनी नगर
3. किदवई नगर
4. हल्दरपुर
5. आर्यपुरा
6. फार्मेसी निगम बोध
7. आजादपुर
8. कटरा खुशाल राय
9. न्यू राजेन्द्र नगर
10. गांधी नगर
11. पहाड़गंज
12. दरियागंज
13. पदम नगर
14. बल्लीमारान
15. तेलीवाड़ा
16. करोलबाग
17. छावला
18. माडल बस्ती
19. सीलमपुरी
20. पहाड़ी धीरज
21. अशोक नगर
22. मीलमपुर
23. बल्लावरपुर
24. भोगल
25. डबल फाटक (किशन गंज)
26. हेलम्बी

27. हरदयाल लाइब्रेरी

28. जवाहर नगर

29. नरायन दत्त (राम नगर)

30. पटौदी हाउस (दरिया गंज)

31. टाउन हाल

32. हैदरपुर

33. त्रिनगर

34. अंधा मुगल

35. कश्मीरी गेट

36. कलां मस्जिद

37. महरौली

38. नरेला

39. फाटक हब्शखान

40. चूड़ीवालान

41. शाहगंज

42. मोती बाग

होमियोपैथिक औषधालय

1. टिकड़ी खुर्द

2. शाहदरा

यूनानी औषधालय

1. चांदनी महल

सोनीपत-दिल्ली सैक्शन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

2462. **श्री रवि राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के सोनीपत-दिल्ली सैक्शन पर नवम्बर, 1992 में मालगाड़ी के पटरी से उतरने की कोई घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण थे; और

(ग) ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15-11-1992 को उत्तर रेलवे के सोनीपत-दिल्ली खंड के राठधना स्टेशन पर बटाला-सांगली फूडग्रेन स्टेशन के 5 माल डिब्बे पटरी से उत्तर गए थे।

(ख) रेलों को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) रेलपथ	=	26,07,850 रुपये
(ii) सवारी और माल डिब्बे	=	1,02,000 रुपये
(iii) सिगनल और दूर संचार	=	10,000 रुपये
जोड़	=	27,19,850 रुपये

एक माल डिब्बे का एक्सल जर्नल टूट जाने के कारण ये डिब्बे पटरी से उत्तरे थे।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(1) गतायु परिसम्पत्तियों विशेषकर रेलपथ, पुल और चल स्टाक के नवीकरण और पुनः स्थापन पर निरन्तर बल देना।

(2) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(3) टेलीकाम गियरों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों और रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं का गहन निरीक्षण करना।

(4) संवेदनशील कोटियों के कर्मचारियों जैसे ड्राइवरों और स्टेशन मास्टरों के कार्य संचालन पर कड़ी नजर रखना।

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश

2463. **श्री अन्ना जोशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान और अन्य राज्यों में, राज्यवार, केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु कितने विद्यार्थियों ने आवेदन दिया; और

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को दिल्ली और अन्य राज्यों मे, राज्यवार प्रवेश मिला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हापा स्टेशन पर "पिट" लाइन में दरार

2464. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजकोट डिवीजन में स्थित हापा स्टेशन पर "पिट" लाइन में दरार आने के कारण कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने यात्री मारे गए और रेलवे को कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाना

2465. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए औद्योगिक एकक की स्थापना हेतु कोई दूरी संबंधी सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित प्रमुख औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एककों को स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना न होने देने के लिए ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग किलो-मीटर माप के एक ट्रेपिजियम की शिनाख्त की गई है ।

(ग) ट्रेपिजियम में तीन बड़ी वायु प्रदूषक इकाइयां हैं जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सत्रह अभिनिर्धारित श्रेणियों में आती हैं ।

(घ) इनको अंतरित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इनके प्रदूषण का ताजमहल पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

2466. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

श्री सूरज भानु सोलंकी :

श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है और जिन पर कार्य शुरू हो गया है, उनकी अनुमानित लागत क्या है अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है और उन्हें पूरा करने का निर्धारित समय क्या है; और

(ग) अगले चरण के दौरान राज्य में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव नीचे दिए गये हैं :—

(i) ललितपुर-खजुराहो-सतना, रीवा-सिधी-सिंगरौली नई बड़ी लाइन ।

(ii) मालनपुर के रास्ते गुना-इटावा नई दिल्ली का पुनः संरेक्षण ।

(iii) ढल्लीराजहरा-जगदलपुर नई लाइन ।

(ख) मध्य प्रदेश की वे परियोजनाएं जिन्हें/अनुमोदित/कर दिया गया है और जिन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, नीचे दी गई हैं :—

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु० में)	प्रगति (30-9-92)	पूरा करने का वर्ष
1 2	3	4	5
1. सातना-रीवा (50 कि०मी०)	35.00	85%	92-93
2. गुना-इटावा (348.25 कि०मी०)	256.00	127 कि०मी० (गुना-शिवपुरी और ग्वालियर-पनिहार पहले ही खोल दी गई हैं ।	
		33 कि०मी० (विरलानगर-सनिचरा और शिवपुरी-खजूरी) खोलने का लक्ष्य 92-93 रखा गया है ।	
		समूची परियोजना पूरी करने का लक्ष्य 95-96 है ।*	
3. गोधरा-इंदौर, देवास-मक्सी (316 कि०मी०)	297.14	21% । देवास-मक्सी (चरण-1) (देवास-मक्सी) पूरा करने का लक्ष्य 93-94 है ।*	

1	2	3	4	5
			तत्पश्चातचरण 11 शुरू किया जाएगा ।*	
	दोहरीकरण			
4.	नर्मदा पुल	12.80	60%	92-93
5.	माताटीला-बसई	8.83	82%	92-93
6.	कीरतगढ़-काला आखर और भरतवाढ़-मेटपंजरा	69.42	70%	93-94*
7.	माही पुल	6.97	70%	93-94*
8.	शुजालपुर-काला पीपल	9.05	95%	92-93
9.	बैरागढ़-फंदा	16.20	15%	93-94*
10.	पीरूमरोह-बेड़छा और बोलाई-अकोदिया	22.60	20%	93-94*
	यातायात सुविधाएं			
11.	हबीदगंज-कोचिंग टर्मिनल	9.98	23%	94-95*

*बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों

(ग) जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य अगले चरण में शुरू किए जाने की संभावना है ।

[अनुवाद]

पोलियोग्रस्त व्यक्ति

2467. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलियोग्रस्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु में पोलियोग्रस्त व्यक्तियों की प्रतिशतता अधिक है;

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पोलियो के प्रकोप का सामना करने के लिए विशेष योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) वर्ष 1992 के दौरान सूचित किए गए पोलियो के रोगियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) तमिलनाडु में पोलियों की घटनाओं में कमी हुई है और यह 1987 में 4323 रोगियों से घटकर 1991 में 776 रोगी रह गई है जिससे तमिलनाडु में इस रोग की घटनाओं में पर्याप्त कमी का पता चलता है। रोग-प्रतिरक्षण सेवाओं को जारी रखने और उनमें तेजी लाने के अलावा राज्य सरकारों ने नियन्त्रण उपाय शुरू किए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मामलों की संख्या	वर्ष 1992 की अवधि के लिए जनवरी से
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	456	जुलाई
2. अरुणाचल प्रदेश	1	अगस्त
3. असम	+	—
4. बिहार	+	—
5. गोवा	18	सितम्बर
6. गुजरात	162	सितम्बर
7. हरियाणा	280	अगस्त
8. हिमाचल प्रदेश	0	जून
9. जम्मू और कश्मीर	0	मई
10. कर्नाटक	79	मई
11. केरल	33	सितम्बर
12. मध्य प्रदेश	82	मई
13. महाराष्ट्र	677	सितम्बर
14. मणिपुर	0	जून
15. मेघालय	2	जुलाई
16. मिजोरम	0	अगस्त

1	2	3	4
17.	नागालैंड	7	सितम्बर
18.	उड़ीसा	218	जुलाई
19.	पंजाब	69	अगस्त
20.	राजस्थान	346	जून
21.	सिक्किम	0	अगस्त
22.	तमिलनाडु	307	जुलाई
23.	त्रिपुरा	6	अगस्त
24.	उत्तर प्रदेश	357	जुलाई
25.	पश्चिम बंगाल	146	मई
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	सितम्बर
27.	चण्डीगढ़		
28.	दादरा और नगर हवेली	0	मार्च
29.	दमण और दीव	0	सितम्बर
30.	दिल्ली	1154	सितम्बर
31.	लक्ष्यद्वीप	0	सितम्बर
32.	पांडिचेरी	1	अगस्त
	कुल :	4401	

टिप्पणी : 0=शून्य, + उपलब्ध नहीं । आंकड़े अनन्तिम हैं ।

काजीपेट से हैदराबाद तक रेल लाइन का विद्युतीकरण

2468. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीपेट से हैदराबाद तक रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह परियोजना इस समय किस चरण में है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने में कितनी धन राशि और समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) काजी पेट-बीबीनगर खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। शेष खंडों पर विद्युतीकरण का कार्य लगभग समाप्त होने की अग्रिम अवस्था में हैं।

(ग) सम्भाव्यतः अपेक्षित राशि 30 करोड़ रु० है।

समाप्ति का लक्ष्य :—सितम्बर, 1993।

वित्तीय स्वायत्तता

2469. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय स्वायत्तता के लिए रेलवे की मांग की जांच करने हेतु तीन सदस्यों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन

2470. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली क्षेत्र में और अधिक रेलवे स्टेशन खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस में आगजनी की घटना

2471. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बरहन स्टेशन के पास अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस में आगजनी की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने गंभीर रूप से घायल हुए थे; और

(घ) सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को राहत के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) आग लगने के कारण का अभी पता नहीं लगा है ।

(ग) आग लगने की इस घटना के परिणामस्वरूप न तो कोई व्यक्ति मारा गया और न ही कोई घायल हुआ । बहरहाल, सवारी डिब्बे से उतरते समय अभागे यात्री अप रेलपथ पर आ गए और वे एक कपल्ड इंजन से कुचले गए । परिणामस्वरूप 11 व्यक्ति मारे गए और 5 व्यक्ति घायल हुए ।

(घ) मारे गए व्यक्तियों के संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 24,250/- रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

शाहगंज और अमेठी के बीच रेल संपर्क

2472. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में शाहगंज जं० से अमेठी तक बरास्ता कादीपुर और सुल्तानपुर रेल लाइन बिछाने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त लाइन के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य कब किया गया था और इस बारे में भू-अधिग्रहण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आठवीं योजना के दौरान कुल कितनी नई रेल लाइनें बिछाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का शाहगंज-अमेठी योजना को पूरा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) शाहगंज-सुल्तानपुर-अमेठी बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण 1982-83 में किया गया था । भूमि अधिग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए प्रस्तावित लाइन पर प्राप्त होने वाले यातायात को पर्याप्त नहीं समझा गया ।

(ग) योजना आयोग द्वारा नई लाइन परियोजनाओं के लिए परिव्यय वार्षिक आधार पर आवंटित किया जाता है । तदनुसार नई लाइन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है तथा उन्हें

वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया जाता है जो अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले रेल बजट दस्तावेजों का भाग है।

(घ) और (ङ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अमरावती से नारखेड़ तक रेल लाइन

2473. **श्री तेजसिंह राव भोंसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में अमरावती से नारखेड़ तक एक रेल लाइन बिछाने के संबंध में घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को करने के लिए कुछ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1992-93 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि पिछले क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, इस नई लाइन से संबंधित प्रस्ताव को योजना आयोग के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। तदनुसार ऐसा किया गया था। बहरहाल, योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

2474. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे की मुरादाबाद डिवीजन में अनुकम्पा के आधार पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ख) क्या ऐसे अनेक मामले अभी भी लंबित पड़े हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवोदय विद्यालयों पर खर्च

2475. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नवोदय विद्यालयों पर राज्यवार प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : गत तीन वर्षों में नवोदय विद्यालयों पर राज्यवार प्रति वर्ष होने वाले खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में नवोदय विद्यालयों पर राज्यवार प्रतिवर्ष होने वाला खर्च

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वास्तविक व्यय		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	270.92	355.07	492.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	61.59	51.43	91.39
3.	बिहार	372.11	480.73	619.92
4.	गोआ	20.12	30.13	43.86
5.	गुजरात	85.24	112.33	150.02
6.	हरियाणा	124.73	157.80	195.41
7.	हिमाचल प्रदेश	128.34	172.49	193.97
8.	जम्मू और कश्मीर	143.34	179.19	235.55
9.	कर्नाटक	247.72	316.91	404.29
10.	केरल	142.85	223.78	259.18
11.	मध्य प्रदेश	323.43	414.02	557.56
12.	महाराष्ट्र	261.49	344.23	435.38
13.	मणिपुर	77.30	113.25	150.02
14.	मेघालय	36.17	38.15	58.16
15.	मिजोरम	17.63	22.84	32.53
16.	नागालैंड	12.16	14.05	23.14
17.	उड़ीसा	171.21	205.62	267.32
18.	पंजाब	99.44	126.74	158.17
19.	राजस्थान	254.58	337.21	433.64
20.	सिक्किम	9.24	14.19	15.21

1 2	3	4	5
21. त्रिपुरा	13.39	14.66	18.81
22. उत्तर प्रदेश	402.42	526.93	727.29
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28.85	36.48	33.26
24. चंडीगढ़	9.79	18.17	18.73
25. दिल्ली	10.24	12.66	23.00
26. दमन और दीव	12.38	16.68	20.48
27. दादर और नगर हवेली	14.35	14.83	16.51
28. लक्ष्यद्वीप	8.13	18.21	10.01
29. पाण्डिचेरी	54.56	65.37	76.98
कुल :	3414.04	4434.15	5762.21

(निर्माण-कार्य पर खर्च की गई पूंजी इसमें शामिल नहीं है)

सामान की ढुलाई

2476. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल द्वारा भेजे गये सामान की सुपुर्दगी देते समय फार्म 31/32 देना शुरू करने का है जैसाकि सड़क द्वारा भेजे गये सामान के मामले में किया जाता है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल द्वारा सामान की सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्तियों के लिए उ० प्र० सरकार द्वारा निर्धारित फार्म 31/32 प्रस्तुत करने पर बल दिए जाने से माल शेडों/पार्सल कार्यालयों के कामकाज में बाधा पड़ेगी जिसके परिणामस्वरूप सुपुर्दगी करने में विलम्ब होगा और माल शेडों में भीड़भाड़ होगा।

रेल द्वारा ढोए जाने वाले सामान पर बिक्री कर के अपवचंन के मामले पकड़ने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए इस आश्रय के अनुदेश मौजूद हैं कि स्टेशन रिकार्डों से सूचना उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्राधिकृत बिक्री कर पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग

दें। रेलें, परेषकों परेषितियों से सम्पर्क करने तथा उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बिक्रीकर पदाधिकारियों को मालशेडों और पार्सल कार्यालयों अथवा सिटी बुकिंग एजेंसियों और आउट एजेंसियों में जाने की सुविधा भी देती हैं।

[अनुवाद]

अम्लों तथा रसायनों की बुकिंग

2477. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अम्लों तथा रसायनों की छोटी खेपों में बुकिंग को स्वीकार करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) जी, हां। अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के पण्यों की ढुलाई के लिए माल डिब्बों का स्टार बनाये रखने तथा उनकी मांग पूरी करने की दृष्टि से, 16-7-1991 से "फुटकर" के रूप में एसिड और रसायन सहित माल यातायात की बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मामले की जांच की गई है। फुटकर और पार्सल के रूप में ऐसे परेषण स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

आर० यू०-486 गोली

2478. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात गोली आर० यू०-486 (माइफेप्रिस्टोन) का बाजार में लाने से पूर्व परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) गोली आर० यू०-486 (माइफेप्रिस्टोन) की आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में क्लिनिकी जांच की जा रही है और इसे बेचने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है।

बंगलौर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाना

2479. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-निजामुद्दीन एक्सप्रैस के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर देर रात पहुंचने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए इस गाड़ी को नई दिल्ली स्टेशन तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नई दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण ।

[हिन्दी]

सेकेन्ड्री स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण

2480. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 21 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित सैकेन्ड्री स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी विशेषज्ञों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रारूप रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

पालिटेक्निकों में अनुसूचित जाति/जनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश

2481. **श्री शशि प्रकाश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न पालिटेक्निकों में सामान्य श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को प्रवेश दिगा गया;

(ख) क्या ये छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को उपलब्ध लाभ ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली के पालिटेक्निकों में चालू वर्ष में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी अ०जा०/अ०ज०जाति के उम्मीदवार ने दाखिला प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और पर्यावरणीय आयोजन एवं समन्वय संगठन

2482. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और पर्यावरणीय आयोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन संगठनों के बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उद्देश्य संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (घ) जहां तक भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल का संबंध है, इसकी कार्य-प्रणाली की शासी बोर्ड और भारतीय वन प्रबंध संस्थान की सोसाइटी द्वारा इनकी नियमित बैठकों में बार-बार समीक्षा की जाती है। संस्थान में नियमित निदेशक न होने के कारण वहां कुछ समस्याएं रही हैं। तथापि, उस कठिनाई पर काबू पा लिया गया है और संकाय को सुदृढ़ बनाने, वानिकी प्रबन्ध कार्यक्रमों की कवरेज और विषय-वस्तु को व्यापक बनाने और अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य चल रहा है।

पर्यावरण सुरक्षा और समन्वय संगठन में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केन्द्र के प्रारम्भ से ही इसकी कार्य-प्रणाली की मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और इसका कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

विवरण

भारतीय वन प्रबंध संस्थान तथा पर्यावरण सुरक्षा और समन्वय संगठन, भोपाल की स्थापना के उद्देश्य

1. **भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल** :

संस्थान के मुख्य उद्देश्य, सेवारत वन अधिकारियों, वन विकास निगमों और वनों से संबंधित उद्योगों के अधिकारियों को वानिकी प्रबंध में उच्च प्रशिक्षण देना है ताकि वे वानिकी विकास के प्रबंध

की कला और व्यवस्था को सीखने वानिकी तथा वनों से संबंधित प्रणालियों में प्रबंध उत्तरदायित्व वाले व्यवसायों के लिए उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली युवा लोगों को चुनने और उन्हें तैयार करने योग्य बन सकें। यह संस्थान एक स्नातकोत्तर वानिकी प्रबंध डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है।

2. **पर्यावरण सुरक्षा और समन्वय संगठन** :

यह संगठन मध्य प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त निकाय है।

भारत सरकार ने अपनी पर्यावरण सूचना प्रणाली स्कीम के तहत पर्यावरण सुरक्षा और समन्वय संगठन में 1984 में एक पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केन्द्र की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रबंध के क्षेत्र में सूचना का संग्रहण, मिलान, भण्डारण, निकासी और उपभोक्ता वर्ग में प्रचार करना है।

मगरमच्छों की मृत्यु

2483. **श्री गुरुदास कामत** : **क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुकरैल प्रजनन केन्द्र में इस वर्ष अनेक मगरमच्छों की अकस्मात् मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पोषण नीति

2484. **श्री गोपीनाथ गजपति** : **क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय पोषण नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मोटे अनाज का आयात

2585. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : **क्या खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को स्थानीय लोगों के उपभोग के लिए मोटे अनाज का सीधा आयात करने की छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली राजसहायता की राशि कितनी है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किस सीमा तक परिणाम प्राप्त किए जाने हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नयी सहकारी चीनी मिलें

2486. **श्री दत्ता मेघे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी मिलों की परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या इस वित्तीय प्रावधान को पर्याप्त समझा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस धनराशि को बढ़ाये जाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ताकि इन चीनी मिलों को वित्तीय संस्थानों से अधिक ऋण मिल सके ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केन्द्र सरकार किसी भी चीनी परियोजना के लिए, चाहे वह सहकारी क्षेत्र की हो या अन्य क्षेत्र की, धनराशि का आवंटन नहीं करती है। चीनी फैक्ट्रियों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदि से धन प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट स्वयं तैयार करनी होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट के लिए सहायता

2487. **श्री वी० एस० विजयाराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के पलाक्काड जिले में नेलोयामपठी में मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैगनों (रेल डिब्बों) तथा कोचों का निर्माण

2488. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में रेल डिब्बों/यात्री कोचों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ख) लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण प्रतिवर्ष योजना आबंटन और यातायात प्रक्षेपणों के आधार पर किया जाता है। बहरहाल, आठवीं योजना अवधि के लिए मोटे तौर पर 1,20,000 माल डिब्बों (चौपहिया यूनिट के हिसाब से) और 9100 सवारी डिब्बों की खरीद का अनुमान लगाया गया है।

(ख) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए देश में ही पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

[हिन्दी]

बाल कल्याण हेतु संगठन

2489. **श्री छीतूभाई गामीत** :

श्री महेश कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में इन संस्थाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) गुजरात में बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न प्रमुख संस्थाओं/संगठनों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कुछ आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं में खाद्य आहारों की खरीद के बारे में और कार्मिकों की भर्ती में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें गुजरात राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये गए हैं।

विवरण

विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के विवरण

क्रम सं०	संस्था/स्वयंसेवी संगठनों के नाम	कार्यान्वित की जा रही बाल कल्याण योजना का नाम
1	2	3
1.	भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, रेडक्रास भवन, सूचक रोड, राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
2.	गंगली ट्रस्ट, हाइवे रोड, राधानपुर, जिला बनस्कंधा	समेकित बाल विकास सेवा योजना
3.	लोक सेवा समाज ट्रस्ट, उषा, दासी जीवनपुरा, राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
4.	सौराष्ट्र कल्याण ट्रस्ट, रेडक्रास भवन, राजकुमार कालेज के सामने, राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
5.	पुतलीबा उद्योग मंदिर, भक्तिनगर, सर्कल, गीतामंदिर के सामने, राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
6.	सारस्वतम, पी० बी० नं० 7, मांडवी, जिला-कच्छ	समेकित बाल विकास सेवा योजना
7.	सेवा ग्रामीण, झगदिया, जिला-भरूच-393110	समेकित बाल विकास सेवा योजना
8.	कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, कस्तूरबा गांधी मार्ग, हमनमर	समेकित बाल विकास सेवा योजना
9.	मेडिकल केयर सैण्टर ट्रस्ट, बाल अस्पताल, करेलीबाग, बड़ौदा	समेकित बाल विकास सेवा योजना
10.	अहमदाबाद सहर समाज, शिक्षण समिति, मजूर कल्याण केन्द्र भवन, महिपातरम आश्रम के सामने, रायपुर, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना

1	2	3
11.	अनसूयाबेन साराभाई स्मारक ट्रस्ट, गांधी मजूर सेवालय, भादरा, पी० बी० नं० 10, अहमदाबाद ।	समेकित बाल विकास सेवा योजना
12.	गुजरात बाल कल्याण संघ, डिमावन, पाल्वी, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
13.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, द्वारा जिला समाज कल्याण संघ, भादरा, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
14.	गुजरात केलावनी ट्रस्ट, एस० वी० कालेज कम्पाऊंड, रिलीफ रोड, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
15.	काका बा और कलाबुद्ध पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, काका बा हत्पताल, ब्लाक नं० 33, उतराज, तालुका हंसोट, जिला-भरुच	समेकित बाल विकास सेवा योजना
16.	महिला सेवा ट्रस्ट, सेवा स्वागत केन्द्र, विक्टोरिया गार्डन के सामने, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
17.	भारतीय परिवार नियोजन संघ, संगीता, घेबर भाई रोड, नजदीक गुरूकुल, राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
18.	विकास विद्यालय कल्याण ग्राम, शोभेन्द्र, रोड, मोरबी, जिला राजकोट	समेकित बाल विकास सेवा योजना
19.	विकास गृह, पाल्दी, धूमकेतू मार्ग, अहमदाबाद-380007	समेकित बाल विकास सेवा योजना
20.	लोक सेवा मंडल, सी० एच० भगत छत्रालय, विकास गृह के समीप, पाल्दी, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना

1	2	3
21.	भारतीय परिवार नियोजन संघ, नशाबंदी कम्पाऊंड, लाल दरवाजा, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
22.	नूतन भारती, मदनगढ़, पालनपुर, जिला-बानस्कंथा	समेकित बाल विकास सेवा योजना
23.	डा० अम्बेडकर ट्रस्ट, 21/ए, मयूर को-आप हाऊसिंग सोसाइटी, रेलवे क्रासिंग के पीछे, कलोल, जिला महेसाना	समेकित बाल विकास सेवा योजना
24.	गांधी आश्रम, जिलिया, ताल, चांस्मा जिला-महेस ना-384225	समेकित बाल विकास सेवा योजना
25.	रावलयोगी उत्तेजक मंडल, द्वारा नवजीवन आश्रम स्कूल, डाकखाना मुकुन्द, तालुका पतन, जिला महेसान	समेकित बाल विकास सेवा योजना
26.	केलवनी मंडल, धासा, तालुका-गाडवा, जिला-भावनगर	समेकित बाल विकास सेवा योजना
27.	विकास विद्यालय, वधावन, वधावन सिटी, जिला-सुरेन्द्र नगर	समेकित बाल विकास सेवा योजना
28.	श्री वाघोडिया युवक मंडल, ज्योतिधाम, वाघोडिया, जिला-बड़ौदा 391760	समेकित बाल विकास सेवा योजना
29.	श्री न्यू नरोत्तम लाल भाई, ग्रामीण विकास फण्ड, अहमदाबाद	समेकित बाल विकास सेवा योजना
30.	श्री वाघोडिया तालुका, ग्रामीण विकास मंडल, वाघोडिया, जिला-बड़ौदा	समेकित वाल विकास सेवा योजना
31.	त्रिभुवनदास फाऊन्डेशन, राजोदपरा, चिखोदरा रेलवे क्रासिंग के नजदीक, आनन्द-377001 गुजरात	आनन्द पद्धति परिवार कल्याण परियोजना
32.	रचनात्मक अभिगम न्यास, "हार्दिक" प्रेरणा पार्क सोसाइटी, एल० जी० हस्पताल के सामने, मणिनगर, अहमदाबाद-8	महिला एवं बाल कल्याण परियोजना

1	2	3
33.	गुजरात केलवनी न्यास, एस० बी० कालेज कम्पाऊंड, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380001	महिला एवं बाल कल्याण परियोजना
34.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	शिशु-गृह/बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
35.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली	शिशु-गृह/बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
36.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
37.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, इन्दौर	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
38.	श्री जामनगर जिला समाज कल्याण संघ, पण्डित नेहरु मार्ग, जामनगर	शिशुगृह
39.	मंगल भारती विद्यापीठ, डाकखाना भदुरपुर जिला-साबरकंथा	शिशुगृह
40.	भारतीय समाज कल्याण, परिषद, नगरपालिका बाल भवन, पाल्दी, अहमदाबाद	शिशुगृह

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

2490. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई रेल-परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य लाइनें बिछाने मीटर गेज लाइनों और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने, लाइनों को दोहरा करने हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में इस समय चल रही रेल परियोजनाओं, तथा परियोजनाओं के नाम, कुल अनुमानित लागत, 1992-93 में इनके लिए नियत की गई राशि और प्रत्येक परियोजना पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा संस्तुत रेल परियोजनाओं और उन पर की गई कार्यवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना	की गई कार्रवाई
1. होसपेट-हुबली-अंकोला रेल लाइन	होसपेट-हुबली के आमान परिवर्तन कार्य को 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है। हुबली-अंकोला के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। आगे का निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
2. बागलकोट-मंगलोर लाइन का आमान परिवर्तन	इसमें से गदग-हुबली-अरसीकेरे 1992-93 के बजट में पहले से ही स्वीकृत है। शेष भाग को कार्य में शामिल किया गया है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
3. बेंगलूर-बेलगाम लाइन का आमान परिवर्तन	इसे अनुमोदित कर दिया गया है और 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है।
4. कोट्टूर-हरिहर लाइन	इस लाइन के लिए सर्वेक्षण अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 1992-93 में शामिल किया गया है।
5. बेंगलुरू सर्कुलर रेलवे	शहरी परिवहन यह एक नई योजना होने के कारण, इस सर्कुलर रेलवे के निर्माण के लिए स्थानीय प्राधिकरणों/राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित केन्द्रीय सहायता, यदि कोई हो, के लिए वे शहरी विकास मंत्रालय से सम्पर्क करें जो शहरी परिवहन के मामले में नोडल मंत्रालय है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित किये गये सर्वेक्षण इस प्रकार हैं :—

(i) हुबली-अंकोला नई बड़ी लाइन।

(ii) सेलम और बेंगलूरु के बीच मीटर लाइन का आमान परिवर्तन।

(iii) हरपानाहल्ली के रास्ते कोट्टूर-हरिहर के बीच लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

(iv) हरपानाहल्ली के रास्ते गदग और हरिहर के बीच वैकल्पिक लाइन के सर्वेक्षण।

(v) तेल्लीचेरी और मैसूर के बीच नई लाइन।

(vi) मंगलोर और मडगांव (325 कि०मी०) के बीच वैस्ट कोस्ट कोंकण लाइन के लिए अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण।

(vii) रायचूर के रास्ते गडग-गडवाल के बीच नयी लाइन ।

(घ) कर्नाटक में चालू कार्य और उनकी उपस्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	1992-93 के दौरान परि-व्यय (करोड़ रुपयों में)	प्रगति का प्रतिशत (30-9-92)
	नई लाइनें			
1.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग *	40.90	17.00	40%
	आमान परिवर्तन			
2.	मैसूर-बेंगलूरु और बेंगलूरु-येलहंका	102.56	8.00	पूरी कर दी गई 35%
3.	बेंगलूरु-हुबली (यशवंतपुर-अरसीकेरे चरण-1)	235.00	62.00	30%
4.	मिरज-लोंडा *	122.00	1.00	—
5.	होसपेट-हुबली गोवा *	312.00	1.00	—
	दोहरी लाइन बिछाना			
6.	कुप्पम-व्हाइटफील्ड	108.11	3.00	—
7.	रायचूर-मटमारी और कोसगी-कुपल *	22.43	1.00	यातायात के लिए खोली गई
8.	थानगुंडी-चेगुंटा	29.16	0.16	92%
9.	तांदूर-मलखेड रोड *	35.94	2.45	87%
10.	मलखेड रोड-वाडी	20.13	1.52	78%
	रेल विद्युतीकरण			
11.	जोलारपेट्टै-बेंगलूरु सिटी*	50.00	1.44	90%

* अंशत: कर्नाटक में ।

इसमें चिकजाजूर-बेल्लारी मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शामिल है ।

तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन

2491. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौंद्रम** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सितंबर तक देश में हुए चीनी के कुल उत्पादन में तमिलनाडु का कितना भाग है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीना के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में चीनी मौसम 1991-92 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान हुए चीनी के कुल 132.77 लाख टन (अनंतिम) उत्पादन में से तमिलनाडु की चीनी फैक्ट्रियों ने 12.55 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो देश में हुए कुल उत्पादन का 9.45 प्रतिशत है।

(ख) चीनी मौसम 1991-92 के दौरान तमिलनाडु की चीनी फैक्ट्रियों ने 12.55 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जबकि चीनी वर्ष 1990-91 के दौरान यह उत्पादन 11.83 लाख टन था। इस प्रकार तमिलनाडु की चीनी फैक्ट्रियों के उत्पादन में 6.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर)		उत्पादन (लाख टन)
1988-89	—	10.04
1989-90	—	8.89
1990-91	—	11.83

उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए छात्र

2492. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान उच्च अध्ययन के लिए देश-वार कितने छात्रों को विदेश भेजा गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए प्रत्येक छात्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शैक्षणिक वर्ष 1992-93 के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा सीधे ही संचालित द्विपक्षी

कार्यक्रमों और सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के तहत अब तक 114 छात्र विदेश भेजे गए जिसके देश-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

अरब गणराज्य अमीरात (मिश्र)	1
आस्ट्रेलिया	1
कनाडा	18
चीन	9
चेकोस्लोवाकिया	6
फ्रांस	1
हंगरी	1
आयरलैंड	2
इटली	8
जापान	13
नार्वे	8
पोलैंड	1
पुर्तगाल	1
यू०के०	44
कुल :	144

(ख) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अब तक भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित खर्च की अदायगी की जानी है :

(i) जवाहर लाल नेहरू स्मारक (यू०के०) छात्र-वृत्तियों के तहत दो छात्रों का नई दिल्ली से लन्दन की यात्रा का किराया	54,442 रु०
(ii) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत चीन को भेजे गए 9 छात्रों की यात्रा का किराया	1,61,447
(iii) चीन में 9 छात्रों के अनुरक्षण खर्च को	1,27,003
कुल :	3,42,892

कलकत्ता/हावड़ा के उपनगरीय स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

2493. **श्री अमल दत्त :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह कलकत्ता/हावड़ा क्षेत्र के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन स्टेशनों पर वर्ष 1992-93 के दौरान यात्री सुविधाओं में सुधार करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) किसी स्टेशन पर निर्धारित मानदण्डों के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती है जो स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात पर निर्भर करती हैं। तदानुसार, सियालदह/कलकत्ता/हावड़ा क्षेत्र में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म सायबान (यदि आवश्यक हो), पीने का पानी, बुकिंग और बैठने की व्यवस्था इत्यादि जैसी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध है।

(ख) 1992-93 के दौरान 12 स्टेशनों पर पैदल ऊपरि पुलों, 34 स्टेशनों पर प्लेटफार्म सायबान, 25 स्टेशनों पर बेंचों, 10 स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, 74 स्टेशन पर मूत्रालयों, 53 स्टेशनों पर शौचालयों, 32 स्टेशनों पर पानी के नल, 36 स्टेशनों पर नलकूपों, 25 स्टेशनों पर बिजली तथा 14 स्टेशनों पर जल शीतकों की सुविधाओं की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है। जहां तक 1992-93 के दौरान इस प्रयोजन के लिए धन आवंटित करने का संबंध है उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के लिए रेलें अलग से कोई धन आवंटित नहीं करती हैं।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आडियो कैसेट

2494. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर छोटा उदयपुर में ऐसी संस्थाओं की संख्या क्या है जिनको विकलांगों की शिक्षा के संबंध में एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रदान की गई ऑडियो कैसेटों का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत एक ही संस्थानों में विकलागों तथा सामान्य बच्चों को साथ-साथ पढ़ाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने गुजरात की किसी भी संस्था को विकलांगों की शिक्षा के लिए आडियो कैसेट नहीं दिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार अपंग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य आम स्कूलों में अपंग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है।

योजना के अन्तर्गत, आम स्कूलों में अपंग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं का सृजन करने के लिए तथा अपंग बच्चों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, ट्रांसपोर्ट, वर्दी, उपस्कर आदि के लिए विभिन्न भत्ते प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों/स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों को वेतन, संसाधन कमरों का गठन, अपंग बच्चों का मूल्यांकन करना, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुशिल्पीय रुकावटों को दूर करने तथा शैक्षणिक सामग्री तैयार करने का व्यय भी वहन किया जाता है।

यह योजना गुजरात में 799 स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए 566 स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक कालेज

2495. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निजी संस्थाओं को इंजीनियरिंग कालेज जैसे स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक कालिज खोलने की अनुमति देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में तथा संशोधित) में स्वीकृत मानदण्डों और उद्देश्यों के अनुसार तकनीकी शिक्षा में निजी स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने पर बल दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन

2496. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है,

(ख) चालू-वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकारों को, राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु देश में विशेषकर राजस्थान में प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए आवंटन निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रु०)
(i) अनौपचारिक शिक्षा	750.00
(ii) प्रौढ़ शिक्षा	1400.00

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए राज्य क्षेत्र में प्रारंभिक (जिसमें अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल हैं) तथा प्रौढ़ शिक्षा के वास्ते राज्यवार किए गए आवंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केन्द्रीय क्षेत्र में राज्यवार कोई आवंटन नहीं किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन (अनुबंध-I) की आवश्यकताओं के आधार पर अनुदान जारी किए जाते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों के लिए औपचारिक शिक्षा, तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका उद्देश्य 15-35 आयुवर्ग के सभी प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, यह सब सारे देश में सामान्य तौर पर और विशेषरूप से राजस्थान में, निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2377	665
2.	अरूणाचल प्रदेश	2280	72
3.	असम	7689	311
4.	बिहार	9040	1011
5.	गोआ	540	45
6.	गुजरात	1538	355
7.	हरियाणा	3440	159
8.	हिमाचल प्रदेश	1826	100
9.	जम्मू और कश्मीर	3000	168
10.	कर्नाटक	7194	350

1	2	3	4
11.	केरल	436	20
12.	मध्य प्रदेश	11708	780
13.	महाराष्ट्र	3946	297
14.	मणिपुर	582	47
15.	मेघालय	1680	86
16.	मिजोरम	457	34
17.	नागालैण्ड	306	12.60
18.	उड़ीसा	3000	800
19.	पंजाब	853	200
20.	राजस्थान	4995	160
21.	सिक्किम	644	10
22.	तमिलनाडु	3050	1300
23.	त्रिपुरा	1500	75
24.	उत्तर प्रदेश	9922	550
25.	पश्चिम बंगाल	4546	500
26.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	438	4.60
27.	चण्डीगढ़	132	10
28.	दादरा और नगर हवेली	90	0.60
29.	दमन और दीव	86.87	2.25
30.	दिल्ली	5262.70	122.90
31.	लक्षदीप	34.21	2.76
32.	पांडीचेरी	215	10
	कुल :	92801.78	8066.21

इलेक्ट्रानिक मीडिया पर परिवार कल्याण कार्यक्रम

2497. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री के० तुलसिऐया वान्डयार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया विशेषत: इसके क्षेत्रीय नेटवर्क पर धारावाहिक लघु फिल्में, लघु, कहानियां लघु नाटक और लघु वार्ताएं प्रायोजित करने के लिए कोई कार्य योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) संगठित क्षेत्र में गर्भ निरोधक नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य योजनाएं वार्षिक आधार पर तैयार की जाती हैं जिनमें देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए गए अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार सम्बन्धी कार्यकलापों के साथ-साथ राष्ट्रीय नेटवर्क तथा क्षेत्रीय नेटवर्क पर इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों से धारावाहिक, लघु फिल्में, नाटक लघु चर्चाएं, स्पाट्स और जिंगल्स जैसे कार्यकलाप प्रायोजित करने को बढ़ावा दें ।

(ग) भारत सरकार ने परिवार कल्याण नियोजन संबंधी त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति के जरिए संगठित क्षेत्र से अनुरोध किया है कि वे परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए गर्भनिरोधक युक्तियों के वितरण को बढ़ावा दें ।

गार्ड रहित गाड़ियां शुरू करना

2498. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही गार्ड रहित गाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ये गाड़ियां शुरू की जाएगी; और

(ग) ये गाड़ियां किस सीमा तक रेल दुर्घटनाओं से मुक्त होंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर बिना गार्डों के गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दालों की कमी

2499. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजार में दालों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) स्वदेश में दालों का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः आयात-निर्यात नीति के अधीन दालों का आयात करने की खुली छूट दे दी गई है।

(ख) देश में 1986-87 से केन्द्र द्वारा सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना और केन्द्रीय क्षेत्र विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-दालें कार्यान्वयनाधीन हैं ताकि देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, दालों का आयात करने की खुली छूट दे दी गई है।

गुजरात में रेलवे फाटक

2500. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने स्थानों पर सिंचाई नहरों के ऊपर रेलवे फाटकों का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर यह कार्य समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15।

(ख) जी, हां।

(ग) दो स्थानों पर कार्य राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमान की स्वीकृति संसूचित न करने के कारण निर्धारित लक्ष्य से पीछे है और एक स्थान पर इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित केनाल ब्लाक की व्यवस्था न कर पाने के कारण योजना संशोधित करनी पड़ी थी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद दो से तीन वर्ष।

डा० मेघनाद साहा की जन्म शती

2501. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री सुदर्शन रायचौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक डा० मेघनाद साहा की जन्म शती मनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विकास) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शताब्दी मनाई जाएगी।

(ख) और (ग) ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

हृदय चिकित्सा में रोग निदान संबंधी उपकरण

2502. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वाध्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले सभी बड़े अस्पतालों के हृदय-चिकित्सा विभागों में हृदय सम्बन्धी विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए रोग-निदान सम्बन्धी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हृदय रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) हृदय रोगियों को बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों में चरणबद्ध ढंग से नवीनतम उपस्कर लगाए जा रहे हैं और उनमें वृद्धि की जा रही है ।

विवरण

सफदरगंज अस्पताल :

1. कम्प्यूटरीकृत ट्रीड मिल मशीन
2. ट्रांस-थोरेसिक और ट्रांस इसोफेजियल

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान :

1. कलर डोप्लर सहित इको कार्डियोग्राफी
2. कार्डियक केथेटेराइजेशन और एंजियोग्राफी प्रयोगशालाएं
3. ऐवसरसाइज प्रयोगशाला
4. होल्टर प्रयोगशाला
5. न्यूक्लीयर कार्डियोलाजी प्रयोगशाला
6. इलेक्ट्रोफिजियोलाजी प्रयोगशाला

7. हृदय जैव-रसायन प्रयोगशाला
8. हृदय विकृति विज्ञान प्रयोगशाला
9. कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल :

1. कलर डोप्लर
2. होल्टर मशीन
3. टी० एम० टी० मशीन

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल :

1. ई० सी० जी० कार्डियक मानीटर, डी० सी०
2. शाक; और
3. ईको कार्डियोग्राफिक सुविधाएं

जी० बी० पन्त अस्पताल :

1. दो डिजिटल इमेजिंग सहित 3 केथेटेराइजेशन प्रयोगशालाएं
2. डोप्लर और कलर डोप्लर ट्रांसपोसोफेजियल ईको कार्डियोग्राफी सहित दो डाइनेशनल ईकोकार्डियोग्राफी
3. कम्प्यूटरीकृत ट्रेड मिल
4. एम्बूलेटरी होल्टर मानीटरिंग
5. अस्थायी और स्थायी पेसमेक प्रत्यारोपण
6. केथेटर एबलेशन संबंधी सुविधाओं सहित इन्ट्राकार्डियक इलेक्ट्रोफियोलाजी
7. कार्डियक एररिथिमिक्स की शल्य चिकित्सा के लिए कम्प्यूटरीकृत इन्ट्राआपरेटिव मैपिंग सिस्टम
8. इन्ट्रावास्कूलर एंजियो स्कोपी
9. आर्थियामिक्स के निदान के लिए लेटेक्स पोटेन्शियल रिकार्डिंग
10. रक्त लेबल+औषधों की मानीटरिंग करने के लिए एच० पी० एल० सी०
11. 12 लीड इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी।

गुरु तेग बहादुर अस्पताल :

1. इको कार्डियोग्राफी कलर डापर के साथ वेल्वुलर लेसन्स/इंजेक्शन फ्रेवशनकोरोनरी आर्टेरी विजुअलाइजेशन के प्रयोग के लिए।

2. ट्रेडमिल टेस्ट (टी० एम० टी०) उपस्कर

3. एक 3-डी और सिंगल चैनल ई० सी० जी० मशीन

4. छह पलंगों वाले सी० सी० यू०-सेंट्रल टेलीमेटरी और डेफिबुलेटर्स एण्ड वेड साइड मानीटर के साथ ।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली :

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के हृदयरोग विज्ञान विभाग में एक आधुनिक कोरोनरी केस यूनिट है जिसमें हृदय रोगियों की परिचर्या के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं ।

कक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना पर व्यय

2503. **श्री महेश कनोडिया** :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

प्रो० प्रेम धूपल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार ने स्कूलों में कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान और अध्ययन तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना पर वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना व्यय किया;

(ख) इससे लाभान्वित स्कूलों की राज्य वार संख्या क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1992-93 में "शैक्षिक प्राद्योगिकी" स्कीम के अन्तर्गत 14 करोड़ रु० की राशि तथा स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) परियोजना के लिए 4 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है । विवरण में उल्लिखित कारणों से राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है ।

विवरण

चूंकि शैक्षिक प्रौद्योगिकी और "क्लास" परियोजना दो भिन्न-भिन्न स्कीमें हैं अतः इनका अलग-अलग विवरण दिया गया है ।

(क) क्लास परियोजना (रु० करोड़ रुपयों में)

किया गया व्यय	1989-90	1990-91	1991-92
	6.19	6.86	5.95

राज्य-वार कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है क्योंकि इस परियोजना को सी० एम० सी० लि० तथा एन० सी० ई० आर० ही के माध्यम से हाल ही में चालू किया गया है ।

अब तक 2598 स्कूल शामिल कर लिए गए हैं। इन स्कूलों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	सम्मिलित स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	159
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	आसाम	112
4.	बिहार	150
5.	गुजरात	153
6.	हरियाणा	64
7.	हिमाचल प्रदेश	39
8.	जम्मू और कश्मीर	52
9.	कर्नाटक	140
10.	केरल	104
11.	मध्य प्रदेश	145
12.	महाराष्ट्र	237
13.	मणिपुर	12
14.	मेघालय	13
15.	मिजोरम	10
16.	नागालैंड	14
17.	उड़ीसा	126
18.	पंजाब	116
19.	राजस्थान	120
20.	सिक्किम	12
21.	तमिलनाडु	115
22.	त्रिपुरा	12

1	2	3
23.	उत्तर प्रदेश	276
24.	पश्चिम बंगाल	228
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9
26.	चण्डीगढ़ प्रशासन	11
27.	गोवा	13
28.	दादर और नागर हवेली	6
29.	दिल्ली प्रशासन	80
30.	लक्षद्वीप	9
31.	पांडिचेरी	9
32.	दमन और दीव	1

(ख) शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्कीम (रु० करोड़ में)

किया गया व्यय	1989-90	1990-91	1991-92
	36.50	15.02	14.00

उपर्युक्त आंकड़ों में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान इत्यादि के माध्यम से किया गया व्यय भी शामिल है ।

राज्यवार आवंटित राशि विवरण-I में दर्शाई गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों को रेडियो कम कैसेट प्लेयर के 100/- अनुदान तथा रंगीन टेलीविजन की लागत के लिए अनुमोदित दर पर 75/- केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । स्कूलों को आपूर्ति किए गए रंगीन टी० वी०/आर० सी० सी० पी० का राज्य वार विवरण-2 में दिया गया है । राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता क्योंकि राज्य सरकारें अपनी वास्तविक जरूरतों के मुताबिक ही अपने प्रस्ताव भेजती हैं ।

विवरण I

वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 के दौरान रंगीन टेलीविजन/रेडियो एवं कैसेट्स प्लेयर्स के लिए स्वीकृत राशि

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
1.	आंध्र प्रदेश	1,13,00,219	2,27,90,181	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,14,400	—	—
3.	असम	42,20,400	73,52,282	—
4.	बिहार	8,33,125	—	—
5.	गोआ	1,76,000	5,29,474	—
6.	गुजरात	1,73,65,000	96,18,750	—
7.	हरियाणा	39,89,680	50,00,000	—
8.	हिमाचल प्रदेश	45,80,400	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	17,82,000	1,02,99,285	—
10.	कर्नाटक	66,37,200	15,81,000	1,09,01,600
11.	केरल	27,87,000	—	12,17,480
12.	मध्य प्रदेश	30,45,800	29,15,999	—
13.	महाराष्ट्र	93,00,000	1,26,20,000	4,40,92,147
14.	मणिपुर	1,21,200	10,08,350	16,19,350
15.	मेघालय	4,23,000	5,00,000	5,08,000
16.	मिजोरम	9,12,750	—	71,340
17.	नागालैंड	7,71,525	—	—
18.	उड़ीसा	1,28,79,738	2,58,25,000	—
19.	पंजाब	48,22,800	60,00,000	—

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	91,91,750	—	36,71,250
21.	सिक्किम	1,88,000	3,49,700	—
22.	तमिलनाडु	70,00,000	1,00,00,000	—
23.	त्रिपुरा	17,200	5,700	—
24.	उत्तर प्रदेश	20,84,207	—	3,26,02,848
25.	पश्चिम बंगाल	12,97,200	—	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32,000	50,000	—
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	48,438	1,11,137	—
28.	दिल्ली प्रशासन	—	—	—
29.	दादरा और नागर हवेली	22,000	—	36,000
30.	दमन और दीव	12,000	—	—
31.	लक्षदीप	12,800	—	—
32.	पांडिचेरी	1,22,800	—	—
		10,60,90,552	11,65,56,858	9,46,60,015

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	संस्वीकृत रंगीन टेलीविजन सेट्स की संख्या			संस्वीकृत रेडियो एवं कैसट, प्लेयर की संख्या		
		1989-90	90-91	91-92	1989-90	90-91	91-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	900	2,716	—	—	10,000	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	3,527	7,354	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—
5.	गोआ	—	—	—	—	312	—
6.	गुजरात	920	1,500	—	2,000	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—	3,520	5,000	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	3,866	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	1,500	7,863	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	—	—	—	4,500	1,581	10,902
11.	केरल	—	—	—	2,787	—	1,217
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	4,000	10,000	10,000	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	938	1,390
15.	मेघालय	—	—	—	363	500	508
16.	मिजोरम	—	—	—	400	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	500	—	—
18.	उड़ीसा	979	2,000	—	5,000	13,000	—
19.	पंजाब	—	—	—	3,500	6,000	—
20.	राजस्थान	—	—	—	3,500	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	269	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	5,000	10,000	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	2,000	—	—	14,400
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	50	—
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	—	16	—	—	16	—
28.	दिल्ली प्रशासन	—	—	—	—	—	—
29.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	36
30.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
31.	लक्षदीप	—	—	—	—	—	—
	योग :	2,799	6,232	6,000	49,963	72,883	28,453

वायु और ध्वनि प्रदूषण

2504. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) महानगरों में प्रदूषण में वृद्धि के लिए वाहन प्रदूषण और घरेलू अपशिष्ट मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) महानगरों में परिवेशी और जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(3) महानगरों की वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

(5) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों का पता लगाया गया है और इन्हें एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं।

(6) केन्द्रीय सरकार की गंगा कार्य योजना के तहत मलजल एवं जल निकासी प्रणाली के निर्माण/उसे बेहतर बनाने और मलजल शोधन की स्कीम शुरू की गई है।

(7) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने और उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(9) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत वर्ष 1995 के लिए सभी वाहनों हेतु ठोस और द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयो को 1 मार्च, 1990 से ठोस उत्सर्जन मानक लागू करने की सलाह दी है।

(10) वाहन प्रदूषण के बारे में जन-जागरुकता अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष

2505. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत गुजरात के किन-किन रेलवे स्टेशनों पर यात्री यातायात की भीड़भाड़ को देखते हुए विश्राम कक्षों एवं अन्य यात्री सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है;

(ख) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्य शुरू हो गया है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ये सुविधाएं गुजरात में अन्य स्टेशनों पर कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विश्राम कक्षों सहित रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है जिन्हें यातायात संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि होने पर, जब कभी अपेक्षित होता है, शुरू किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, अहमदाबाद, आनन्द, अंकलेश्वर, भरुच, भुज, भावनगर, द्वारका, गोधरा, गांधीधाम, गोंडल, गांधीग्राम, जामनगर, जूनागढ़, मेहसाना, मोरवी, पालनपुर, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्र नगर, बलसाड, बडोदरा, वीरमगाम, वेरावल और वापी पर विश्राम कक्ष सुविधा उपलब्ध हैं। यातायात की मात्रा के अनुरूप अन्य यात्री सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई हैं। इसके अलावा गुजरात राज्य में निम्नलिखित यात्री सुविधा के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन और निर्माण कार्य का वितरण	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	बडोदरा-आरक्षण कार्यालय की व्यवस्था	37.37
2.	संजाण-22 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म नं० 1, 2 और 3 का विस्तार	16.60

1	2	3
3.	मरोली-22 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म नं० 2 और 3 तथा 12 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म नं० 1 का विस्तार	23.18
4.	सूरत-कवरिंग ओवर प्लेटफार्मों का विस्तार	33.46

उपर्युक्त यात्री सुविधा संबंधी निर्माण कार्यों के अतिरिक्त सूरत, अहमदाबाद और गांधीधाम में प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था/का विस्तार, हापा में प्लेटफार्म सतह को ऊंचा करना, नवसारी, संजाण और चंदलोदिया में प्रतीक्षालयों में सुधार, सूरत, न्यू जामनगर और राजकोट में जल शीतकों की व्यवस्था, दाहोद में विश्राम कक्षों, हापा में बुकिंग कार्यालयों और संजाण और वीरपगाम में ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था जैसे अन्य निर्माण कार्य भी शुरू किए गए हैं। ये सभी निर्माण-कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों में हैं और 1993-94 तक इनके पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

अन्य स्टेशनों पर यातायात आवश्यकताओं में वृद्धि होने पर जब कभी अपेक्षित होगा निर्माण-कार्य शुरू किए जाएंगे बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में दवाइयों की सप्लाई

2506. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों में मानव दवाइयां सप्लाई करने के एक समान मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय औषधालयों में घटिया स्तर की दवाइयों की सप्लाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय द्रविण अध्ययन संस्थान

2507. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 11 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5243 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय द्रविण अध्ययन संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकारों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित संस्थान एक निजी संस्थान होगा अथवा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एक संस्थान अथवा इच्छुक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोजित संस्थान होगा; और

(ग) प्रस्तावित संस्थान का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) तमिलनाडु सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हो गई है, परन्तु केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) इस प्रस्ताव में एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक संस्था की परिकल्पना की गई है जिसे केन्द्रीय सरकार और चार दक्षिण राज्यों अर्थात केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ।

(ग) संप्रवर्तकों के अनुसार, प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य, द्रविण भाषाओं, साहित्य, संस्कृति, सर्जनात्मक कलाओं, विज्ञान आदि पर अन्तरविषयक अनुसंधान आरम्भ करना और उसको बढ़ावा देना है ।

[हिन्दी]

जाली रेल टिकट

2508. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रेल अधिकारियों की मिली-भगत से जाली रेल टिकटों की बड़ी संख्या में खुले आम बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जाली टिकटों की बिक्री तथा बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए वाणिज्यिक तथा सतर्कता विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफार्मों तथा चलती गाड़ियों में

बार-बार जांच की जाती है, जिन मामलों में बाहरी व्यक्ति शामिल होते हैं वहां राजकीय रेलवे पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता भी ली जाती है। गर्मियों में भीड़-भाड़ तथा दुर्गा पूजा के दौरान ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। दलालों और अप्राधिकृत स्रोतों से टिकट खरीदना, रेल अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गैरकानूनी तथा दण्डनीय होने के कारण उन्हें न खरीदने के लिए जनता को मीडिया तथा लाउड स्पीकरों द्वारा शिक्षित किया जाता है।

[अनुवाद]

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पी०सी०ए०) अधिनियम 1960 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड

2509. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पी०सी०ए०) अधिनियम, 1960 के क्रियान्वयन हेतु कोई राज्य सलाहकार बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य राज्यों में ऐसे बोर्डों का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे जीव जन्तु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन करें। ये बोर्ड जीव-जन्तु कल्याण से संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकारों को सलाह देंगे, जीव-जन्तु कल्याण से जुड़े मामलों पर संगठनों/सोसाइटियों को दिशा-निर्देश जारी करेंगे तथा भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड को इस क्षेत्र में जीव-जन्तु कल्याण गतिविधियों को समन्वित करने में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की सहायता करेंगे।

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ प्रशासन, दादरा और नगर हवेली तथा मिजोरम सरकारों ने पहले ही राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन कर लिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल परियोजना

2510. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सेक्शनों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ङ) इसके लिए अब तक क्या प्रावधान किया है;

(च) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(छ) क्या राज्यों ने अपना-अपना हिस्सों की राशि दे दी है और यदि नहीं तो राशि न देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ख) (i) दो खण्डों, अर्थात् मंगलोर-उदुपि (70 कि०मी०) और रोहा-वीर (दासगांव) का निर्माण-कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है और इन्हें क्रमश: दिसम्बर, 92 तथा जनवरी, 93 में यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है ।

(ii) वीर-उदुपि (643 कि० मी०) शेष खंड के निर्माण-कार्य की प्रगति लगभग 21% है ।

(ग) सरकारी बांडों के लिए बाजार की स्थिति कठिन होने के कारण, संसाधन जुटाने में कुछ विलम्ब हुआ है । बांडों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, उन पर ब्याज की दर 9% से बढ़ाकर 10-1/2% कर दी गई है ।

(घ) 1800 करोड़ रुपये ।

(ङ) अभी तक इक्विटी के रूप में 351 करोड़ रुपये तथा बांडों के रूप में 650 करोड़ की व्यवस्था की गई है । इक्विटी के रूप में शेष 49 करोड़ रुपये तथा बांडों के रूप में 750 करोड़ रुपये आगामी वर्षों में जुटाये जाएंगे ।

(च) 1994-95 के दौरान, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(छ) सभी राज्य सरकारों ने वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए अपने अंशदान की पूरी रकम का भुगतान कर दिया है । वर्ष 1992-93 के सम्बन्ध में भुगतान की अन्तिम तारीख 31-3-1993 है ।

[हिन्दी]

बलोतरा और पचपादरा के बीच रेल लाइन को क्षति

2511. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलोतरा और पचपादरा के बीच रेल लाइन 1990 के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ियों को चलाने हेतु इसकी मरम्मत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, 1990 में रेत की दरारें पड़ गई थीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चूंकि यह एक अलाभप्रद शाखा लाइन है जिसे बन्द करने की रेल सुधार समिति ने सिफारिश की थी इसलिए वैकल्पिक सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता तथा रेलपथ मरम्मत की ऊंची लागत को देखते हुए इस खंड पर गाड़ी सेवा बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हाथियों की मृत्यु

2512. **श्री शिवराज सिंह चौहान** :

श्री मोहन लाल झिकराम : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राष्ट्रीय वन से कुछ हाथियों को हाल ही में जंगली हाथियों को पकड़ने हेतु सरगुजा भेजा गया है;

(ख) क्या उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं की गई और उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बों के स्थान पर वातानुकूलित शयन कोच लगाना

2513. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में कुछ वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बों के स्थान पर वातानुकूलित शयन कोच लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, 31 दिसम्बर, 1992 से बेंगलूर से और 2 जनवरी 1993 से निजामुद्दीन से वातानुकूल कुर्सीयान के स्थान पर वातानुकूल शयनयान लगाया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

2514. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **पर्यावरण तथा वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर गन्दी बस्ती क्षेत्रों का दौरा करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों में वर्ष 1991-92 के दौरान 31 अक्टूबर, 1992 तक किये गये दौरों तथा उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास योजना

2515. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए आठवीं योजना के दौरान कितनी राशि नियत की गई है अथवा नियत किए जाने का विचार है; और

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देने के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय की योजना में पोषाहार से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आवश्यक रूप से पोषाहार संवर्धन के लिए होती हैं।

स्वास्थ्य देखरेख के लिए विश्व बैंक सहायता

2516. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु 500 मिलियन डालर की धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत किन-किन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस सहायता में से प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र (सोशल सेफ्टी नेट), जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल है, के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के आई० डी० ए० क्रेडिट के लिए विश्व बैंक के साथ हाल ही में बातचीत हुई थी। इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक के बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी बैठक 27 दिसम्बर, 1992 को होनी निश्चित हुई है। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, प्राथमिक शिक्षा और पोषण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय नवीकरण निधि शामिल है।

(ग) राज्यों के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

सम्बलपुर स्टेशन

2517. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उड़ीसा में कोई माडल स्टेशन नहीं है;

(ख) क्या सम्बलपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्वी रेलवे के पास काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिमी उड़ीसा में आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए किसी भी स्टेशन को नहीं चुना गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम शक्ति में कमी

2518. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का इस शताब्दी के अन्त तक मानव शक्ति में चालीस प्रतिशत कटौती लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हापा-अहमदाबाद में इण्टर सिटी रेलगाड़ी को बड़ौदा तक चलाना

2519. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जामनगर, राजकोट, बड़ौदा और मुम्बई के यात्रियों से मुम्बई, दिल्ली और देश के अन्य भाग में जाने हेतु और यात्रियों की आवाजाही कम करने की सुविधा प्रदान करने हेतु हापा-अहमदाबाद इण्टर सिटी रेलगाड़ी को बड़ौदा तक चलाये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों और मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) श्री चन्द्रेश पटेल, श्री एन० एन० बिकारिया, श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला (संसद सदस्य), श्री परमानन्द खट्टर (सदस्य विधान सभा), श्री नलिन भट्ट (सदस्य विधान सभा), श्री शशिकान्त लखानी (उद्योग, विधि एवं न्याय मंत्री, गुजरात सरकार), श्री जालावाड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, राजकोट चैम्बर आफ कामर्स, गुजरात चैम्बर आफ कामर्स फेडरेशन आफ कच्छ सौराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, सेन्ट्रल गुजरात चैम्बर आफ कामर्स, नवानगर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा जामनगर रीजन पैसेंजर एसोसिएशन ने 9153/9154 हापा/राजकोट अहमदाबाद एक्सप्रेस को वडोदरा तक बढ़ाने का अभ्यावेदन भेजा है ।

(ग) जांच की गई परन्तु ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

सर्कस में पशुओं पर प्रतिबन्ध लगाना

2520. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सर्कस में पशुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्कस से आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार सरकार ने भालुओं, बन्दरों, बाघों और तेंदुओं के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । भारतीय सर्कस संघ द्वारा इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है तथा उच्च न्यायालय ने मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक इन आदेशों को स्थगित कर दिया है ।

(ग) प्रतिबन्ध आदेशों के लागू हो जाने के बाद भी सर्कस प्रतिबन्धित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों के स्टेज प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। केवल इस प्रकार के जीवों के प्रशिक्षकों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का पता लगाना होगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अन्तः शिरा द्रव्य का निर्माण

2521. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अन्तः शिरा द्रव्य के निर्माण हेतु खासतौर पर किसी एकक का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस एकक को बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस एकक को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। इस एकक की स्थापना से लाइन और स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर जैसी अन्य मदों के साथ-साथ अन्तः शिरा द्रवों का विनिर्माण करने के लिए 1975-76 में की गई। इस एकक की स्थापना एक बार में 450-500 बोतलें तैयार करने की क्षमता से उस समय की गई जब दबारा इस्तेमाल की जाने वाली शीशे की बोतलों की उपलब्धता के कारण यह किफायती था।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि यह एकक कार्यरत है और ऐसे विशिष्ट घोलों का विनिर्माण कर रहा है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

क्विलोन-मदुरा रेल लाइन

2522. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्विलोन-मदुरा सीधी रेल लाइन निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में रेल सड़क परिवहन में समन्वय

2523. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की उपनगरीय दैनिक सेवा तथा उपनगरीय स्टेशनों पर सड़क परिवहन के बीच समन्वय हेतु वर्तमान प्रबन्ध क्या है तथा यह प्रबन्ध कितना प्रभावी/पर्याप्त है;

(ख) कुल उपनगरीय स्टेशनों में कितने स्टेशनों पर पूरक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) अन्य स्टेशनों पर पूरक परिवहन सेवाएं उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) ऐतिहासिक रूप से पूर्व रेलवे के उपनगरीय खंड पर कलकत्ता को सेवित करने वाली रेल लाइन और सड़क नेटवर्क का साथ-साथ विकास हुआ है। कलकत्ता क्षेत्र के अधिकांश उपनगरीय स्टेशनों का सड़क फीडर प्रणाली से पर्याप्त मेल है। उपनगरीय स्टेशनों और सड़क परिवहन नेटवर्क की फीडर सेवाओं का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ है। बहरहाल, ऐसे विकास में निर्देश तथा समन्वय के लिए कोई नोडल प्राधिकरण नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में अध्यापकों और छात्रों को छात्रवृत्ति

*2524. **श्री एन०जे०राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्यापकों और छात्रों को जर्मनी में अपने अध्ययन हेतु वर्ष 1993-94 के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितने आवेदन, विशेषरूप से गुजरात से, प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस छात्रवृत्ति हेतु चयन किए गये अध्यापकों और छात्रों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इण्डो-जर्मन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत जर्मन संघीय गणराज्य ने 1993-94 के लिए शिक्षा विभाग को 9 शिक्षावृत्तियां प्रदान की हैं। देश भर से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम चयन अभी किया जाना है। चार आवेदन पत्र गुजरात से प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग के पास भारत-जर्मन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा/अनुसंधान के लिए जर्मनी में प्रत्येक वर्ष शिक्षक भेजने की एक योजना है। वर्ष 1993-94 के लिए चयन 1992-93 के दौरान किया जाएगा। वि०अ०आ० द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से अगस्त, 1992 में आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे और डी० ए० ए० डी० छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1993-94 के तहत गुजरात से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास

2525. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्वरूप में पर्याप्त सुधार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नवीकरण योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधीय जड़ी बूटियां

2526. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में और अधिक औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के लिए 1992-93 में वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने राजस्थान सरकार को 1992-93 के दौरान औषधीय पादपों सहित लघु वन्य उत्पाद की खेती करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन 29.00 लाख रुपये की रकम मंजूर की है। 12 लाख रुपये की रकम का भुगतान पहले ही कर दिया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी "अधिक पैदावार और स्वीकार्य औषधीय गुणवत्ता के लिए सफेद मुसली के उपयुक्त कल्चर के विकास" पर एक तदर्थ योजना तैयार की है जिसे राजस्थान कृषि कॉलेज, उदयपुर में चलाया जा रहा है और 1992-93 में लगभग 2·14 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। औषधीय और एरोमेटिक पादपों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अधीन उदयपुर केन्द्र हेतु 1992-93 के लिए 7.00 लाख रुपये का अनंतिम परिव्यय है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

2527. **श्री कांशी राम राणा :**

श्री छीतूभाई गामीत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना के अन्तर्गत गुजरात में कौन-कौन से उद्योगों का पता लगाया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : कार्य योजना के अन्तर्गत गुजरात में जिन उद्योगों की पहचान की गई है वे शिनाख्त किए गए 17 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की बड़ी और मझौली इकाइयां हैं। ये इकाइयां सीमेंट, ताप-विद्युत, मद्य निर्माण, चीनी, उर्वरक, इस्पात, तेल शोधक कारखाना, कॉस्टिक सोडा, चमड़ा, पेट्रो-रसायन, लुगदी और कागज, सलफ्यूरिक एसिड,

कीटनाशक, बेसिक ड्रग्ज एवं फार्मेस्युटिकल्स तथा रंग और रंग अन्तस्थ की श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां हैं ।

बिना टिकट यात्रा करना

2528. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए रेल विभाग ने कितने अचानक/दण्डाधिकारीय छापे मारे;

(ख) ऐसे यात्रियों से कुल कितने राजस्व की वसूली की गई;

(ग) क्या मासिक सीजन टिकट धारकों पर आरक्षित कोचों में घुसने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1992 से सितम्बर, 1992 तक 5.31 लाख बार जांच की गई ।

(ख) रेलवे को देय 23.95 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई ।

(ग) और (घ) नियमों के अनुसार मासिक सीजन टिकटधारियों को आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है । बहरहाल, दैनिक यात्रियों की सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीजन टिकटधारियों को कतिपय खंडों पर कुछ गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है ।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं की स्वीकृति

2529. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :

श्री योगानन्द सरस्वती :

श्री हरीश नारायण प्रभु भ्रांटेय :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

श्री याइमा सिंह युमनाम :

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

मे० जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

श्री सुखेन्दु खान :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत् एक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई विकास परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान अस्वीकृत परियोजनाओं के राजस्वार नाम क्या हैं;

(ग) सरकार के पास स्वीकृति हेतु आज तक लंबित विकास परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितने वन-क्षेत्र का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में बिलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) विवरण (I, II, III संलग्न है ।)

(ङ) राज्य सरकारों से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद अन्तिम विर्णय लेने के लिए प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की जाती है ।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिला	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे० में)	अनुमोदित करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सोबरसिरी	डिकरोंग पावर स्टेशन से बिरला सब-स्टेशन तक 400 किलोवाट डी/सी ट्रांसमिशन	67.6	16-7-92
2.	आन्ध्र प्रदेश	खाम्माम	खनन पट्टे का नवीनीकरण	0.50	26-11-91
3.	आन्ध्र प्रदेश	रंगा-रेड्डी	पशु वध गृह का निर्माण	0.15	18-9-92
4.	आन्ध्र प्रदेश	हित्तूर	हवाई अड्डा प्राधिकरण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण	0.04	20-3-92
5.	असम	कामरूप	चन्द्रपुर ताप विद्युत गृह से सरिस्का तक 200 कि० वाट डी/सी पारेषण लाइन	32.02	12-8-92
6.	असम	कामरूप	लांगपी से गुवाहाटी तक 200 कि०वाट लाइन	30.255	17-8-92

1	2	3	4	5	6
7.	असम	गोलपारा	सालाकाटी से अगिया तक 20 कि०वाट डी/सी पारेषण लाइन	26.5	17-8-92
8.	बिहार	सिंहभूम	400 कि.वाट जमशेदपुर राउरकेला पारेषण लाइन	20.258	1-7-92
9.	बिहार	सिंहभूम	2400 कि.वाट लाइन बिछाना	0.9978	8-5-92
10.	गोआ	दक्षिण गोआ	सम्पर्क मार्ग	0.967	15-9-92
11.	गोआ	दक्षिण गोआ	मार्ग का निर्माण	0.099	15-9-92
12.	गुजरात	भड़ौच	नहर का निर्माण	0.5936	3-12-91
13.	गुजरात	सूरत	अवरोध बंध का निर्माण	0.33	24-12-92
14.	गुजरात	वडोदरा	शाखा नहर का निर्माण	0.2142	17-1-92
15.	गुजरात	साबरकंठ	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.016	17-1-92
16.	गुजरात	जामनगर	पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन	0.01618	17-1-92
17.	गुजरात	अंकलेश्वर	पुल का निर्माण	0.05	17-1-92
18.	गुजरात	वडोदरा	शाखा नहर का निर्माण	0.1739	17-1-92

1	2	3	4	5	6
19.	गुजरात	वडोदरा	डोरा शाखा नहर का निर्माण	0.225	17-1-92
20.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शाखा नहर का निर्माण	0.1152	17-1-92
21.	गुजरात	भड़ौच	अमलेश्वर शाखा नहर का निर्माण	0.2192	17-1-92
22.	गुजरात	वडोदरा	देवार शाखा नहर का निर्माण	0.1607	24-1-92
23.	गुजरात	वडोदरा	गलीकुण्ड क्षेत्रीय पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन बिछाना	0.706	5-3-92
24.	गुजरात	वडोदरा	नीमता में शाखा नहर का निर्माण	0.34	24.3-92
25.	गुजरात	जूनागढ़	बिखरे पत्थरों का संकलन	0.95	20-4-92
26.	गुजरात	वडोदरा	नाहरा शाखा नहर का निर्माण	0.1260	20-4-92
27.	गुजरात	वडोदरा	मिजागमा शाखा नहर	0.23	3-7-92
28.	गुजरात	जूनागढ़	गुजरात के राज्य के लिये मेनटेनिंग केन्द्र	0.80	3-7-92
29.	गुजरात	वडोदरा	नर्मदा प्रोजेक्ट पर सकारदा शाखा का निर्माण	0.1288	7-7-92
30.	गुजरात	भड़ौच	सौसर्द गांव में लूवरा नहर का निर्माण	0.60	7-7-92

1	2	3	4	5	6
31.	गुजरात	वडोदरा	बड़ौदा नगर में पेयजल पाइप लाइन	0.6750	9-7-92
32.	गुजरात	मेहसाना	मार्ग का निर्माण	0.03	9-7-92
33.	गुजरात	भड़ौच	अम्बेश्वर शाखा नहर	0.2128	9-7-92
34.	गुजरात	भड़ौच	टनकारिया गांव में लूवरा शाखा नहर	0.1648	9-7-92
35.	गुजरात	पंचमहल	सिंचाई/पेयजल पाइपलाइन बिछाना	0.831	9-7-92
36.	गुजरात	भड़ौच	वगसा गांव में शाखा नहर	0.3136	9-7-92
37.	गुजरात	सूरत	पिक अप वियर का निर्माण	0.50	29-6-92
38.	गुजरात	वडोदरा	सकरादा शाखा नहर	0.1180	29-6-92
39.	गुजरात	जामनगर	कच्छ की खाड़ी द्वितीय तेल ताप विद्युत की स्थापना	9.6	9-1-92
40.	गुजरात	वडोदरा	खनन पट्टे का नवीकरण	22.5	31-1-92
41.	गुजरात	पंचमहल	मुख्य नहर का निर्माण	29.722	30-4-92
42.	गुजरात	डांग	सामान्य प्रयोजन के लिए भूमि	1947.26	30-4-92
43.	गुजरात	वनासकंठ	घांटे गांव के पी०टी० का निर्माण	4.70	6-5-92
44.	गुजरात	पंचमहल	66 किलोवाट रबाड़ी-देवगढ़ बिजली लाइन	2.142	30-4-92

1	2	3	4	5	6
45.	गुजरात	डांग	11 किलोवाट पारेषण लाइन	20.119	6-7-92
46.	गुजरात	डांग	11 किलोवाट पारेषण लाइन	21.025	6.7-92
47.	गुजरात	बनासकंठ	मार्ग का निर्माण	1.00	24-7-92
48.	गुजरात	पंचमहल	सुखी नहर का निर्माण	12.286	24-7-92
49.	गुजरात	बनासकंठ	कपसिया गांव में मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण	26.35	31-7-92
50.	गुजरात	भड़ौच	ने० हाइवे 1 पर 204/0 से 208/0 तक 4 सड़कों के लिए भूमि	4.80	15-10-92
51.	गुजरात	बनासकंठ	कामपुरा में एस०आई० स्कीम का निर्माण	7.28	16-10-92
52.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	दरालघाट में सीमेंट संयंत्र की स्थापना	102.8	13-2-92
53.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	तहतोली स्टैण्डर्स रोड	1.45	21-5-92
54.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	दसौट-देदरा कवर आर०ई०सी० प्रोजेक्ट से 22 किलोवाट एच०टी० लाइन	7.5	1.10-92
55.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गाज पन विद्युत परियोजना	11.9872	14-11-92
56.	हरियाणा	करनाल	एच.एस.डी आउटलेट को सम्पर्क मार्ग	0.012	14-1-92
57.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला-कालका रोड को चौड़ा बनाना	0.13	6-11-91

1	2	3	4	5	6
58.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला-कालका रोड पर ले-बाई का निर्माण	0.5928	11-12-91
59.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला कालका रोड पर 8.330 कि०मी० का चैक बैरियर	0.6612	27-1-92
60.	हरियाणा	फरीदाबाद	एल०पी०जी० गोदाम	0.0928	9-4-92
61.	हरियाणा	रोहतक	सैलटैक्स बैरियर के लिए ले-बाई रोड का निर्माण	0.315	29-4-92
62.	हरियाणा	फरीदाबाद	बैथल घतली रोड के साथ-साथ नाले का निर्माण	0.105	29-7-92
63.	हरियाणा	करनाल	ने० हाइवे और औद्योगिक मार्ग जंक्शन पर वन भूमि का उपयोग	0.170	4-8-92
64.	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला-कालका रोड पर 44.310 कि०मी० जंक्शन का सुधार	0.291	25-8-92
65.	हरियाणा	करनाल	एन०डी०एफ०सी० सविरेज की स्थापना	0.0024	22-9-92
66.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	रज्जू मार्ग की स्थापना	0.40	28-2-92
67.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी	निरीक्षण कुटी का निर्माण	0.05	6-5-92
68.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	भूकम्पमापी की स्थापना	0.1301	25-8-92

1	2	3	4	5	6
69.	हिमाचल प्रदेश	लाहुल और स्पीति	कम्पनी हेडक्वाटर ऑफ एस०एस०सी० का निर्माण	0.252	25-8-92
70.	मध्य प्रदेश	शैहडोल	एस०ई०सी०एल० द्वारा पाइपलाइन बिछाना	0.0444	17-1-92
71.	मध्य प्रदेश	रायसेन	गाय सुरक्षा केन्द्र	0.960	24-2-92
72.	मध्य प्रदेश	भोपाल	गैस पीड़ितों के लिए भवन का निर्माण	0.2	25-2-92
73.	मध्य प्रदेश	सतना	मध्य प्रदेश मिनरल प्रोसेसिंग प्रा०लि० के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	2.500	23-1-92
74.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	डब्ल्यू०सी०एल० (टण्सी प्रो०) द्वारा कोयले का भूमिगत खनन	299.44	20-11-91
75.	मध्य प्रदेश	सतना	मैसर्स मध्य प्रदेश मिनरल प्रोसेसिंग नहर को चूना-पत्थर के लिए खनन पट्टे का नवोनीकरण	2.720	23-1-92
76.	मध्य प्रदेश	सिधी	एन०सी०एल० लि० जयन्त प्रोजेक्ट द्वारा कोयला खनन के लिए भूमि	100.00	23-3-92
77.	मध्य प्रदेश	शिवनी	ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए बांधवगढ़ रा०उ० का विस्तार	216.226	14-5-92
78.	मध्य प्रदेश	सतना	मैसर्स मेहर सीमेंट कं० को चूना-पत्थर का खनन	5.00	18-5-92

1	2	3	4	5	6
79.	मध्य प्रदेश	सतना	मै० मेहर सीमेंट कं० के लिए ओवर लैण्ड वेल्ट कन्वेयर सिस्टम की स्थापना	4.00	18-5-92
80.	मध्य प्रदेश	सतना	मेहर सीमेंट कम्पनी के लिए चूना-पत्थर का खनन	2.374	18-5-92
81.	मध्य प्रदेश	सतना	मेहर सीमेंट कम्पनी के लिए चूना-पत्थर का खनन	14.585	18-5-92
82.	मध्य प्रदेश	सतना	मेहर सीमेंट कम्पनी के लिए चूना-पत्थर का खनन	103.398	19-5-92
83.	मध्य प्रदेश	रायगढ़	लोअर सिरपाड़ी प्रोजेक्ट	3.110	23-6-92
84.	मध्य प्रदेश	सतना	पत्थर खनन के लिए बाण सागर परियोजना	20.00	23-6-92
85.	मध्य प्रदेश	बस्तर	डोर्डे टैंक	4.04	23-6-92
86.	मध्य प्रदेश	शैहदोल	कठोसिया टैंक	4.468	23-6-92
87.	मध्य प्रदेश	शैहदोल	अमझर टैंक	1.704	23-6-92
88.	मध्य प्रदेश	बस्तर	सोनापुर टैंक	5.001	23-6-92
89.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	गुडबिडा टैंक प्रोजेक्ट	4.13	17-7-92
90.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	बेदखलियों का पुनर्वास	72.00	17-7-92

1	2	3	4	5	6
91.	मध्य प्रदेश	रायसेन	रामपुरा टैंक प्रोजेक्ट	17.98	17-7-92
92.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	अमादही टैंक प्रोजेक्ट	41.04	17-7-92
93.	मध्य प्रदेश	रायपुर	बोदरा बाघा टैंक प्रोजेक्ट	72.41	17-7-92
94.	मध्य प्रदेश	रायसेन	पारसोरा टैंक प्रोजेक्ट	47.438	17-7-92
95.	मध्य प्रदेश	रायसेन	पिपलई टैंक प्रोजेक्ट	41.305	17-7-92
96.	मध्य प्रदेश	छतरपुर	खुजराहो मिनरल्स छतरपुर को खनन के लिए भूमि	2.368	17-7-92
97.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	तमिया टैंक प्रोजेक्ट	12.97	17-7-92
98.	मध्य प्रदेश	गुना	400 किलोवाट-बीना-मलानपुर लाइन	45.25	17-7-92
99.	मध्य प्रदेश	रायसेन	जुझारपुर टैंक	20.00	17-7-92
100.	मध्य प्रदेश	राजनंदगांव	बागडोर टैंक प्रोजेक्ट	1.29	17-7-92
101.	मध्य प्रदेश	राजनंदगांव	बकरकट्टा टैंक प्रोजेक्ट	6.999	17-7-92
102.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	मै० नर्मदा टाइल्स के लिए मृदा खनन	0.809	3-3-92

1	2	3	4	5	6
103.	मध्य प्रदेश	झबुआ	हवाई पट्टी का विस्तार	0.9975	5-3-92
104.	मध्य प्रदेश	सिओनी	जगौती नाला स्कीम	0.960	5-3-92
105.	मध्य प्रदेश	सतना	मै० मेहर सीमेंट द्वारा सम्पर्क मार्ग	0.950	25-3-92
106.	मध्य प्रदेश	सरगुजा	एस०ई०सी०एल० द्वारा चिरीमिरी कोलियरी	0.833	31-3-92
107.	मध्य प्रदेश	खारगौन	सफेद मिट्टी का उल्लखन	0.992	2-7-92
108.	मध्य प्रदेश	शैहदोल	एस०ई०सी०एल० द्वारा सब-विद्युद केन्द्र का निर्माण	0.455	9-7-92
109.	मध्य प्रदेश	सरगुजा	बेसिक बीज प्रवर्द्धन और प्रशिक्षण केन्द्र	179.68	17-7-92
110.	मध्य प्रदेश	दमोह	ओण्डी-जैतगढ़ सिंचाई टैंक	39.220	17-7-92
111.	मध्य प्रदेश	मुरैना	बोरगांवा-पालपुर रोड	50.50	17-7-92
112.	मध्य प्रदेश	सागर	निरन्दपुर टैंक	30.76	17-7-92
113.	मध्य प्रदेश	सागर	झिरिया टैंक प्रोजेक्ट	6.98	17-7 92
114.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	मैसर्स त्रिशूल टाइल्स वर्क्स को खनन पट्टे का नवीनीकरण	4.00	22-7-92

1	2	3	4	5	6
115.	मध्य प्रदेश	देवास	आस्ता-कन्नोड, कन्नोड-सतवास धसद रोड	12.39	31-8-92
116.	मध्य प्रदेश	इंदौर	कोटिया-झिरी टैंक प्रोजेक्ट	10.660	31-8-92
117.	मध्य प्रदेश	रायसेन	नगरी टैंक प्रोजेक्ट	18.380	31-8-92
118.	मध्य प्रदेश	राजानंदगांव	अम्डानिया डाइवर्जन स्कीम	5.240	23-9-92
119.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	मैसर्स ईस्टर्न मिनरल्स को डाइसपोर प्रोफिलाइट खनन के लिए पट्टे का नवीनीकरण	12.00	22-10-92
120.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सिंहपुर फील्ड फाइरिंग रेंज	24.556	22-10-92
121.	मध्य प्रदेश	धुले	टैंक का निर्माण और पाइपलाइन बिछाना	0.33	17-12-91
122.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	0.8844	23-12-91
123.	महाराष्ट्र	वर्धा	33 किलोवाट पारेषण लाइन बिछाना	0.48	17-1-92
124.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	परकुलेशन टैंक का निर्माण	0.10	17-1-92
125.	महाराष्ट्र	थाणे	स्वीच रूम का निर्माण	0.035	17-1-92

1	2	3	4	5	6
126.	महाराष्ट्र	रायगढ़	भूमिगत जल आपूर्ति लाइन	0.503	17-1-92
127.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	लिफ्ट सिंचाई स्कीम	0.9540	17-1-92
128.	महाराष्ट्र	नासिक	बेतार टावर की स्थापना	0.18	17-1-92
129.	महाराष्ट्र	जलगांव	भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	0.047	17-1-92
130.	महाराष्ट्र	नागपुर	पेयजल पाइप लाइन बिछाना	0.09	24-2-92
131.	महाराष्ट्र	नागपुर	स्कूल भवन	0.56	11-2-92
132.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	परकुलेशन टैंक कां निर्माण	0.82	24-2-92
133.	महाराष्ट्र	रायगढ़	कौंकण रेलवे प्रोजेक्ट	4.038	17-1-92
134.	महाराष्ट्र	भण्डारा	मैसर्स पारवी किनाइट माइन्स को भूमि	10.12	27-1-92
135.	महाराष्ट्र	बुलडाना	तोरणा नदी परियोजना	58.21	24-3-92
136.	महाराष्ट्र	रायगढ़	हेदवाली गांव में 400 किलोवाट पारेषण लाइन	6.24	25-3-92
137.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	220 किलोवाट डबल सर्किट लाइन	11.4093	3-4-92
138.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	घराटघर पम्प स्टोरेज स्कीम	62.09	12-5-92

1	2	3	4	5	6
139.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	अपर परवारा नीजवंडा एम.आई. टैंक	384.85	12-5-92
140.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	संघवी में एम०आई० टैंक	8.43	16-7-92
141.	महाराष्ट्र	जलगांव	वागोर नदी परियोजना	319.21	27-7-92
142.	महाराष्ट्र	रायगढ़	भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	0.94	13-3-92
143.	महाराष्ट्र	धुले	देहाली पीडियम प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पत्थर उत्खनन	0.99	13-3-92
144.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	अम्बार गांव में 11 किलोवाट की पारेषण लाइन	0.42	13-3-92
145.	महाराष्ट्र	रायगढ़	खरखर स्टेशन पर 400 किलोवाट लाइन	0.494	9-7-92
146.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	0.88	29-6-92
147.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना	0.0026	28-7-92
148.	महाराष्ट्र	अमरावती	सिमहोरा गांव से निम्भी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.39	6-8-92
149.	महाराष्ट्र	सतारा	पर्यटकों के लिए 8 मौसमी स्टालों की स्थापना	0.0137	14-8-92

1	2	3	4	5	6
150.	महाराष्ट्र	रायगढ़	कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण	0.96	15-9-92
151.	महाराष्ट्र	अहमद नगर	चन्द्रपुर पदघा में 500 किलोवाट एच.०वी०डी०सी० पारेषण लाइन	40.8616	5-10-92
152.	महाराष्ट्र	सतारा	पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए बैन्ना झील	28.12	16-10-92
153.	महाराष्ट्र	यवतमाल	चपड़ा मीडियम टैंक प्रोजेक्ट	8.88	16-10-92
154.	महाराष्ट्र	यवतमाल	देवगांव प्रोजेक्ट	12.10	19-10-92
155.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां	भूमिगत जल फीडर आदि का निर्माण	0.1805	10-12-91
156.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां	सड़क का निर्माण	0.027	24-12-91
157.	उड़ीसा	वियोंझर	लोहा और मैंगनीज के लिए श्री एन० पटनायक को भूमि	15.068	7-2-92
158.	उड़ीसा	बालासोर	मै० एन०एन० पाण्डा एण्ड कम्पनी को स्वर्ण चड़ स्टोर्सकवेरी का नवीनीकरण	17.00	4-3-92
159.	उड़ीसा	चाकनाल	तल्चर-संबलपुर रेल लाइन	249.625	6-4-92
160.	उड़ीसा	कोरापुट	जेपोर से गुजवाका-400 कि०ग्रा० का निर्माण	1.237	8-9-92
161.	उड़ीसा	कोंझर	सड़क का सुधार	0.9549	13-1-92

1	2	3	4	5	6
162.	उड़ीसा	पुरी	जल भंडार टैंक का निर्माण	0.5125	18-2-92
163.	उड़ीसा	कोंझर	श्री बलराम शाहू का खनन पट्टा	0.90	24-6-92
164.	पंजाब	जालंधर	करतारपुर-जालंधर 220 कि०वा० पारेषण लाइन	0.8400	9-12-91
165.	पंजाब	जालंधर	सुपर पैसेज विप्ट डोव नहर	0.0404	26-2-92
166.	राजस्थान	जयपुर	दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर चार लाइन वाली रोड	77.25	30-9-92
167.	राजस्थान	जयपुर	भारतीय जी.ओ. मेगनिटिना की आब्जर्वेटरी	0.84	10-7-92
168.	तमिलनाडु	नीलगिरि	टी०एन०पी०सी०बी० के लिए वन भूमि	0.8	4-9-92
169.	तमिलनाडु	धर्मपुरी	पर्यटन विभाग द्वारा पुल	0.002	18-12-91
170.	तमिलनाडु	पेरियार	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ब्लैक ग्रेनाइट खनन का नवीनीकरण	0.35	1-10.92
171.	तमिलनाडु	सेलम	ब्लैक ग्रेनाइट खनन का नवीनीकरण	1.10	7-10-92
172.	तमिलनाडु	सेलम	टी०एन० मिनरल्स लि० को ब्लैक ग्रेनाइट के लिए पट्टे का नवीनीकरण	0.035	7-10-92

1	2	3	4	5	6
173.	त्रिपुरा	एन० त्रिपुरा	ओ०एन०जी०सी० द्वारा संपर्क मार्ग तथा ड्रिल स्थल	2.53	22-7-92
174.	त्रिपुरा	प० त्रिपुरा	ओ०एन०जी०सी० द्वारा बी.आर.एम.-के०वाई० पर ड्रिलिंग हेतु भूमि	1.93	22-9-92
175.	त्रिपुरा	प० त्रिपुरा	भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	0.535	22-6-92
176.	त्रिपुरा	प० त्रिपुरा	ओ०एन०जी०सी० द्वारा फ्लेयर स्टाक को खाली करवाना	0.25	22-6-92
177.	त्रिपुरा	प० त्रिपुरा	बी०आर०एम०-एफ० ड्रिल साइट व संपर्क रोड का निर्माण	3.43	29-9-92
178.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	धाडेर खेड़ा पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.2302	6-11-92
179.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	धाडेर खेड़ा पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.2302	6-11-91
180.	उत्तर प्रदेश	हरिद्वार	33/11 के०वी० पारेषण लाइन	0.75	6-11-91
181.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	सिमोली पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.09	14-1-92
182.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	कांची पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.53	14-1-92
183.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	दीमाटोक पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.1804	14-1-92

1	2	3	4	5	6
184.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	पाताल देवी दुग्ध डेयरी पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.09	14-1-92
185.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	अंखली पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.2754	1-1-92
186.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	वरखा पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.4446	4-2-92
187.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	पाइप लाइन बिछाना	0.1785	4-2-92
188.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	हवालबाग-वासदी मोटर मार्ग	0.4612	7-2-92
189.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	टोलगंध ओलगंध पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.1268	4-2-92
190.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी	चल्ला पेय जल आपूर्ति स्कीम	0.723	1-4-92
191.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	मौरोली दसोली पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.53	3-4-92
192.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	रचनाकोट पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.349	12-5-92
193.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	पत्थर खाल पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.2192	17-6-92
194.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी	विन्ना जल आपूर्ति स्कीम	0.1813	18-6-92
195.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी	सिलखोला जल आपूर्ति स्कीम	0.12	18-6.92
196.	उत्तर प्रदेश	उत्तर कांशी	तिकोची दुचग त्रिगल पथ	0.91	18-8-92

1	2	3	4	5	6
197.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	पील द्वीप समूह में पुलिस लुकआउट पोस्ट का निर्माण	0.90	23-4-92
198.	कर्नाटक	नोर्थ कन्नड़	खनन पट्टे की मंजूरी	0.04	26-11-91
199.	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	पुल का पुर्ननिर्माण	0.22	23-9-92
200.	कर्नाटक	नायत्तौर	सत्यगल जहागीर में पट्टे पर भूमि	70.00	24-9-92
201.	केरल	पालाखाद	पुलिस स्टेशन का निर्माण	0.12	22-9-92
202.	केरल	त्रिचूर	दूर-संचार विभाग को पट्टे की समय वृद्धि	0.0056	23-9-92
203.	केरल	कीटयम	डी०टी० लाइन खींचना	0.045	23-9-92
204.	केरल	त्रिचूर	इदुक्की एर्नाकुलम में 220 कि०वा० पारेषण लाइन	11.347	25-8-92

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	जिला	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे० में)	नामंजूर करने वाली तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	चालांग	कार्यालय-व-शिविर का निर्माण	0.4	4-6-92
2.	हरियाणा	अम्बाला	लघु सीमेंट संयंत्र	32.4	22-11-92
3.	हरियाणा	सोनीपत	गन्नौर में जी० टी० रोड से नई बस स्टैंड सम्पर्क मार्ग	0.047	30-4-92
4.	हरियाणा	कैथल	कैथल से नया बाई-पास	0.69	30-4-92
5.	हरियाणा	फ़रीदाबाद	गैस आधारित विद्युत परियोजना	0.4	4-9-92
6.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	कृषि विभाग के पक्ष में	0.4	11-11-92
7.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	सर्किट हाऊस का निर्माण	0.127	11-11-92
8.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	सरकाघाट डाकघर का निर्माण	0.031	30-4-92

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	एक ऑटोमोबाइल वर्कशाप का निर्माण	0.4	20-3-92
10.	मध्य प्रदेश	विलासपुर	वनवासी सेवा समिति	56.49	12-5-92
11.	महाराष्ट्र	यवतमाल	पाइपलाइन बिछाना	0.1125	24-1-92
12.	महाराष्ट्र	नासिक	11 कि० वा० पारेषण लाइन बिछाना	0.84	24-1-92
13.	महाराष्ट्र	धूले	भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	0.012	24-1-92
14.	महाराष्ट्र	धूले	बांध निर्माण के लिए पत्थर खनन	0.99	24-1-92
15.	महाराष्ट्र	जलगांव	वाडगांव मे पाइप लाइन बिछाना	0.020	8-4-92
16.	महाराष्ट्र	पुणे	वीर गांव में पाइप लाइन विछाना	0.0513	8-4-92
17.	महाराष्ट्र	अमरावती	जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	0.0018	13-4-92
18.	महाराष्ट्र	यवतमाल	पानी की पाइप लाइन बिछाना	0.1125	8-7-92
19.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	विद्युत लाइन बिछाना	0.18	1-9-92
20.	उड़ीसा	बालासोर	ब्रेकिश जल मत्स्य पालन परियोजना	187.65	17-7-92

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	पटियाला	मोगा से फिरोजपुर तक 220 कि० वा० लाइन	0.6593	9-12-91
22.	पंजाब	अमृतसर	बस बेज का निर्माण	0.64	5-3-92
23.	पंजाब	संगरूर	कोटला शाखा नहर पर नए ब्राइड का निर्माण	0.3252	5-3-92
24.	पंजाब	संगरूर	220 कि० वा० भाखड़ा माहीपुर लाइन	0.184	5-3-92
25.	पंजाब	रोपर	220 कि० वा० गंगवाल मोहली लाइन	00.270	5-3-92
26.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	रमन हेप के लिए रम्मन नदी पर इन्टेक ढांचे का निर्माण	0.001	29-7-92
27.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	मेहगोली पेयजल आपूर्ति योजना	0.0185	28-5-92
28.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	बेताल नहर	0.422	28-5-92
29.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	जाली ग्रान्ट रायपुर एल० एम० बी० आर०	0.955	28-5-92
30.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	मल्ली विधोली पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.183	3-4-92
31.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा	बस्ती पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.2211	13-5-92
32.	उत्तर प्रदेश	देहरादून	चन्द्रावत विष्ट ग्राम एम० आर०	0.87	28-5-92

1	2	3	4	5	6
33.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	खनिजों का खनन	319.33	31-7-92
34.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	डिडिहाट पेयजल आपूर्ति स्कीम	0.0241	28-5-92
35.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	अमटोडा टोक पेयजल स्कीम	0.1225	28-5-92
36.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	नवोलिया गांव पेयजल स्कीम	0.6509	28-5-92
37.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	सेना द्वारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	0.360	4-9-92
38.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	अण्डमान	हल्के सकूर स्तम्भों की स्थापना	0.04	4-9-92

विवरण-III

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र हे० में	लम्बित रहने की अवधि	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. कृषि प्रयोजनों के लिए असाइनमेंट सुगाली	200.00	6 माह से अधिक	क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		2. ए०सीं०सी० आदिलाबाद को चूना पत्थर खनन पट्टा	122.61	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		3. मानुगुओ से खुली खदान कोयला खनन परियोजना-3	181.00	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		4. चिमालपद आर०एफ० में येलियेन्डु ओसीपी का कोयला खनन	48.00	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		5. डबल ट्रक रेल लाइन बिछाना	32.00	1 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना है ।
		6. श्रीराम सागर प्रोजेक्ट सरस्वती सागर	3.30	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. सेना के उपयोग हेतु के०आई०ई०पी० पुल	720.00	1 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
		2. तवाग के लिए वैकल्पिक मार्ग	13.8	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
3.	असम	1. कयालगुडी से दीमापुर तक पारेषण लाइन	19.80	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		2. जोगीघोपा में गोवाहाटी तक नई बी०जी० रेल लाइन	121.56	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		3. एन०ई०ई० एण्ड कम्पनी द्वारा कोपिली जल-विद्युत परियोजना	3685.60	2 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
4.	बिहार	1. फिल्ड फाइरिंग रेंज का अभिनिर्धारण		2-3 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
5.	गुजरात	1. दमनगांगा परियोजना	977.875	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		2. लेखिया लघु सिंचाई स्कीम	10.00	2 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		3. जोखारी सिंचाई स्कीम	1120.00	3 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।
		4. वालान सिंचाई परियोजना	433.08	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6
		5. अखिल उद्योग विकास सहकारी मंडल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	16.20	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
6.	हरियाणा	1. सिंधमुख नाहर परियोजना	196.8	2 माह	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		2. पानीपत से मोलरकोटला तक 400 कि०वा० पारेषण लाइन	3.37	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ को हस्तांतरित किया जा रहा है ।
		3. राधा स्वामी कोसत्संग की भूमि	40.93	3 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
7.	हिमाचल प्रदेश	1. सेना द्वारा पारगमन शिविर का निर्माण	12.00	6 माह से ऊपर	क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ को हस्तांतरित किया जा रहा है ।
8.	कर्नाटक	1. गुट्टूर से नेल्मांगोला तक 400 कि०वा० पारेषण लाइन	31.76	1 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
		2. एस०ए० तवाब के पक्ष में खनन का नवीकरण ।	31.6	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।
		3. श्रीमती के०एन० सरोज को खनन पट्टा	89.6	-वही-	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।

1	2	3	4	5	6
		4. मैसूर मिनरल्स को खनन पट्टे का नवीनीकरण	80.93	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।
		5. डालमिया सीमेंट को खनन पट्टा	327.63	-वही-	-वही-
9.	केरल	1. इदुक्की विकास प्राधिकरण को भूमि	397.04	3-6 माह	कार्रवाई की जा रही है।
10.	मध्य प्रदेश	1. सेना द्वारा फील्ड फाइरिंग रेज	16630.441	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		2. सेना द्वारा बर्चा फील्ड फाइरिंग रेंज	3650.12	2 माह	-वही-
		3. कोसरटेडा लघु सिंचाई परियोजना	447.247	2 माह	कार्रवाई की जा रही है।
		4. पीवी 103 सिंचाई परियोजना का निर्माण	95.930	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		5. नेबता टैंक परियोजना	33.204	-वही-	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।
		6. खुदरी सिंचाई परियोजना	7.710	-वही-	कार्रवाई की जा रही है।
		7. डांडीबहोरा टैंक परियोजना	13.584	-वही-	-वही-
		8. धबखर टैंक परियोजना	54.520	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		9. साहसीनवोही टैंक	21.650	2 माह	कार्रवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
		10. कोतलीजान टैंक परियोजना	38.125	2 माह	-वही-
		11. गोहानाला टैंक परियोजना	37.600	-वही-	-वही-
		12. लीलार डाइवर्जन स्कीम	13.190	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का हस्तांतरित किया जा रहा है।
		13. बगेन टैंक परियोजना	70.00	-वही-	कार्रवाई की जा रही है।
		14. गोडलानाला टैंक	53.703	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		15. लोवर भाण्डोरा टैंक	115.628	-वही-	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।
		16. पेधी टैंक परियोजना	204.620	-वही-	-वही-
		17. नाइक बांधा टैंक	49.48	-वही-	-वही-
		18. कंसलवाल डाइवर्जन स्कीम	2.765	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का हस्तांतरित किया जा रहा है।
		19. श्यामागीरी सिंचाई परियोजना	8.552	3 माह	-वही-
		20. बत्रा सिंचाई परियोजना	109.725	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		21. मुरै टैंक परियोजना	18.466	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6
		22. बाघाघाट एन०ई०पी०	5704.332	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		23. बिरामपुर सिंचाई परियोजना	12.001	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का हस्तांतरित किया जा रहा है।
		24. आध्यात्मिक उत्थान के लिए डाइवर्जन	1.00	-वही-	-वही-
		25. कोणार्क खनिजों के लिए खनन लीज	20.234	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		26. धुमोरपाली सिंचाई परियोजना	40.090	-वही-	-वही-
		27. देनारपाड़ा सिंचाई परियोजना	46.500	-वही-	-वही-
		28. पोहडा सिंचाई परियोजना	44.00	-वही-	-वही-
		29. पाथोखोर में अण्डर ग्राउण्ड राईट	1349.2	-वही-	सलाहकार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है ।
		30. चन्द्र नगर सिंचाई परियोजना	17.39	3 माह	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का हस्तांतरित किया जा रहा है ।
		31. सागर सिंचाई परियोजना	24.245	-वही-	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
		32. स्रोवपुर टंक परियोजना	45.31	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4	5	6
		33. ढोकरिया नाला सिंचाई परियोजना	136.290	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।
		34. दिगम्बर जैन अकिशांग क्षेत्र के लिए भूमि	11.97	-वही-	-वही-
		35. नर्मदा मिनरल्स के शाप स्टोन खनन	4.048	-वही-	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का हस्तांतरित किया जा रहा है ।
		36. म०प्र० एम०एम०पी० को खनन पट्टा	29.173	-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		37. लोहारेना टैंक परियोजना	35.100	-वही-	-वही-
		38. सुल्तारपारा सिंचाई परियोजना	29.805	-वही-	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
11.	महाराष्ट्र	1. डीलडी फील्ड फायरिंग का विस्तार		-वही-	कार्रवाई की जा रही है ।
		2. सरेखा एम०आई० टैंक	39.12	-वही-	-वही-
		3. पैंधीनाला एम०आई० टैंक	156.91	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
		4. सिंघवेवाही टैंक	139.76	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6
		5. अस्वाली एम०आई० टैंक	25.900	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी ।
		6. हरषी एम०आई० टैंक	44.92	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।
		7. सागरनाला मध्यम सिंचाई परियोजना	170.76	1 माह	सलाहकार समिति की कागजी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
		8. वारपारी एम०आई० टैंक	35.60	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की कागजी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
		9. पुनार्ड एम०आई० टैंक	57.90	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की कागजी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
		10. मोहा एक्ट के तहत वन भूमि का अधिग्रहण	7598.726	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।
		11. ओवेर एम०आई० टैंक	129.800	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		12. मोर जलाशय परियोजना	117.00	1 माह	सलाहकार समिति की कागजी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
		13. भात्सा बांध चरण-2	2027.860	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4	5	6
		14. दूधगंगा सिंचाई परियोजना	1178.5540	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		15. घनोली एम०आई० टैंक	49.50	1 माह	कार्रवाई की जा रही ।
		16. परदा एम०आई० टैंक	2.690	2 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		17. बजाटोला एम०आई० टैंक	10.720	2 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		18. सलाद एम०आई० टैंक	8.660	2 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		19. निवगाम एम०आई० टैंक	141.620	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		20. पालन्टुर एम०आई० टैंक	64.130	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		21. पाराकोवोडी एम०आई० टैंक	69.180	2 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
		22. उमरझरी परियोजना और नहर	245.418	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		23. बामलेश्वर के घाले तक 400 कि०वा० विद्युत लाइन	21.528	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
	12. मणिपुर	1. लोकटक डाउन स्ट्रीम प्रोजक्ट	420.00	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6
13.	उड़ीसा	1. 395 परिवारों का पुनर्वास	532.97	6 माह से ऊपर	सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
		2. पैटर्न लघु जल विद्युत परियोजना	12.83	2 माह	कार्रवाई की जा रही है
		3. बसुन्धरा खुली खदान परियोजना	21.59	2 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
		4. मैसर्स एफ०ए०सी०ओ०आर० लि० को क्रोइवेट माइनिंग लीज	187.03	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		5. एन० पटनायक को खनन लीज	36.42	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
14.	पंजाब	1. दमसल बांध	78.04	1 माह	कार्रवाई की जा रही है।
15.	राजस्थान	1. 4 लैंडिंग रोड एन०एच० 8 का निर्माण	30.00	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है।
		2. बिलास सिंचाई परियोजना	622.2	2 माह	कार्रवाई की जा रही है।
16.	सिक्किम	1. 1200 मे०वा० टीस्टा चरण-3 जल विद्युत परियोजना	363.057	6 माह से ऊपर	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
17.	तमिलनाडु	1. कराडिकंठी क्वैरी	1.00	6 माह से ऊपर	क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर को हस्तांतरित किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
		2. ए०सी०सी० लि० को खनन पट्टा	65.18	6 माह से ऊपर	सलाह समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है
18.	त्रिपुरा	1. रबड़ पौध रोपण	9019.52	6 माह से ऊपर	कार्रवाई की जा रही है ।
		2. सेना के लिए फिल्ड फायरिंग रेंज	519.88	1 माह	सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
19.	उत्तर प्रदेश	1. दग्गड नहर	1.23	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		2. उन्नाव से लखनऊ तक 400 के०वी० पारेषण लाइन	2.153	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		3. सावर डुंगा मोटर रोड	3.9627	1 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
		4. मडनवेली डिवन मोटर रोड	3.915	3 माह	कार्रवाई की जा रही है ।
20.	पश्चिम बंगाल	1. ए०के० बनर्जी को खनन पट्टा	21.608	3 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

[हिन्दी]

ताजमहल के आस-पास प्रदूषण

2530. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ताजमहल के आस-पास प्रदूषण का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, नागपुर से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में संस्थान से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। ताजमहल के आसपास प्रदूषण की मात्रा का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को एक परियोजना सौंपी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रिपोर्ट के सितम्बर, 1993 तक आने की आशा है।

[अनुवाद]

आधारिक शिक्षा कार्यक्रम

2531. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में करोड़ों की राशि से चलाये जाने वाले आधारिक शिला कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार करने का कोई प्रस्ताव हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) इन कार्यक्रमों हेतु वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान योजना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 284 करोड़ रु० आवंटित किए हैं।

योजनावार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	योजना	आवंटित राशि
1.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	—99.14
2.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	—64.50
3.	अनौपचारिक शिक्षा	—90.10
4.	विदेशों से सहायता प्राप्त (वित्त पोषित) परियोजनाएं	—24.40
5.	सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का अनुवीक्षण	—00.86
6.	सूक्ष्म आयोजना का प्रचालन	— 3.00
7.	शिक्षुओं की उपलब्धि में सुधार	— 2.00
		284.00

2. इन निधियों का राज्यवार आवंटन का निर्णय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा इससे पूर्व चरणों में उनके कार्य निष्पादन का विश्लेषण करने, संस्वीकृत की गई राशि की उपयोगिता तथा उनके पास उपलब्ध अनप्रयुक्त बकाया राशियों के आधार पर किया जाता है।

3. इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सुधार के लिए विदेशी सहायता भी उपलब्ध है :

1. **आंध्र प्रदेश :**

यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय विकास प्रशासन, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (1989-94) के लिए 31.1 मिलियन पौंड की सहायता प्रदान कर रहा है।

2. **बिहार :**

यूनिसेफ ने बिहार शिक्षा परियोजना (1991-95) के लिए अपने सामान्य संसाधनों से 8 मिलियन अमरीकी डालर देने तथा 100 मि० अमरीकी डालर की अनुपूरक निधियां जुटाने का वचन दिया है।

3. **राजस्थान :**

स्वीडिश इन्टर नेशनल डेवलपमेंट एथारिटी, राजस्थान के दूर-दराज के गांवों में कार्यान्वित की जा रही शिक्षा कर्मी नामक परियोजना के लिए सहायता प्रदान कर रही है। 1989-91 के दौरान 4.61 करोड़ रु० का व्यय होगा। बड़ी एजेंसी राजस्थान राज्य में लोक जुम्बिश परियोजनाओं के लिए भी निधियां प्रदान कर रही हैं। 1992-94 के प्रथम चरण के लिए 18 करोड़ रु० के व्यय

की परिकल्पना की गई है। इसके लिए सीडा, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच 3:2:1 के अनुपात का अंशदान होगा। इसके अलावा विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की एक बेसिक शिक्षा परियोजना को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्यक्रम

2532. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1992-93 और 1993-94 के लिए शिशु एवं मातृ सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम गुजरात के सभी जिलों विशेषरूप से पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) 1. अन्य बातों के साथ-साथ शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के निम्नलिखित संघटक हैं :

(क) रोग प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा और रोग-निरोधन के चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(ख) दाइयों को प्रति प्रसव बढ़ी हुई 10.00 रुपये की रिपोर्टिंग फीस देकर सामुदायिक स्तर पर मातृत्व परिचर्या में सुधार करना और गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट देना; और

(ग) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का चरणवार ढंग से विस्तार करना।

2. जहां सामुदायिक स्तर पर व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा, रोग निरोधन योजनाएं और अनिवार्य मातृत्व परिचर्या को गुजरात के जिलों सहित देश के सभी जिलों में पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है, वहां 1992-93 में 51 जिलों से शुरू करके तीव्र श्वसनीय संक्रमण संघटक का चरणवार ढंग से विस्तार किया जायेगा। गुजरात के जिलों के लिए चरणबद्ध योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

3. आठवीं योजनावधि के दौरान शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के लिए निश्चित किया गया अनुमानित परिव्यय 3222.11 लाख रुपये है। 1992-93 और

1993-94 के लिए परिव्ययों का ब्यौरेवार विवरण इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	परिव्यय		
	नकद	सामग्री	योग
1992-93	118.50	355.50	474.00
1993-94	249.23	382.00	631.23

विवरण

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात के जिलों को शामिल करने के लिए चरणबद्ध योजना

1992-93 : वडोदरा, जाम नगर

1993-94 : राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सुरेनफ्रा नगर

1994-95 : खेड़ा, पंचमहल, भड़ोंच, भुज (कच्छ)

1995-96 : अहमदाबाद, गांधी नगर, मेहसाणा, वनासकांठा, सबरकांठा

1996-97 : सूरत, डंग्स, वलसाड़

नवोदय विद्यालय

2533. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ जिलों में पहले से चल रहे विद्यालयों को बन्द करके नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिले में नवोदय विद्यालय को अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवोदय विद्यालय समिति ने यह सूचित किया है कि उनको ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दिल्ली के अस्पतालों में संक्रमण से होने वाली मौतें

2534. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में संक्रमण से मरने वाले रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का ऐसी मौतों के कारणों का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति के गठन का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों के संक्रमण मुक्त बनाने हेतु उनके सर्जिकल वार्डों के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) पिछले एक वर्ष में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में संक्रमण से किसी रोगी की मौत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसे देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अधिक खतरे वाले क्षेत्रों और वार्डों में संक्रमण के स्तर की मानीटरिंग की जा रही है तथा संक्रमण दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपरेशन थिएटरों, प्री-आपरेटिव और पोस्ट आपरेटिव कमरों को नियमित रूप से धूमन क्रिया द्वारा विसंक्रमित किया जा रहा है।

राजधानी एक्सप्रेस को चलाने से लाभ

2535. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और हावड़ा को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की प्रत्येक श्रेणी में अधिभोग दर क्या है;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ियां कोई लाभ अर्जित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो रेलगाड़ियों की परिचालन लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे के निःशुल्क पास धारक उक्त रेलगाड़ियों में यात्रा करने के पात्र है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे यात्रियों की औसत प्रतिशत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बम्बई और हावड़ा की दोनों राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का सामान्यतः पूरा उपयोग होता है।

(ख) 1986-87 में किए गए विशिष्ठ अध्ययन के अनुसार ये गाड़िया लाभप्रद थीं।

(ग) इन गाड़ियों के परिचालन की लागत तथा प्रति फेरें (एक तरफ) प्राप्त आमदनी का का ब्यौरा इस प्रकार था :—

(आंकड़े रुपयों में)

	नई दिल्ली-हवड़ा एक्सप्रेस	नई दिल्ली-बम्बई एक्सप्रेस
संचालन व्यय	2,18,896	2,11,098
मूल्यह्रास	12,421	11,464
ब्याज	19,428	18,524
कुल लागत	2,50,745	2,41,086
आमदनी	2,86,870	2,78,491

संचालन व्यय में रेल इंजनों और सवारी डिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की लागत, कर्षण लागत, स्नेहक, वातानुकूलन के लिए बिजली जनित्र, कर्मचारी लागत, खानपान, रेलपथ का अनुरक्षण, सिगनल तथा अन्य परिवहन, शिरोपरि प्रभार, आदि शामिल हैं ।

(घ) इन गाड़ियों में ड्यूटी पर यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त पासों/सुविधापासों पर यात्रा करने वाले सेवानिवृत्त/सेवारत बोर्ड के सदस्यों को सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें आबंटित की जाती हैं ।

(ङ) यह 2.4% से कम है ।

खुले बाजार में चीनी की बिक्री

2536. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : **क्या खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 88 प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सभी चीनी मिलें सम्मिलित की जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना में किन मिलों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं को कवर करने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना बनाने का मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

विकिरण के कारण रक्त कणिकाओं संबंधी विकृति

2537. **डा० आर० मल्लू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता चला है कि केरल स्थित इंडियन रेयर अर्थ विकिरण उत्सर्जन कर रहा है, जिसकी वजह से रक्त कणिकाओं में विकृति आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) केरल में "भारत रेयर अर्थ" के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार लो डोज रेडियेशन श्वेत रक्तता होने का एक संदिग्ध कारण हो सकता है। भाभा परमाणु शोध केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन से इस बात का संकेत मिलता है कि इंडियन रेयर अर्थ, केरल आस पास के क्षेत्रों में पृष्ठिका विकिरण स्तर सुरक्षा सीमाओं के भीतर है।

नेहरू युवा केन्द्र के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

2538. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवा संगठन/केन्द्रों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान समझा जाता है;

(ख) यदि नहीं; तो उनके वेतनमान महंगाई भत्ता और उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं/लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन्हें भी केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुपात से महंगाई भत्ता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन में दो प्रकार के कर्मचारी हैं। पहली श्रेणी के सीधी भर्ती के कर्मचारी और राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं जो संगठन बनने से पहले विभाग के कर्मचारी थे और न्यायालय में लम्बित मामले के कारण संगठन में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर माना जाता है। दूसरी श्रेणी के वे कर्मचारी हैं जिन्हें संगठन बनने के बाद संगठन ने नियुक्त किया है और जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जाता। इस श्रेणी के कर्मचारियों को समेकित वेतन तथा उनके वेतन का 20% की दर से आवास किराया भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने

1-1-90 को एक वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक पूरी कर ली है उन्हें एक वेतन वृद्धि दी गई है। इसी प्रकार जिन्होंने 1-1-90 को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें 2 वेतन वृद्धि दी गई है। संगठन में उन कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना भी है, जिनकी भर्ती इसके बनने के बाद हुई है।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की सिफारिश की है। सिफारिशों पर कार्मिक और व्यय विभाग की सलाह से कार्रवाई की जा रही है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में रोग कल्याण समिति

2539. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोगियों की सहायता के लिए एक कल्याण समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में दिये गये वित्तीय अनुदान और समिति द्वारा एकत्र की राशि के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। इस समिति का उद्देश्य, विकलांग, गरीब या जरूरतमंद लोगों सहित अस्पताल के रोगियों की देखभाल करना है। एक अन्य कार्य अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों आदि के बीच संपर्क स्थापित करना है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा दिए गए वित्तीय अनुदान और अन्य स्रोतों से समिति द्वारा एकत्रित की गई निधियों से संबंधित विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	सरकार से प्राप्त अनुदान (रुपये में)	अन्य स्रोतों से एकत्रित निधियां (रुपए में)	योग
1990-91	20,000	47,957	67,957
1991-92	20,000	58,941	78,941

एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश

2540. **श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०बी०बी०एस० प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कृपापूर्ण अवसर प्रदान करने के कोई प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में क्रमश: सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कितने कृपापूर्ण अवसर प्रदान किये गये हैं;

(ग) ऐसे कृपापूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(घ) क्या आरक्षित उम्मीदवारों के लिए कृपापूर्ण अवसर प्रदान करने में भेदभाव बरते जाने के समाचार मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मुम्बई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली

2541. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेलवे प्रणाली का अधिकाधिक विस्तार करने के लिए किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न हैं ।

(ग) परियोजनाओं का पूरा किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

विवरण

निर्माण-कार्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	91-92 के अंत तक व्यय	92-93 के लिए परिव्यय
1	2	3	4	5
1. बम्बई वी० टी०-दोहरे निकास वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने के लिए उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	17.07	16.54	0.25

1	2	3	4	5
2.	बम्बई-कल्याण में धीमे गलियारे के सिगनलों का पुनः अंतरण ।	09.21	00.15	0.96
3.	अंबरनाथ उप स्टेशन	01.62	00.65	0.96
4.	पारसिक टनल उप स्टेशन	01.34	01.02	0.32
5.	ठाकुरली बिजली घर	02.29	00.01	1.19
6.	दातिवली उप स्टेशन	2.08	01.93	0.65
7.	मुम्बरा उप स्टेशन	02.87	00.03	0.08
8.	ठाकुरली उप स्टेशन	01.67	01.25	0.42
9.	विद्या विहार उप स्टेशन	01.69	0.78	0.91
10.	अंबीवली उप स्टेशन	02.01	नया निर्माण कार्य	0.04
11.	नाईगांव उप स्टेशन	06.46	00.51	1.85
12.	मारिम, मीरा रोड और विरार उप स्टेशन निर्माण कार्य	02.57	नया निर्माण कार्य	0.08
13.	मैरीन लाइन्स उप स्टेशन	09.35	नया निर्माण कार्य	0.16
14.	चल स्टाक	441.33	25.89	32.12

[हिन्दी]

केन्द्रीय मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

2542. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में केन्द्रीय मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मलेरिया पर अनुसंधान कार्य करने के लिए देश के अन्य भागों में भी ऐसे केन्द्र स्थापना करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) मध्य प्रदेश में मंडला में स्थापित अस्थायी फील्ड स्टेशन के अलावा इस समय राज्य में दूसरा मलेरिया अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मलेरिया अनुसंधान केन्द्र के अधीन देश के विभिन्न भागों में बारह अस्थायी फील्ड स्टेशन हैं । इस समय इन स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान संस्थान में कथित अनियमितताएं

2543. **श्री अनिल बसु** :क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आर्युवेद एवं सिद्ध अनुसंधान संस्थान में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां । यह शिकायत केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में है । प्रारम्भिक जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई है ।

जिगर/गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधाएं

2544. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिगर और गुर्दे के प्रत्यारोपण की सुविधाओं से युक्त सरकारी अस्पतालों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रत्यारोपण के लिए विदेश जाने वाले रोगियों की समस्याओं को कम करने के लिए देश के अन्य प्रमुख अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) गुर्दे के प्रत्यारोपण की सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, चण्डीगढ़ में उपलब्ध हैं । बहरहाल, इस समय जिगर के प्रत्यारोपण की सुविधाएं देश के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं । ब्रेन स्टेम मृत्यु होने के बाद अंगों को निकालने की अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सभा में लाए गए अंग प्रत्यारोपण विधेयक को संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत ही इसे शुरू किया जा सकता है ।

कोला में मदिरा का मिश्रण

2545. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदिरा से युक्त कोला के विपणन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पेय से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पेय की बिक्री पर निषेध करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि यह मानव सेवन के लिए उपयुक्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) मदिरा से युक्त पेय पदार्थों के मामले में विशिष्टियों, मानकों, सांद्रता, अनुमत्य मिश्रणों आदि का निर्धारण/अनुवीक्षण संबंधित राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित उत्पाद कानूनों/नियमों के तहत किया जाता है ।

हावड़ा और हल्दिया सेक्शनों की उपयोगिता

2546. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और हल्दिया के बीच वर्तमान परिवहन नेटवर्क की उपयोगिता की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेक्शन की उचित/बेहतर उपयोगिता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कुछ भागों में नेटवर्क के उपयोग की सीमा 92% है, उपयोग निर्धारित करना एक सतत् प्रक्रिया है । अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ग) खंड का पर्याप्त रूप से उपयोग किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

शिक्षा पर व्यय

2547. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत शिक्षा के लिए विशेष रूप से केन्द्रीय प्रायोजित नई शिक्षा

पद्धति संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि नियत की गई है और इसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यवार कितनी सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : शिक्षा के विभिन्न उप क्षेत्रों और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए किये गए अन्तरिम आबंटन, विवरण-I और II में दिए गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को प्राप्त प्रस्तावों तथा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध निधियों के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

विभिन्न उप-क्षेत्रों के अन्तर्गत आठवीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र आबंटन

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं०	उप क्षेत्र का नाम	आठवीं योजना आबंटन
1.	प्रारंभिक शिक्षा	2880.00
2.	माध्यमिक शिक्षा	1519.00
3.	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	700.00
4.	प्रौढ़ शिक्षा	1400.00
5.	भाषाएं	
	(क) हिन्दी	30.95
	(ख) आधुनिक भारतीय भाषा	14.25
	(ग) अंग्रेजी	3.80
	(घ) संस्कृत	21.00
	कुल (भाषाएं)	70.00
6.	छात्रवृत्तियां	10.00
7.	पुस्तक प्रोन्नति	8.00
8.	आयोजना एवं प्रशासन	32.00
9.	तकनीकी शिक्षा	824.00
	कुल :	7443.00

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनागत आबंटन

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	आठवीं योजनागत आबंटन
1	2	3
	प्रारम्भिक शिक्षा	
1.	ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड	950.00
2.	शिक्षक शिक्षा	607.00
3.	**गैर औपचारिक शिक्षा**	
	(क) 9-11 आयु वर्ग के लिए गैर औपचारिक शिक्षा	345.00
	(ख) लड़कियों के लिए गैर औपचारिक केन्द्र	280.00
	माध्यमिक शिक्षा	
4.	प्रौद्योगिक शिक्षा	108.00
5.	क्लास	146.00
6.	पर्यावरणीय अनुस्थापन	10.00
7.	विज्ञान शिक्षा का सुधार	120.00
8.	शिक्षा का व्यावसायीकरण	410.00
9.	आई० ई० डी० सी०	25.00
10.	योग की प्रोन्नति	3.25
	प्रौढ़ शिक्षा	
11.	आर० एफ० एल० पी०	25.00
12.	उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा	132.00
13.	प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना	28.00
	भाषायें	
14.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	12.00

1	2	3
15.	आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	3.00
16.	उर्दू शिक्षक	—
17.	शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम	16.27
	कुल :	3220.52

[अनुवाद]

पेंशन मामलों का निपटान

2548. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 तक सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के मामलों की वर्गवार संख्या कितनी है जो कि अन्तिम निबटान हेतु लगभग एक, दो और तीन वर्षों से लम्बित पड़े हैं,

(ख) क्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के मामलों के तुरन्त निपटान हेतु कोई योजना बनाई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	तीन वर्ष से अधिक
ग्रुप "क"	36	14	10
ग्रुप "ख"	48	19	14
ग्रुप "ग"	968	595	605
ग्रुप "घ"	371	222	321

(ख) से (घ) इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि सेवानिवृत्त हो रहे रेल कर्मचारियों को देय पेंशन और उपदान आदि की राशि का ठीक समय पर आकलन किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन भुगतान आदेश और उपदान की अदायगी के आदेश कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर तत्काल जारी किए जाएं रेल प्रशासनों द्वारा अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, इस बात पर समय-समय पर जोर डाला जाता है। तथापि, कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर खाली न किए जाने, कर्मचारियों द्वारा कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम/सतर्कता के मामले और अदालती मामलें होने आदि विभिन्न कारणों की वजह से, कभी-कभी पावने की राशि ली जाती है और इनका निपटारा हो जाने पर ऐसे मामलों को बिना और अधिक विलम्ब किए अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

गांधी स्मृति और दर्शन समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

2549. **श्री शशि प्रकाश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उन कर्मचारियों को जो अप्रैल, 1990 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे, पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है;

(ख) इस संबंध में कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) क्या उनकी पेंशन की शीघ्र मंजूरी के लिए कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गांधी स्मृति और दर्शन समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस संबंध में पांच मामले लम्बित पड़े हैं।

(ग) से (ङ) पांच कर्मचारी प्रथमदृष्टया पात्र नहीं हैं क्योंकि पेंशन एवं उपदान योजना भूतलक्षी रूप से लागू नहीं है।

विश्व पुस्तक मेला

2550. **श्री पांडुरंग पुण्डलिक फुण्डकर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में फ्रेंकफर्ट में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा; और

(ख) भविष्य में पुस्तक मेले में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 30 सितम्बर, से 5 अक्तूबर, 1992 तक आयोजित 44वें फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अलावा, भारत के 37 प्रतिभागी थे। अस्थायी अनुमान के अनुसार, मेले के दौरान 90 लाख रु० का व्यापार हुआ। अनुवाद/सह-प्रकाशन अधिकारों, मुद्रण कार्यों आदि के लिए, किए गए ठेकों की कीमत, लगभग 45 लाख रु० थी।

(ख) फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले में भारत की सहभागिता में सुधार के लिए किये जाने वाले उपायों में, निम्नलिखित शामिल है :—

(i) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत और रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (सी० ए० पी० ई० एक्स० आई० एल०) अगले फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले के लिए, और अधिक संसक्ति से तैयारी करेंगे ताकि पृथक व्यक्तित्व/पहचान की अपेक्षा, मेले में भारतीय प्रतिभागी, संयुक्त रूप से एक सामूहिक भारतीय छवि प्रस्तुत कर सकें।

(ii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी प्रमुख यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद के लिए, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

[हिन्दी]

लेवी चीनी पर लाभ की सीमा

2551. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेची जा रही चीनी के थोक मूल्य तथा खुदरे मूल्य से मिलने वाले लाभ की सीमा का कोई सर्वेक्षण कराया गया है तथा इस पर वास्तव में कितना व्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभ की सीमा कम होने के कारण सहकारी समितियों को इस बिक्री प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(घ) लाभ की इस सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) राजस्थान सरकार ने सिफारिश की है कि लेवी चीनी का वितरण करने के लिए देय मार्जिन को बढ़ाकर राज्य के नामितियों के लिए 1.65 रुपये प्रति क्विंटल, थोक बिक्रेताओं के लिए 27.14 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं के लिए 12.74 रुपये प्रति क्विंटल (खाली बोरियों से प्राप्तियों को छोड़कर) कर दिया जाए। यहां उल्लेखनीय है कि लेवी चीनी का वितरण करने के लिए राजस्थान राज्य में देय मार्जिन की 1991 में समीक्षा की गई थी और ये मार्जिन अब राज्य के नामितों के लिए 1.15 रुपये प्रति क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 16.27 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा विक्रेताओं के लिए 7.46 रुपये प्रति क्विंटल इसमें खाली बोरियों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं) है। ये मार्जिन 1-4-1991 से प्रभावी हैं और इनमें प्रत्येक तीन वर्षों के बाद संशोधन किया जाता है।

राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से उनके मार्जिनों में वृद्धि करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की दृष्टि में इन मार्जिनों को निश्चित करने से संबंधित मानदण्डों में संशोधन किया जा रहा है। इन मानदण्डों में जब एक बार संशोधन कर दिया जाएगा, तब राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में लेवी चीनी का वितरण करने के लिए थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के देय मार्जिनों में भी तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा।

11.02 म० पू०

तत्पश्चात लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म० प०

लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में हुई कार सेवा और उसके परिणामस्वरूप देश में हुई घटनाएं

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं जसवन्त सिंह जी के साथ आपसे मिला था और हमने अनुरोध किया था कि आप प्रतिपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्हें आज सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया है, सदन में लाने का प्रबन्ध करें। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप पहले प्रधान मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहें और फिर सभा की कार्यवाही शुरू करें। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने आज प्रश्नकाल स्थगित करने तथा स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : पूरा देश जल रहा है और वे दंगे भड़काने के लिए उत्तरदायी हैं और आप श्री वाजपेयी को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। (**व्यवधान**)

2.02 **म०प०**

इस समय श्री फूलचन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और फिर सभा पटल के निकट खड़े हो गए

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इस स्थिति में यह सदन कैसे चलेगा। क्या हो रहा है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.04 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 1992/8 अग्रहायण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : चौहान प्रिन्टिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53